

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 मार्च, 1985

खण्ड 1 अंक 10

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 21 मार्च, 1985

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(10)1
नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे हुए तारांकित प्र न का लिखित उत्तर	(10)24
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(10)34

राज्यपाल के संदेश	(10)36
वक्तव्य—	
लोक स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भिवानी तथा महेंद्रगढ़ जिलों में पेयजल की भारी कमी सम्बन्धी	(10)37
गैर सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा सम्बन्धी प्रक्रिया के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव उठाना	(10)41
अध्यक्ष द्वारा रूलिंग—	
एक प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा दिए गए भाषणों सम्बन्धी	(10)42
गैर सरकारी प्रस्ताव—	
एस0वाई0एल0 नहर के निर्माण सम्बन्धी (पुररारम्भ)	(10)42
कंसीडर	(10)42
गैर सरकारी प्रस्ताव (पुररारम्भ)	(10)44
अध्यक्ष द्वारा घोषणा—	
पंजाब यूनिवर्सिटी सेनिट के इलैक्ट्रिकल सम्बन्धी	(10)65
गैर सरकारी प्रस्ताव (पुररारम्भ)	(10)66

## हरियाणा विधान सभा

वीरवार 21 मार्च, 1985

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

### तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बज, अब सवाल होंगे।

#### **Use of Poisonous Gases/Chemicals by Industries**

**\*828. Shrimati Chandrawati:** Will the Minister for State for Labour and Employment be pleased to state-

(a) the districtwise number of Industries in the Private and Public Sectors in the State, if any, using poisonous gases/chemicals for the manufacture of insecticides/pesticides/medicines etc. and whether any such industries exists at Gurgaon and Charkhi Dadri;

(b) the names of chemicals/gases being used in the industries as referred to in part (a) above togetherwith-

(i) the names of chemicals/gases, if any, being imported;

(ii) the names of firms importing the said chemicals/gases;

(iii) the names of the countries from which being imported ; and

(iv) the names of the Indian or Foreign owners of the firms, who deal with the poisonous gases/chemicals as referred to in part(a) above;

(c) whether any precautionary measures are being taken by the owners of the said industries against health hazards; if so, details thereof; and

(d) whether any measures are being taken by the said industries for checking the creation of pollution; if so, details thereof togetherwith the manner in which the effluents (solid and liquid) are being disposed of?

श्रम तथा रोजगार राज्य मंत्री (श्री राजे 1 कुमार): उत्तर सदन के पटल पर रखा जाता है।

### उत्तर

(ए) हरियाणा राज्य में पेस्टीसाइडज/इनसैक्टीसाइडज बनाने के 12 कारखाने हैं जो जहरीले कैमिकल करते हैं इनमें से केवल दो कारखाने पब्लिक सैक्टर में हैं और बाकी के दस कारखाने प्राइवेट क्षेत्र में हैं। गुडगांव में पेस्टीसाइडज/इनपेस्टीसाइडज बनाने के दो कारखाने है जबकि चरखी दादरी में ऐसा कोई कारखाना नहीं है। इन कारखानों की जिलेवार संख्या निम्न प्रकार से है:-

क्र०	जिला का नाम	प्राइवेट	पब्लिक सेक्टर
------	-------------	----------	---------------

संख्या		कारखानों की संख्या	में कारखानों की संख्या
1	गुडगांव	2	—
2	फरीदाबाद	2	—
3	अम्बाला	2	—
4	कुरुक्षेत्र	—	1
5	करनाल	2	1
6	रोहतक	2	—
7	जींद	—	—
8	हिसार	—	—
9	सिरसा	—	—
10	भिवानी	—	—
11	सोनीपत	—	—
12	महेन्द्रगढ़	—	—

हरियाणा राज्य में दवाईयां बनाने वाले किसी कारखाने में दवाईयां बनाने के लिए जहरीली गैसों अथवा जहरीले कैमिकल्ज इस्तेमाल नहीं होते।

(बी) पेस्टीसाइडज/इनसैक्टीसाइडज बनाने वाले कारखानों में जो कैमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उनके नाम निम्न प्रकार से हैं:—

बी.एच.सी., एलडरिन, मैलोथि 1न, डी.डी.टी, इन्डोसलफान, डाईपैथोऐट, क्वीनलफोर्स, ए.एन.ए., मैनेकिरोटोफोर्स, कारबैरिल, डाइकलोरबोस, पेनथोऐट, मैथिल पैराथियान, क्लोपीरेफोर्स, बुटाकलोर, इथाइन, फनवलरेट, क्लोरडोन, कोपर—आक्सीकलोराइड, समेपरमैथरिन, 2—4 ऐथीलेस्टर, 2—4डी सेडियम साल्ट, एम.सी.पी.ए., अमीन साल्ट पेरोडोल, हैपलाकलोर, नोबीलीन, एम.इ.ऐ.सी., फोरेट, सलफर, फोसफामिडोल, मैनेकेजिव, डिकोफोल, कार्बन—डाजीन, जिनेव तथा फनीटरोथियान।

इस प्रश्न के भाग बी के पार्ट 1, 2, 3, 4 के संबंध में यह कहना है कि यह विषय भारत सरकार का है क्योंकि कई प्रकार के कैमिकल्ज तथा गैसों का जोकि कीटना एक पदार्थ बनाने के काम आती है उनके आयात की अनुमति भारत सरकार ही देती है।

(सी) हां कीटना एक पदार्थ बनाने वाले कारखानों को कारखाना अधिनियम 1948 इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए फ़ैक्टरीज रूलज तथा इनसैक्टीसाइड एक्ट 1968 तथा इनसैक्टीसाइडज रूलज 1971 के अधीन मानव सुरक्षा के उपाय करना जरूरी है। इन रूलज के अनुसार कारखानों में काम करने के लिए अच्छा वातावरण श्रमिकों के लिए बचाव उपकरण तथा कपडे प्रदान

करना, डाक्टरी सहायता का प्रबन्ध, पैस्टीसाइडज/इनसैक्टीसाइडज को ठीक ढंग से पैकिंग लैबलिंग स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्ट करने के तरीके अपनाने के लिए सावधानी का प्रावधान है।

हरियाणा राज्य में स्थित पैस्टीसाइडज/इनसैक्टीसाइडज बनाने वाला कोई भी कारखाना वातावरण को दूषित नहीं करता।

(डी) दवाइयां बनाने वाले निम्नलिखित तीन कारखाने दूषित पानी का निकास करते हैं—

1. मै० डाबर (डा० एस० के० बरमन) प्राइवेट लि० आयुर्वेदिक, फरीदाबाद।
2. मै० इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमैसीटीकल लि० गुडगांवा।
3. मै० सीफन लेब० प्राइवेट लि० कुन्डली, पानीपत।

कम संख्या एक तथा दो पर दिए गए कारखानों में निकलने वाले दूषित जल को साफ करने के यंत्र लगा रखे हैं कम संख्या तीन पर दिए गए कारखाने के विरुद्ध वाटर एण्ड ऐयर पोलूशन कन्ट्रोल बोर्ड, हरियाणा ने प्रबन्धकों के विरुद्ध उचित प्रबन्धन करने के लिए कानूनी कार्यवाही की हुई है। यद्यपि अब इस कारखाने के प्रबन्धकों ने सूचित किया है कि वह कारखाने से निकलने वाले दूषित जल को साफ करने के लिए प्रबन्ध कर रहे हैं।

राज्य में स्थित दवाइयां बनाने वाले अन्य कारखाने वातावरण को दूषित नहीं करते।

**श्रीमति चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, इसका जवाब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने देना था या लेबर मिनिस्टर ने देना था?

**श्री अध्यक्ष:** आपने सवाल लेबर मिनिस्टर से ही पूछ रखा है।

**श्रीमति चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, क्वै चन के पार्ट, ए के जवाब में इन्होंने पहले तो कहा है कि—

“There are 12 pesticides/insecticides manufacturing units in Haryana which are using poisonous chemicals.”

लेकिन आखिर में कहते हैं कि—

“None of the medicines manufacturing units in Haryana is using poisonous gases or chemicals.”

ये दोनो जवाब, स्पीकर साहब, कंट्राडिक्टरी है।

**Mr. Speaker:** He will explain.

**श्री राजे I कुमार:** स्पीकर साहब, पहला जवाब पैस्टिसाइडज और इनसेक्टीसाइडज मैनुफैक्चरिंग यूनिटस से सम्बन्ध रखता है और दूसरा उत्तर मैडिफाइनड मैनुफैक्चरिंग यूनिटस से सम्बन्धित है क्योंकि वे कोई जहरीली कैमिकल इस्तेमाल नहीं करते।

**श्रीमति चन्द्रावती:** \* \* \* \* \* स्पीकर साहब, मैंने यह पूछा था कि कौने से ऐसे कारखाने हैं जो जहरीली गैसों और कैमिकल्ज इस्तेमाल करते हैं। ( गोर)



**मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):** स्पीकर साहब, पहले ये इन लफजो को विदड़ा करें। इसका मतलब तो यह हुआ कि ये विधान सभा के सारे के सारे सैक्रेटारिएट को भाक की नजर से देखती है। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** मैडम, आपने 4-5 दफा पहले भी यह ऐलीगे उन लगाया है और 4-5 दफा ही आपने देखा कि कोई भाब्द इधर-उधर नहीं मिला बल्कि सह कुछ वैसे का वैसे निकला। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप सवाल पूछना चाहती है तो पूछिए।

**श्रीमति चन्द्रावती:** \* \* \* \* मुझे इस बात का क्या पता है?

**श्री अध्यक्ष:** मैडम, तीन दफा मैं खुद सवाल पढता हूं। एक तो एक जवाब आता है तब पढता हूं। फिर जब उसे लगाने लगते हैं तब पढता हूं और एक बार फाइनल स्टेज पर पढता हूं। इस क्वै चन को भी तीन दफा पढा है। अब आप कृप्या अपना सवाल पूछे।

**श्रीमति चन्द्रावती:** जनाब, फरीदाबाद में जो कारखाने हैं वे जब कैमिकल्ज इस्तेमाल करते हैं तो उससे पोल्यू उन होता है। उन्होंने कारखाने से निकलने वाले गन्दे पानी को साफ करने का कोई इन्तजाम नहीं कर रखा है। वे उसे उजीना ड्रेन में डाल देते हैं। उसकी वजह से वहां सारे के सारे खेत खराब हो गए है क्या सरकार इसका कोई इन्तजाम करेगी?

**श्री राजे 1 कुमार:** स्पीकर साहब, ऐफ्लुऐन्टस को ट्रीटमेंट करने के बाद ड्रेन्ज या नहरों आदि में डाला जाता है। जिन यूनिटस

में ट्रीटमेंट प्लान्टस आदि नहीं है उन्हें नोटिस दिए गए है। चालान किए गए है और उन्होंने जल्दी ही आव यक कार्यवाही करने का आ वासन दिया हुआ है।

**श्री मंगल सैन:** मोस्ट इंटेलिजेंट जी। (विघ्न) स्पीकर सर, इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि जितने भी कैमिकल्ज है। उनमें गवर्नमेंट आफ इंडिया डील करती है हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। स्पीकर साहब, ओवर इंटेलिजेंस के कारण कई बार मनुश्य अपने जाल में खुद फंस जाता है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि फर्मज को नोटिस दिए हैं और कुछेक फर्मज ने अ योरेंस दी है कि वे ऐफ्लुएन्टस को ट्रीट करने के लिए कदम उठायेंगे। मैं इनसे कैटेगरीकली यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंटस को क्या गाइड लाइन्ज दी हुई है। क्या उनको ओबजर्व किया गया है या नहीं किया गया है। साथ ही ये यह भी बताएं कि किन किन फर्मज को नोटिस दिये हुए हैं और उनके मालिक कौन हैं?

**श्री राजे । कुमार:** स्पीकर साहब, पहले तो इन्होंने भारत सरकार का जिक किया। इसके बारे में अर्ज यह है कि कैमिकल्ज की इम्पोर्ट और ऐक्सपोर्ट का मामला भारत सरकार का विशय है। जहां तक गाइड लाइन्ज की बात है जो निर्धारित की गई है उनकी पालना की जाती है।

**श्री मंगल सैन:** वे गाईड लाइन्ज क्या है?

**श्री राजे 1 कुमार:** अध्यक्ष महोदय, जहां जहरीली गैस प्रयोग होती है वहां ग्लोब्स और मास्कस जैसी चीजें होती हैं। (विधन) कैमिकल्ज के हिसाब से बचाव की अलग अलग चीजें होती हैं। स्पीकर साहब, समय समय पर फैक्टरीज इंस्पैक्टर और इनवायर्नमेंट इंस्पैक्टर इंडस्ट्रीज की चैकिंग करते रहते हैं। जहां किसी किस्म की अनियमितता मिलती है उसको नोटिस देते हैं और चालान कर देते हैं जहां तक इंडस्ट्रीज के मालिकों का सम्बन्ध है यह जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है क्योंकि यह बात इन्होंने प्र न में नहीं पूछी थी। अगर इसके लिए ये सैपरेट नोटिस देंगे तो यह बात भी इन्हें बता देंगे।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, मेरा सवाल बडा रैलेवैन्ट है। इन्होंने खुद कहा है कि कुछ फर्मज को नोटिस दिए गए हैं। इन्होंने नोटिस दिवारों को दिए हैं या फर्मज के मालिकों को दिए हैं? स्पीकर साहब, इन्हें तैयार होकर आना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** देख लीजिए, अगर आपके पास इन्फर्मे टान है तो जवाब दे दें।

**श्री राजे 1 कुमार:** फरीदाबाद की जिन 7 फैक्टरीज को नोटिस दिए हैं उनके नाम हैं मै0 सुपर कैमिकल्ज, मै0 अ गोक कैमिकल्ज, मै0 हिन्द पोलीमार, मै0 हरियाणा कैमिकल्ज, मै0 क्लोरो कैम, मै0 सुपर लूब और मै0 कैम प्लास्ट। स्पीकर साहब, इन

इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया है क्योंकि ये सरकार द्वारा निर्धारित भातों को पूरा नहीं कर पाई थी।

**श्री फतेह चन्द विज:** स्पीकर साहब, कुछ जगहों पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है। मिसाल के तौर पर आप पानीपत को ही ले लें। वहां लोगों ने 50-50 हजार या 1-1 लाख रूपया लगा कर कारखाने लगाए हुए हैं वे खुद ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा नहीं सकते। क्या ऐसी जगहों पर या इंडस्ट्रियल टाउन्ज में सरकार स्वयं ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाएगी ताकि गन्दा पानी ट्रीट हो जाए और बीमारियों को फैलने से रोका जा सके।

**श्री राजे । कुमार:** स्पीकर साहब, इस बारे में अनुसंधान चलते रहते हैं और ट्रीटमेंट के कई सस्ते तरीके भी निकल गए हैं। अगर कोई फ़ैक्टरी ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं लगा सके तो वह ट्रीटमेंट के किसी और सस्ते तरीके को इस्तेमाल कर सकती है। स्पीकर साहब, बेसिकली यह क्वै चन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का है लेबर डिपार्टमेंट का नहीं। अगर इस बारे में ये कोई ज्यादा जानकारी चाहते हों तो ये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं।

**चौधरी तैयब हुसैन:** स्पीकर साहब, फ़ैक्टरीज से जो ऐफ्लुएन्ट्स निकलते हैं उन्हें गुडगांव कैनल में डाल दिया जाता है और उससे किसानों की जमीन बरबाद हो गई है। क्या उसके लिए सरकार उन किसानों को कोई मुआवजा देगी और आगे के लिये कोई प्रबन्ध करेगी ताकि बाकी लोगों को नुकसान न हो?

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि बहुत सी फैक्टरीज से ऐसा गन्दा पानी निकलता है जिससे वायुमंडल खराब होता है और बीमारियों के फैलने का भय होता है। इसके लिए हमने वाटर एंड एयर पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया है और उसके जिम्मे यह काम लगाया है कि वह देखें कि फैक्टरीज से गन्दा पानी बाहर न जाए। बाकायदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहां लगना चाहिए। हमने सैंकड़ों फैक्टरीज को नोटिस दिए हुए हैं। बहुत से केसरजिस्टर किए हैं। बहुत से इंडस्ट्रियलिट्स ने अदालतों में स्टेटमेंट दी हुई है कि वे 6 महीने के अर्से में, 4 महीने के अर्से में या तीन महीने के अर्से में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि वायुमंडल खराब न हो और गन्दा पानी बाहर न जाए। जहां तक गुडगांव कैनल में गंदा पानी डालने की बात का ताल्लुक है अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि गुडगांव जिला में और फरीदाबाद में फैक्टरीज ज्यादा हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत गन्दा पानी जो इंसान की सेहत को नुकसान देता हो ऐसे ही नहर में फैंक दिया जाए।

आप जानते हैं कि पहले पानी टैस्ट होता है कि कितनी मिकदार का पानी होता चाहिए। उस मिकदार से ज्यादा का पानी किसी भी हालत में इंसान के पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस पानी में कोई ऐसी बात नहीं है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। जहां तक उस जमीन को खराब करने का सम्बन्ध है उस बारे में

हमारा भरसक कोटि है कि ऐसा पानी जो जमीन को खराब करता हो उसे रोका जाए।

**चौधरी तैयब हुसैन:** मैंने यह पूछा था कि जो जमीनें खराब हो गई हैं क्या उनका मुआवजा सरकार देगी?

**चौधरी भजन लाल:** मुआवजा देने का सवाल पैदा नहीं होता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सी जगह गन्दा पानी भी जाता होगा लेकिन भविष्य में हम इसका इंतजाम करने जा रहे हैं ताकि इस जमीन में गन्दा पानी न जायें।

**श्री ए0सी0 चौधरी:** स्पीकर साहब, इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट का जिक्र किया है। हरियाणा में ऐसे यूनिट भी हैं जिनका डिस्पोजल पब्लिक हेल्थ के लिए इनज्यूरियस है लेकिन उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अलाउ नहीं करती कि वे ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकें क्योंकि यह बहुत ही कोस्टली अफेयर्ज हैं। क्या सरकार ऐसा प्रावधान करके देगी कि उनके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगा दे और उसका मुआवजा या खर्चा उन से ले लें। ऐसा करने से गवर्नमेंट का परपज भी सर्व होगा और लोगों को भी कठिनाई नहीं होगी।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, जब कोई इन्डस्ट्री का लाइसेंस लेता है तो बाकायदा उसमें कंडीशन रखी जाती है कि इतने दिनों में गन्दे पानी का ट्रीटमेंट प्लांट का प्लांट लगाना पड़ेगा। बाकायदा एग्रीमेंट होता है। अगर कोई एग्रीमेंट की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करती है सरकार ऐसे प्लांट

लगा कर नहीं देती और न लगाएगी। सरकार की तरफ से बाकायदा आदे 1 है अगर कोई आदे 1ों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और आगे भी करेंगे।

**चौधरी नेकी राम:** स्पीकर साहब, सरकार की ओर से वायु प्रदूषण के लिए बन्दोबस्त होता है लेकिन इसके अलावा पेड पौधों से भी वायु प्रदूषण स्वच्छ होता है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस बारे में क्या कदम उठाये हैं और उठाये हैं तो ऐसे कौन से पौधे लगाये हैं जिससे लोगों के जीवन पर वायु प्रदूषण का असर न पड़े?

**चौधरी भजन लाल:** यह ठीक बात है पेड पौधों भी वायु मंडल को स्वच्छ बनाते हैं इसी बात को लेकर हरियाणा सरकार ने ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने भुरु कर दिये है पिछले सारे साल में दस करोड पौधे लगाये हैं सारे दे 1 में रिकार्ड कायम किया है।

**चौधरी नेकी राम:** मैंने आप से यह सवाल किया है कि किस तरह से पौधे लगाये हैं जो गैस को चूस लें वे पौधे लगाये हैं या दूसरे लगाये हैं?

(इस प्र 1न का उत्तर नहीं दिया गया)

**चौधरी फूल चन्द:** स्पीकर साहब, क्या सरकार के नोटिस में है कि अम्बाला जिले में हिमाचल और हरियाणा के बार्डर पर एक काला आम जगह है जहां पर कुछ फैक्टरियां ऐसे कैमिकल इस्तेमाल करती है जो मारकन्डा के पानी को गन्दा करता है यह पानी मेरे क्षेत्र

में आता है। इस पानी के पीने से कई पशु भी मरे हैं। क्या सरकार उन इन्डस्ट्रीज के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या कोई प्रबन्ध करने की ओर ध्यान देगी?

**श्री राजे ग. कुमार:** सरकार के नोटिस में नहीं आया है। माननीय सदस्य ने आज ही बताया है। इस बारे में फौरन जांच करके एक्शन लेंगे।

**चौधरी ओम प्रकाश:** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने पार्ट ए के जवाब में बताया है कि हरियाणा में कुल 12 फैक्टरीज हैं जो पैस्टीसाइडज और इनपैस्टीसाइडज बनाने में पाईजनैस कैमिकल इस्तेमाल करती हैं। इनमें से प्राइवेट सैक्टर में गुडगांवा में दो, फरीदाबाद में दो, करनाल और रोहतक में भी दो दो हैं और पब्लिक सैक्टर में कुरुक्षेत्र और करनाल में हैं। स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से इनकी लोकेशन के बारे में पूछना चाहता हूँ कि ये फैक्टरीज आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हैं या बाहर हैं और दूसरे इनके लिए सरकार ने क्या सैफटी मैयर्ज ले रखे हैं।

**श्री राजे ग. कुमार:** जब भी किसी फैक्टरी को लाइसेंस देते हैं तो आबादी से बाहर दिया जाता है लेकिन हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता फैक्टरीज आबादी के बीच में आ जाती है। इन में से कोई भी फैक्टरी ऐसी नहीं है जिसका ऐयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन बाहर रिलीज होता हो। किसी तरह का डेन्जरस कैमिकल बाहर नहीं जाता है।



**श्रीमति चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब के नालेज में है कि चरखी दादरी में फीकाडा रोड पर जो कैमिकल्ज की फ़ैक्टरी लगी हुई है उसके आस पास के एरिया की फसल कतई नहीं उगती है और अगर उगती है तो वह जल जाती है। क्या उस बारे में सरकार इन्कवायरी करवायेगी और उसका इन्तजाम करने के लिए क्या कदम उठायेगी?

**श्री राजे । कुमार:** चरखी दादरी की फ़ैक्टरी में आलरेडी नोटिस दिया हुआ है। दूसरे चरखी दादरी में पेस्टीसाइडज, इनसैक्टीसाइडज फ़ैक्टरी नहीं है वह फ़ैक्टरी क्लोरोनेड बनाती है जो कागज में काम आती है। उसमें बहुत कम कैमिकल क्लोरिन रिलीज होती है लेकिन फिर भी उन को भी नोटिस इ पु किया हुआ है।

#### **Persons living below Poverty Line**

**\*858. @Chaudhri Balvir Singh Grewal Chaudhri Kundan Lal:** Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) the number of persons living below poverty line in Haryana during the years 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 and 1984-85 to date; and

(b) the steps, if any taken by the Government to bring the people referred to in part (a) above, above the poverty line togetherwith the district wise data of the results achieved therefrom?

**वित्तमंत्री (श्री सागर राम गुप्ता):**

(ए) एवं (बी) विधान सभा के पटल पर सूचना रखी जाती है।

### सूचना

(ए) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण प्रोग्राम के अधीन जो उपभोक्ता परिव्यय सर्वेक्षण वर्ष 1978-79 में करवाया गया उसके अनुसार हरियाणा में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कुल आबादी का 36.6 प्रतिशत थी। यह सर्वेक्षण वर्ष 1983 में फिर से करवाया गया और इसके अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता घटकर 30.2 रह गई। वर्ष वार सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह सर्वेक्षण पांच वर्षों बाद दोहराया जाता है।

(बी) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के आर्थिक स्तर को उंचा उठाने के लिए सरकार ने कई स्कीमों/प्रोग्राम कार्यान्वित किये हैं। इन लोगों को पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी तथा सुअर पालन, मछली पालन, छोटे उद्योग, परिवहन आदि कार्य अपनाने के लिए अनुदान तथा ऋण के रूप में सहायता दी जा रही है। भिन्न प्रकार के धन्धे अपनाने के लिये प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण उपरान्त यह अपना कार्य आरम्भ कर सकें। जिन व्यक्तियों को वर्ष 1980 से लेकर 31.1.85 तक सहायता दी गई उनका जिलावार विवरण निम्नलिखित है।

द्रमांक	जिला	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्यां (1.4.80 से 21.1.85)
1	अम्बाला	53124
2	कुरुक्षेत्र	38970
3	करनाल	49047
4	सेनीपत	30099
5	फरीदाबाद	26590
6	गुडगांव	38327
7	महेन्द्रगढ	41013
8	भिवानी	33300
9	थहसार	64545
10	थसरसा	23315
11	श्रोहतक	48751
12	जींद	34853
	योग	481934

सहायता दिये जाने के जो परिणाम हुए उसकी सूचना उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है क्योंकि इतने अधिक लाभान्वित

व्यक्तियों से सूचना एकत्र करना एक बहुत बड़ा कार्य है जोकि ऐसी सूचना प्राप्त करने के लाभ के अनुरूप नहीं होगा। परन्तु भाग ए में जिस नमूना सर्वेक्षण का वर्णन किया गया है उसके अनुसार गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता जोकि 1978-79 में 36.6 थी 1983 में घट कर 30.2 रह गई।

**चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल:** स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके मुताबिक 1978-79 में 36.6 परसेन्ट बिलो पावर्टी लाईन पापुलेशन थी और सन 1983 के सर्वे के अनुसार 30.2 परसेन्ट इन्कम बढी है। इसी तरह से सन 1982-83 में 1126 रूपये थी तो सन 1983-84 में 1127 रूपये हुई यानि एक रूपया बढा है रीयल टर्म के अनुसार तो बहुत जबरदस्त बिलों पावर्टी होते है और इनकी फिगरज से भी साबित होता है। स्पीकर साहब, तीन सैक्टर होते हैं एक प्राइमरी सैक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आती है और सैकिण्डरी सैक्टर जिसमें इन्डस्ट्री आती है। एग्रीकल्चर सैक्टर में इन्कम लगातार घट रही है और दूसरों में बढ रही है। गांवों में पावर्टी ज्यादा है यानि बिलो पावर्टी लाईन लोग गांव में ज्यादा रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पावर्टी लाइन से उपर उठाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है।

**श्री सागर राम गुप्ता:** मेरे माननीय दोस्त को कनफयूजन है। दरअसल सवाह यह है कि कितनी फैमिलीज बिलो पावर्टी लाइन है। स्पीकर साहब, ऐसा है कि बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज इन्कम के आधार पर नहीं देखी जाती है बल्कि कन्जम्पशन के आधार पर

देखी जाती है। फ़ैमिली का स्टैन्डर्ड कन्जम्प 1न 2400 कैलेरिज है। जिन फ़ैमिलीज को 2400 कैलेरिज नहीं मिलता है उन्हें बिलों पावर्टी लाइन गिना जाता है और अगर उससे फालतू मिलता है तो अबव पावर्टी लाइन गिना जाता है। मेरे माननीय सदस्य इन्कम से रेलैवैन्ट कर रहे हैं। यह बात गलत है। उससे ताल्लुक नहीं है। बिलो पावर्टी लाइन फ़ैमिलीज की जांच का तरीका इन्कम नहीं है। अगर कोई आदमी खाना ना खाये यानि वह हजार कैलेरीज भी नहीं खाये तो हम क्या कर सकते हैं। कन्जम्प 1न के आधार पर फिगर्ज दी है।

**डा० भीम सिंह दहिया:** स्पीकर साहब, सवाल के ख भाग में यह पूछा है कि बिलो पावर्टी लाईन से उपर उठाने के लिए सरकार ने क्या स्टैप लिए है और डिस्ट्रिक्टवाइज क्या रिजल्टस है? जवाब मिला है कि डैटा कलैक्ट करने में जो मेहनत होगी उसका फायदा इतना नहीं होगा। मान लो कि इतना फायदा न होगा लेकिन सरकार की जो पोलिसी है क्या कोई महकमा जब अपनी स्कीम चलाता है तो यह पता चलाने की कोशिश नहीं करता कि वह स्कीम ठीक चली है या नहीं उसे चालू रखना चाहिए या नहीं? यह फ़ैसला तो तभी कर पायेंगे जब साल में यह पता लगे कि कामयाब हुई या नहीं और उसके क्या रिजल्ट हुए।

**श्री सागर राम गुप्ता:** स्पीकर साहब, बात यह है कि बहुत सी ऐसी स्कीमें सरकार चला रही है जिनसे हम उन लोगों को जो बिलो पावर्टी लाईन है। या जो मार्जीनल साईड पर हैं उनको हम उपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा इन्टेग्रेडिड रूरल

डिवैल्पमेंट प्रोग्राम है एनीमल हस्बैंडरी का प्रोग्राम है डेरी डिवैल्पमेंट का प्रोग्राम है फि ारीज का प्रोग्राम है और हरिजन कल्याण निगम का प्रोग्राम है। यह सारी एक्टिविटीज ऐसी है जिनके द्वारा उपर उठाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं अब मैं आपकी यह तो बता संकूगा कि हमने हर जिले में कितनी कितनी फ़ैमिलीज को अस्सिट किया लेकिन चूंकि आज तक इस किस्म का कोई सर्वे नहीं किया गया है कि इन स्टैप्स के द्वारा कितनी फ़ैमिलीज वास्तव तौर पर बिलो पावर्टी लाइन से उपर उठकर आ गई है इसलिए मैं यह फिगर्ज जिलावार आपको नहीं दे संकूगा। अगर आप पूछना चाहोगें कि इन सारी स्कीमों के द्वारा हमने कितनी फ़ैमिलीज को अस्सिट किया है तो वह मैं दे दूंगा।

**चौधरी कुन्दन लाल:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने गरीब लोगों को बिलो पावर्टी लाइन से उपर उठाने की योजना बनाई है उसमें साल के अन्दर कितना कोटा निर्धारित किया है या करने जा रहे हैं।

**श्री सागर राम गुप्ता:** स्पीकर साहब, ऐसा है कि इस बात को कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है कि सौ फ़ैमिलीज या दो सौ फ़ैमिलीज उपर उठानी है लेकिन जितने लोगों को बिलो पावर्टी लाइन से उपर उठाने के लिये स्कीमें इनफोर्स की है उनके लिए हम हर साल के बजट में रकम जरूर मुकर्रर करते हैं कि इतना रकम इस साल में खर्च की जानी है। जैसे आरडी में कितना, फि ारीज में

कितना और हरिजन कल्याण निगम के थ्रू कितना पैसा खर्च किया जाना है।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ग्रेवाल साहब के सप्लीमेंटरी के जवाब में यह बताया है कि ग्रेवाल साहब को कुछ कन्फ्यूजन है कि बिलो पावर्टी लाइन रहने वाले लोगों को इन्कम के आधार पर नहीं लेते बल्कि कैलेरिज कितनी वह कन्ज्यूम करते हैं उसके आधार पर बिलो पावर्टी लाईन रहने वाले लोगों को गिना जाता है। ऐसा मिनिस्टर साहब ने बताया है। जैसे कि इन्होंने बिलो पावर्टी लाइन रहने वाले लोगों को देखने का काइटेरिया बताया है और यह हम भी मानते हैं कि जो इन्होंने 'बी' भाग के जवाब में कहा है कि गवर्नमेंट बहुत सी स्कीमें उन लोगों को उपर उठाने के लिए इम्प्लीमेंट कर रही है। इन्होंने उन सारी स्कीमों के नाम भी दिये हैं जैसे डेरी डिवैल्पमेंट, पोल्टरी, पिगरी, भीप एण्ड गोट रियरिंग, फि एरीज एटसैट्रा। क्या यह कन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है कि जो स्कीमें गवर्नमेंट चला रही है उन लोगों को उपर उठाने के लिए वह जो ऐसी है कि गरीब से गरीब लोगों की इन्कम के हिसाब से बनायी हुई है। जो वीकैस्ट पर्सन्ज इन दी सोसाइटी हैं उनको उपर उठाने के लिये वह स्कीमें चलायी जा रही है और बिलो पावर्टी लाईन की डैफीनी उन अलग से दी जा रही है जिनमें आधार कैलेरीज बताया जा रहा है। चौधरी नेकी राम जी की कैलेरीज तो डाक्टर ने बन्द कर दी होगी या बड़े बड़े रईस लोगों की खुराक डाक्टरज कई बार बन्द कर देते हैं। (व्यवधान एवं भाोर) डाक्टर लोग

इनकी खुराक इसलिये बन्द करते हैं क्योंकि ये लोग उतनी मेहनत नहीं करते जितनी इनको करनी चाहिये। अब बहुत सारे मिनिस्टर साहेबान भी दवा के सहारे ही जी रहे हैं। उनका खाना पीना भी सब कुछ बन्द कर रखा है। मंत्री जी से प्रार्थना है कि जरा इस बात को कैलेरिफाई करें कि कंट्राडिक्टिव इन क्यों है?

**श्री सागर राम गुप्ता:** स्पीकर सर, कोई कंट्राडिक्टिव इन का क्वै चन एराईज नहीं होता। सवाल यह है कि गवर्नमेंट यह मानकर चलती है कि कुछ लोग बिलो पावर्टी लाईन हरियाणा में रहते हैं। जैसे 1983 के सर्वे में बताया है कि 30.2 परसेंट फ़ैमिलीज ऐसी है। मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी की इनफ़ॉर्मेशन के लिये यह अर्ज कर दूँ कि यह सर्वे नैशनल लैवल पर यूनियन गवर्नमेंट हर 5 साल के बाद करवाती है यह सर्वे सैम्पलज के उपर आधारित होता है। कोई सारी आबादी का सर्वे नहीं किया जाता। पहले यह सर्वे 1978 में हुआ था फिर 1983 में सर्वे हुआ है। उससे यह पता चलता है कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो बिलो पावर्टी लाईन रह रहे हैं। उनमें बच्चे भी आ जाते हैं आदमी भी आ जाते हैं वीमैन भी आ जाती है। अब सवाल यह है कि उन बिलो पावर्टी लाईन रहने वाली फ़ैमिलीज की उपर उठाने का क्या तरीका है? एक तो आम बात यह है कि जो लोग कम खाते हैं या कम खा सकते हैं उनके पास पैसा नहीं होता। दूसरे जिनके पास पैसा होता है वे तो 2100 या 2400 कैलेरीज तक खाने की कोशिश करेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है हम उनको यह समझते हैं कि उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास पूरे साधन नहीं



है कि वे लोग ज्यादा कमा सकें और पूरी कैलेरीज खा सकें। हमारी कोर्नर स्ट्रेटज यह हो रही है कि उन फैमिलीज को बिलो पावर्टी लाईन से उपर ला सकें लेकिन सवाल यह है कि कितनी फैमिलीज बिलो पावर्टी लाईन है जिनकी परसैटज हमारे पास है। सरकार पूरा ध्यान इस बात की ओर सारे तरीकों द्वारा दे रही है और उन फैमिलीज को उपर उठाने की कोर्नर स्ट्रेटज कर रही है।

**श्री निहाल सिंह:** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि नैशनल सैम्पल सर्वे प्रोग्राम गवर्नमेंट आफ इंडिया चलाती है और उसके तहत सर्वे करवाने से सरकार को यह पता चलता है कि कितने लोग बिलो पावर्टी लाईन है। यह इनकम के हिसाब से चलता है न कि कैलेरीज के हिसाब से। इनकम के आधार पर ही सर्वे रिपोर्ट आयी होगी। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कैलेरीज कितनी कोई खाता है यह काइटेरिया जांच का नहीं है। इसके अलावा दूसरे काइटेरियाज भी हैं जैसे उसके पास पहनने के लिए कपडा या रहने और सिर छिपाने के लिए कोई झोपडी है या मकान है मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि इन चीजों को बिला पावर्टी लाईन जज करने के लिए गिना जाता है या नहीं?

**श्री सागर राम गुप्ता:** स्पीकर सर, राव साहब का यह समझना ठीक नहीं है कि सर्वे जो किया जाता है वह इनकम के आधार पर किया जाता है। मैं फिर अपनी बात को एम्फेसाइज करता हूँ कि जो सर्वे होता है उसमें यह देखा जाता है कि कितने लोग उसमें औरतें, आदमी और बच्चे सभी भामिल है निर्धारित कैलेरीज

का खाना नहीं खा पाते, कपडा नहीं पहन पाते या दूसरी जरूरियातें जिन्दगी उनको पूरी नहीं मिल पाती। इस किस्म का सर्वे ने इनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजे इन करती है जोकि गवर्नमेंट आफ इंडिया के अन्डर है। (व्यवधान व भाोर).....

**एक आवाज:** स्पीकर साहब, यह कपडा कैलेरीज में कहाँ से आ गया।

**श्री सागर राम गुप्ता:** मिनिमम स्टैंडर्ड कपडा पहनने का भी तो है कि 72 मीटर कपडा एक आदमी को एक साल में चाहिये। (व्यवधान व भाोर).....

**मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):** स्पीकर साहब, बात यह है कि इसमें थोडा समझ का फर्क है और थोडा कहने का फर्क है। जो कुछ कहा गया है उसका कहने का मकसद यह है कि कितने लोगों को दोनों टाईम खाने को मिल जाता है और कितने लोगों को नहीं मिलता। कैलेरीज का मामला टेढा है सवाल सिर्फ इतना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको पेट भर खाना नहीं मिलता। दूसरा सवाल यह है कि कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं और उनको उपर उठाने के लिए सरकार ने क्या तरीका अपनाया है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर ब्लॉक में छह सौ परिवारों को एक महीने में साधन देकर उंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह से एक साल में 70-72 हजार परिवारों को साधन जुटाकर गरीबी की रेखा से उपर उठाते हैं। इन लोगों के लिए अलग से

स्कीम्ज है। स्पीकर साहब, सरकार पूरी कोशिश करती है कि गरीब लोगों को पूरे साधन दिये जाएं और उनकी हालत को सुधारने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की कोशिश करती है।

### **Generation of Electricity by Thermal Plants**

**\*913. Chaudhri Kundan Lal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the thermal plants at Panipat and Faridabad are generating electricity according to their installed capacity; and

(b) if not, the steps, if any, taken or proposed to be taken to make the said plants generate electricity according to their installed capacity?

**Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsheer Singh Surjewala):**

(a) and (b) A statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

(a) The Panipat Thermal Power Project has been generating less since April 1984 to mid October 1984 as one number 110 MW of this unit in mid October 1984 the generation at Panipat Thermal Station has improved substantially. The average plant load factor from this station from October 1984 to February 1985 comes to 52.8% which is as per schedule fixed by Central Electricity Authority.

At Faridabad the generation is less on account of equipment constraint such as provision of obsolete hammer mills

and inadequate capacity of the coal handling plant. In the hammer mills, the hammers are required to be replaced after 100 hrs.

### **1. Faridabad Thermal Power Station:-**

(i) The work of augmenting the capacity of coal handling plant is in progress.

(ii) The 13<sup>th</sup> Stage has been rebladed in respect of 60 MW Unit-I.

(iii) The platen super heater tube of 60 MW unit-I & II have since been replaced by stainless steel tubes.

(iv) For smooth flow of coal in mills the modification of RC bunker in one of the 60 MW units has been done.

### **II. Panipat Thermal Power Station:-**

(i) The coal bunkers have been modified with the result that coal flow problems has been solved.

(ii) A new grizzly is being fitted on the wagon Tripple hopper to as to facilitate the removal of lumps of bigger sizes.

(iii) A manual unloading hopper is under construction which will facilitate the supply of coal to conveyors IA & IB.

In addition to the above, a detailed exercise has been carried out in both the thermal power plants with the assistance of engineers from M/s Bharat Heavy Electricals Limited, Central Electricity Authority and I & L Kota and various constraints in the equipment have been identified for which renovation schemes have been prepared. The working group of the Planning and

Commission has approved the same for Panipat Thermal Power Station and Faridabad Thermal Power Station amounting to Rs. 1606 lacs and Rs. 3851 lacs respectively. Necessary action on the various items includedd in the renovation programme has been already been initiated.

**चौधरी कुन्दन लाल:** अध्यक्ष महोदय, जिस समय ये यूनिटस लगाये गये, वे खराब यूनिटस लगाये गये। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन आफिसर्ज ने काम पूरा नहीं किया क्या उन आफिसर्ज के खिलाफ इंकवायरी कराई जाएगी? स्पीकर साहब, मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस समय इन यूनिटस में कुछ ऐसे आइटम्ज लगाये जा रहे हैं जो उसी टाइम लगने चाहिए थे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वे आइटम्ज उस वक्त क्यों नहीं लगाये गये और इसमें किसकी गलती थी?

**चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, पानीपत में 110-110 मैगावाट के दो यूनिट हैं उनमें से एक यूनिट 1-11-79 को कमि न हुआ और दूसरा यूनिट 27-3-80 को कमि न हुआ। फरीदाबाद के चार यूनिट हैं एक यूनिट 15 मैगावाट का फरवरी 1964 को कमि न हुआ और दूसरे तीन यूनिट साठ साठ मैगावाट के हैं। इनमें से एक यूनिट नम्बर 1974 को नम्बर दो यूनिट मार्च 1976 में और नम्बर तीन यूनिट अप्रैल 1981 को चालू हुआ कमि न हुआ। स्पीकर साहब, इनकी जो मीनरी है उसमें ऐसा नहीं है कि किसी यूनिट की टोटल मीनरी खराब हो। फरीदाबाद थर्मल प्लांट की हैमर मिल्लज औवसोलीट है और उसकी रैनोवे न के लिए गवर्नमेंट

आफ इंडिया ने पचास परसेन्ट रूपया दिया है और हरियाणा बिजली बोर्ड पचास परसेन्ट पैसा खर्च करेगा। यह मीनरी बीएचइएल सप्लाई करता है जो कि भारत सरकार की पब्लिक अन्डरटेकिंग है और उसमें किसी अफसर के खिलाफ इन्क्वायरी का सवाल पैदा नहीं होता।

**श्री भले राम:** मंत्री महोदय ने पानीपत और फरीदाबाद के प्लांट्स की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बताई है लेकिन वे पूरी कैपेसिटी पर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनको और ज्यादा तेज करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

**चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब, आम धारणा यह है कि कोई थर्मल प्लांट जितनी कैपेसिटी का है उसकी उतनी बिजली पैदा करनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए तकरीबन सब लोगों के पास फियेट और अम्बेस्डर कार है। उसमें 160 कि०मी० की स्पीड लिखी होती है लेकिन क्या किसी ने 110 कि०मी० से ज्यादा स्पीड पर कभी कार को चलाया है। एक थर्मल यूनिट 55 परसेन्ट प्लांट लोड फैक्टर पर चलने के लिए होता है। इसीलिए पानीपत के यूनिट का 55-60 प्लांट लोड फैक्टर है। फरीदाबाद प्लांट अन्डर कैपेसिटी जरूर है लेकिन तीन चार कारण हैं एक कारण तो यह है कि हैमर मिल्ट्रि औबसोलीट है और उनकी रैनोवेगेशन करने पर बाईस चौबीस करोड़ रूपया खर्च होगा। दूसरा

कारण यह है कि कोल हैंडलिंग प्लांट की कैपेसिटी कम है। रैनोवे इन के प्रोग्राम में इसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।

**श्रीमति चन्द्रावती:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पानीपत का जो सैंकण्ड फेज है वह पूरी तरह से ठीक काम कर रहा है।

**चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब, यह सवाल सैंकिंड स्टेज की कंस्ट्रक् इन के बारे में नहीं है। सैंकिण्ड स्टेज का तीसरा यूनिट नवम्बर दिसम्बर में इसी साल पूरा होने की उम्मीद है और सैंकिंड स्टेज का चौथा यूनिट अगले साल मई जून में पूरा होने की उम्मीद है।

**चौधरी तययब हुसैन:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये थर्मल प्लांट कहीं इस कारण से तो पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रहे हैं कि जो कोयला थर्मल प्लांट्स के लिए आता है वह तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को चला जाता है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज का खराब कोयला थर्मल प्लांट्स को चला जाता है और इससे प्लांट्स खराब हो जाते हैं।

**चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब, ये बहुत सीनीयर मैम्बर है और लोकसभा के भी मैम्बर है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हम कोई प्राइवेट कम्पनी से कोयला नहीं खरीदते हैं हम कोल इंडिया लि० से सीधा कोयला मांगते हैं रेलवे वैगन सीधा

आकर अनलोड होता है। इंडस्ट्री को कोयला चले जाने वाली बात बिल्कुल इमैजनरी है।

**चौधरी तययब हुसैन:** स्पीकर साहब, यह बिल्कुल ठीक बात है कि प्राइवेट इंडस्ट्री का खराब कोयला थर्मल प्लांट में आता है और थर्मल प्लांट का कोयला प्राइवेट कंपनी को चला जाता है।

**श्री अध्यक्ष:** कोलरी से सीधा कोयला जाता है प्राइवेट इंडस्ट्री को वह कोयला पहुंचने की बात ठीक नहीं है।

**चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब, बात कहने का फर्क है। एक दफा डाइवर्टिड रैंक थर्मल प्लांट में आ गया। हमारे यहां कोल हैंडलिंग वैगन टिपलर है जो कोल को एकदम उल्ट देता है। लेकिन उस दफा डाइवर्टिड क्लोज्ड वैगन आ गया और उसको वह टिपलर खाली नहीं कर सकता। हमको मैनुअल हैंडलिंग से कोयला उतारना पडा। हमने रेलवे वालों से प्रोटैस्ट किया। किसी इंडस्ट्री का नहीं था। वह तो डाइवर्टिड वैगन वहां आ गया था और उसको मैनुअल हैंडलिंग से अनलोड करना पडा। कोयला खराब नहीं था वह डाइवर्टिड वैगन था जो हमारे यहां आ गया था।

**श्रीमति चन्द्रावती:** इस पर ए0जी0 ने भी ओबजेक्शन किया है।

**श्रीमति भारदा रानी:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जहां से कोयला आता है वह घटिया



किस्म का कोयला होता है क्योंकि वहां पर हमारा इंट्रैस्ट वाच करने वाला कोई नहीं होता?

**चौधरी भामेरा सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब पार्टली यह बात ठीक है पानीपत और खासतौर पर फरीदाबाद के लिए जिस ऐं कन्टैन्ट का कोल इंडिया वालों से टाइअप हुआ था उसके मुताबिक कोयला नहीं आ रहा है। पानीपत में जो थर्मल प्लांट है वहां ओवर साइज का कोल आ गया जिसकी वजह से कोल हैंडलिंग प्लांट की जाली टूट गई। मैंने स्वयं मौके पर जाकर आप्रें इन को देखा है इससे हमारा स्टेट ब्वायलर भी खराब हो गया। हमने कोल इंडिया से प्रोटैस्ट किया और बदले में कम्पनसेट करने के लिए कहा। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई। कोल इंडिया वालों के साथ भी हमारे अफसरों की मीटिंग हुई और इसी वजह से पिछले दिनों कोयले की क्वालिटी में सुधार हुआ है। पहले खराब कोयला आता था और अब काफी सुधार है लेकिन कोल की क्वालिटी अप-टू-स्टैंडर्ड नहीं है।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन्होंने थर्मल प्लांट्स की सरप्राइज चैकिंग करते वक्त किसी इंजीनियर और आफिसर को सस्पेंड किया है? अगर किया है तो क्यों किया है क्या उनके काम में कोई कमी पाई गयी थी।

**मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):** स्पीकर साहब, इन्होंने सीधा ही मेरे से यह सवाल पूछ लिया इसलिए मैं बता देता हूं। यह

ठीक बात है कि मैंने और चौधरी भाम और सिंह सुरजेवाला जी ने मिल कर पानीपत और फरीदाबाद दोनों प्लांटस को चैक किया था क्योंकि बिजली की सप्लाई में कुछ कमी होने के कारण लोगों की काफी शिकायतें थी कि इन प्लांटस को जितनी बिजली पैदा करनी चाहिए थी उतनी ये प्लांटस पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हमने वहां जाकर एक एक बात को देखा। वहां पर आफिसर्स और इंजीनियर्स ने अपनी अपनी समस्याएं भी हमारे सामने रखी और उन्होंने यह भी बताया कि कोयला अच्छी क्वालिटी का न होने की वजह से ऐसा हो रहा है। कोयला ठीक नहीं आता उसमें ढेले आ जाते हैं जिसके कारण हमारे प्लांटस की परफॉरमेंस पूरी नहीं निकलती और वह कोयला छलनी को भी तोड़ देता है। इन सारी बातों पर विचार करने के बाद हमने यह मामला भारत सरकार के साथ टेकअप किया और इसके बाद भारत सरकार ने भी काफी सुधार किया है और इंजीनियर्स और आफिसर्स ने भी काफी लगन के साथ काम करने की कोशिश की है। डा० साहब की जानकारी के लिए मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि किसी भी अफसर को हमने संस्पेंड नहीं किया और न ही किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही ही की है बल्कि हमने उनको यह कहा कि आप सब को मिल कर अपने फर्ज को निभाना चाहिए और अपनी ड्यूटी में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं आनी चाहिए। अगर डाक्टरज और इंजीनियर्स की हडताल कर देंगे तो देश का क्या बनेगा। अपनी ड्यूटी को उन्हें अच्छी तरह से निभाना चाहिए और आप सब को एक होकर ईमानदारी से काम करना चाहिए ताकि

लोगों को और गरीब किसानों को ज्यादा से ज्यादा और ठीक समय पर बिजली मिल सके।

**श्री मनफूल सिंह:** स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से दो बातें पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि पानीपत के जो दो 110-110 मैगावाट के यूनिट्स चले हैं। वे कितनी कितनी देर चले हैं कितने दिन चले हैं और उन्होंने कितनी कितनी बिजली पैदा की है? दूसरी बात यह है कि जो थर्मल प्लांट्स ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं क्या उनका कारण यह तो नहीं था कि आपरेटर्ज की जगह असिस्टैन्ट आपरेटर्ज अप्वायंट कर रखे थे और वे इस काम को चला रहे थे और उनको तनख्वाह भी असिस्टैन्ट आपरेटर्ज की ही दी जाती थी? इस बारे में वे लोग मंत्री महोदय जी को भी मिले थे कि उनकी आधी तनख्वाह पर काम करना पड़ रहा है।

**चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सप्लीमेंटरी पूछी है उस बारे में दूसरे कई माननीय सदस्य भी सूचना प्राप्त करने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि फरीदाबाद और पानीपत के जो थर्मल प्लांट्स हैं वे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं और यह जनरल इम्प्रे ान है कि वे अन्डर कपैसिटी हैं। पिछले सालों की जो ग्रोस जनरे ान फरीदाबाद और पानीपत की हुई है उस बारे में तफसील के साथ बता देता हूँ। वह इस प्रकार है— अक्टूबर 1983-84 में टोटल जो ग्रोस जनरे ान थी वह 730 लाख यूनिट, 1984-85 में 1140 लाख यूनिट्स, नवम्बर 1983-84 में 650 लाख यूनिट्स, 1984-85 में 1300 लाख यूनिट्स, दिसम्बर 1983-84

में 760 लाख यूनिटस, 1984-85 में 1220 लाख यूनिटस जनवरी 1983-84 में 910 लाख यूनिटस इस साल 1984-85 जनवरी में 1290 लाख यूनिटस और पिछले साल 1310 के मुकाबले में 1351 लाख यूनिटस। टोटल 4360 के मुकाबले 6301 लाख यूनिटस जनरे न रही है। इन महीनों की एवरेज डेली अवेलेबिलिटी 29 लाख यूनिटस थी और इस साल 42 लाख यूनिटस रोज की रही है। पिछले सालों में मुकाबले में 13 लाख यूनिटस रोज पैदावार होती रही है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि आपरेटर के स्थान पर उनको असिस्टेंट आपरेटर की तनखाह देते रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले निदो बोर्ड ने स्टाफिंग पैटर्न की जो पोलिसी थी उसके बारे में फैसला लिया है जो थर्मल एक्पर्टस थे उनको थर्मल में ही लगाया जाएगा और दूसरी पालिसी भी एक्टिवली अन्डर कंसिड्रेशन है ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी हायर ग्रेड के आपरेटर को लोअर ग्रेड दिया गया हो।

**श्री अमीर चन्द मक्कड:** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि थर्मल प्लांटस में जो कोयला बाहर से जाता है उसको तोलने का कोई प्रबन्ध है?

**चौधरी भाम सिंह सुरजेवाला:** जी हां, हमारे पास वेईंग मीनिज है। कोयला तोलने का पूरा प्रबन्ध है। इस पर पूरा प्रोवीजन हमने कर रखा है।

**चौधरी फूलचन्द:** अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री महोदय ने बताया थर्मल प्लांट्स के काम में आगे से काफी सुधार लाया जा रहा है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से और कितने ऐसे थर्मल प्लांट्स या जनरेटिंग सिस्टम चालू किए जा रहे हैं जिनसे बिजली की मांग को पूरा किया जा सके, क्योंकि बिजली की खपत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।

**चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब, पानीपत थर्मल प्लांट के 110-110 मैगावाट के दो यूनिट स्टेज दो में 1985-86 में चालू हो जाएंगे। स्टेज तीन में 220 मैगावाट के एक यूनिट पर काम चल रहा है यमुना हाईडल में 8-8 मैगावाट के दो स्टेज इन अन्डर कंसट्रक्शन हैं। यमुना थर्मल प्लांट जिसकी सवा 400 मैगावाट की कैपेसिटी है पर भी काम शुरू हो चुका है।

### **Sick colleges in the State**

**\*923. Chaudhri Om Parkash:** Will the Minister of State of Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to close down the Sick Colleges in the State, if so, the criteria, if any, prescribed for declaring a college as sick?

**शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):** नहीं।

**चौधरी ओम प्रकाश:** अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि राज्य में सिक कालेजिज को बन्द करने

का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कि किसी कालेज को बन्द किया जाए यह अच्छी बात है लेकिन मैंने अपने सवाल के दूसरे पार्ट में यह पूछा था कि किसी कालेज को सिक घोषित करे के लिए कोई नामर्ज सरकार द्वारा निर्धारित किये गये है। कोई इसके लिए काइटेरिया फिक्स किया गया है या नहीं। इस बात को जरा क्लीयर कर दें क्या प्राइवेट और सरकारी कोलजों का अलग नामर्ज और काइटेरिया दिया है।

**श्री जगदी 1 नेहरा:** अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई काइटेरिया नहीं है किसी कालेज को बन्द किया जाए। ऐसा है कि एक प्राइवेट कालेज है और एक गवर्नमेंट कालेज है। प्राइवेट कालेजिज में जहां मैनेजमेंट का कोई झगडा है तनख्वाहें वगैरह समय पर नहीं दी जाती है या मैनेजमेंट का प्रिंसिपल या लैक्चरर्ज से कोई झगडा है उस कालेज को सरकार टेक ओवर कर लेती है और जो गवर्नमेंट कालेजिज है वह सिक कालेज हो ही नहीं सकता करीब करीब सारे कालेज ठीक है। अध्यक्ष महोदय, जो कालेजिज वायेबल नहीं है उसको भायद ये सिक कालेज कहते होंगे। जिस कालेज में बच्चों की स्ट्रैन्थ कम हो और स्टाफ पूरा लगा हुआ हो, वहां पर सरकार को खर्चा पडता था। इसकी हमने असैसमेंट भी की थी जैसे नारनौल में 2500 बच्चों हैं और वहां पर एक बच्चे के उपर सारे साल का साढे चार सौ रूपया खर्चा होता है। जहां थोडे बच्चे हैं स्टाफ पूरा होता है वहा पर 3300 रूपये साल में एक बच्चे के उपर खर्च आता है लेकिन इस कालेजिज को भी बन्द करने का कोई विचार नहीं है

आगे भी 10-12 सिस्टम आने की वजह से इस तरह के जो कालेज अनवायेबल थे वे ठीक हो जाएंगे।

**श्री फतेह चन्द विज:** स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा महोदय से यह पूछना चाहते हैं कि सरकार ने 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितने कालेजिज टेक-ओवर किये हैं?

**श्री जगदी ा नेहरा:** स्पीकर साहब, मैं सारा सूचना एक साथ ही दे देता हूँ। सब से पहले नै इनल कालेज सिरसा 21-1-1979 को, नरवाना को 1-8-79 को एसडी कालेज गुडगांव 14-1-1979 को जनता कालेज बावल 14-1-1980 को आदे ा कालेज सफीदों 14-1-1980 को, ने इनल कालेज टोहाना 14-1-1980 को जीबी कालेज नाहड 15-2-1980 को मेवात दुब्बलनधन 14-1-1980 को नेहरू मैमोरियल कालेज हांसी 20-2-1980 को व हेलीमण्डी कालेज 30-4-1980 को टेकओवर किये थे। इसी प्रकार बीबीआर कालेज सिंगरौली को 2/81 में टेकओवर किया। हरियाणा बार हीरो मैमोरियल कालेज 12-2-1981 को धरौंडा कालेज में 5-8-1981 को बेरी कालेज 14-6-1982 को और सीआर कालेज जींद को अप्रैल 1982 में टेक ओवर किया। इस तरह से ये कालेज टेक ओवर किए गए।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उनके पास इस प्रकार के भी मांग

पत्र आए है जिनमें सरकार से कालेज टेकओवर करने की मांग की हो। अगर हां, तो कौन कौन से कालेजों के विषय में मांग की गई?

**श्री जगदी । नेहरा:** अध्यक्ष महोदय, मांग तो ऐसी कोई नहीं आई लेकिन जो मैनेजमेंट ठीक न हो उनके कालेजों को टेकओवर कर लिया जाता है जैसे किसी ने टीचरों को तनखाह न दी हो या कोई और झगडा हो ऐसे दो तीन कालेजों को हमने टेकओवर किया है।

**श्री खिल्लन सिंह:** स्पीकर साहब, सरकार ने 1980 में जो कालेज टेकओवर किये थे उनमें यूज मंडल कालेज होडल भी है। सरकार ने उसके स्टाफ को भी ले लिया और जो उसकी सम्पत्ति और भवन था उसको भी ले लिया। लेकिन टीचरों को जो डेढ दो साल की तनखाह थी वह उनको नहीं दी गई। इसके अलावा उस कालेज को जो ग्रांट देनी थी वह भी रोक ली गई। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उनकी ग्रांट रिलीज की जाएगी ताकि टीचरों को पिछली तनखाह मिल सके?

**श्री जगदी । नेहरा:** अध्यक्ष महोदय, तनखाह वगैरह के झगडे की वजह से ही उस कालेज को टेकओवर किया गया था हमने पिछले चार पांच सालों में 17 कालेज टेकओवर किए थे। इन सब में तनखाह के बारे में झगडा था। जितने भी उसके असैटस और लाएबिलिटीज थी वे हमने अपने उपर ली। इस समय कुल 34 सरकारी कालेज हैं जिसमें से 17 इन्हीं तीन सालों में टेकओवर किए



हैं ताकि कालेज लैक्चररज को तनखाह ठीक ढंग से मिल सके। आगे के लिए अगर किसी कालेज में ऐसा झगडा होगा तो उसको भी हम टेकओवर करेंगे।

**Complaint against officers of Gurgaon and Mahendergarh  
Districts**

**\*919. Shri Ram Bilas Sharma:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state whether any complaint against any officers of Gurgaon and Mahendergarh districts was received by the Government during December, 1984 elections; if so, the action if any, taken thereon?

**Development Minister (Chaudhri Rajinder Singh):**  
Sir, nine complaints from individuals against the officers of Gurgaon and Mahendergarh districts have been received in the elections department of the state Government. One complaint received from Shri Bashir Ahemed, General Secretary, CPI has been found baseless. Another report received from the complainant was found to be baseless as per reports received from the Commissioner, Ambala Division and Chief Secretary Haryana. Reports on the remaining complaints have been asked for from the concerned quarters.

**श्री राम बिलास भार्मा:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा है कि 8 रिक्वायर्मेंटें जो मिली हैं उनके बारे में ये पूछताछ कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ कि यह पूछताछ कब तक कर लेंगे और कसूरवार के खिलाफ कब तक कार्यवाही करेंगे?

**चौधरी राजेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, इन्क्वायरी चल रही है और इसमें कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हम को ि ा कर रहे हैं कि इन्क्वायरी रिपोर्ट जल्दी आ जाए।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, लायक वजीर साहब ने फरमाया कि कंसर्ड क्वार्टर्ज को ि ाकायतें रैफर कर दी है मैं जानना चाहता हूं कि कंसर्ड क्वार्टर्ज कौन कौन से है?

**चौधरी राजेन्द्र सिंह:** जिस जिस महकमें से वे अफसर ताल्लुक रखते थे वही कंसर्ड क्वार्टर्ज है।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, यह तो इलैक् ान में पक्षपात करने की ि ाकायतें हैं इसमें डिपार्टमेंट से पूछने की क्या बात है।

**चौधरी राजेन्द्र सिंह:** उनके खिलाफ ऐक् ान लेने के लिए ये ि ाकायतें भेजी हैं कि वाक्या ही उन्होंने ऐसी बात की है या नहीं। जो आपने एलीगे ान लगाएं हैं अगर वे ठीक पाए गए तो कंसर्ड अफसर ही ऐक् ान लेंगे।

**श्री निहाल सिंह:** स्पीकर साहब, जिन अफसरों के खिलाफ ि ाकायतें आई है उनके नाम क्या क्या है और वे किस किस पद पर काम करते हैं।

**चौधरी राजेन्द्र सिंह:** एक कम्प्लेंट श्री गोविन्द भारतद्वारा की है। इसने डीसी, एसपी, एसडीओ के खिलाफ रिपोर्ट की है।

दूसरी श्री राम बिलास भार्मा की कम्प्लेंट हैं। इन्होंने श्री कंवल सिंह पटवारी, श्री दलीप सिंह पटवारी, श्री धनी राम पटवारी, श्री साधू राम पटवारी, श्री नत्थू राम पटवारी तथा रैवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ और कर्मचारी। इसी तरह से श्री ब गीर अहमद ने श्री भगवती प्रसाद, डीसी गुडगांव और उनके जीए के खिलाफ एलीगे तन लगाए हैं कि कवे कांग्रेस (आई) के हक में ओपनली काम कर रहे हैं। उसके बाद श्री राम बिलास भार्मा की कम्प्लेंट हैं जिसमें जाटूसाना के बीडीओ, श्री हीरा लाल, एसएचओ फरूख नगर, एसडीओ गुडगांव और तहसीलदार, नारनौल के खिलाफ एलीगे तंज लगाएं हैं कि उन्होंने वोटर्ज को कांग्रेस (आई) को वोट देने के लिए प्रैस किया। उसके बाद फिर श्री राम बिलास भार्मा की कम्प्लेंट हैं जिसमें उन्होंने हीरा लाल एसएचओ पर इल्जाम लगाया है कि उसने वोटर्ज को कांग्रेस (आई) को वोट डालने के लिए मजबूर किया। इसके बाद श्री रघु यादव की कम्प्लेंट हैं। उन्होंने श्री हीरा लाल एसएचओ फरूख नगर के खिलाफ इलजाम लगाया है कि उसने कांग्रेस (जे) के एजेंट के तौर पर काम किया इसके बाद श्री निहाल सिंह की कम्प्लेंट है जिन्होंने एसडीएम रिवाडी के बारे में लिखा है कि उन्होंने बोगस वोटें डाले जाने के खिलाफ कोई एक् तन नहीं लिया जबकि उनको इस बारे में एप्लीके तन भी दी गई थी। इसके बाद दो कम्प्लेंटस श्री राम चन्द्र और श्री ओम प्रका त की हैं जिन्होंने एसएचओ फरूख नगर और एसडीओ रिवाडी की ि तकायत की है। ये सभी कम्प्लेंटस संबंधित डीसीज और कमी तनर्ज को रैफर कर दी गई है।

**श्री मंगल सैन:** क्या मंत्री जी बताएंगे कि इन कम्प्लेंटस के अलावा कोई कम्प्लेंट रोहतक के डिस्ट्रिक्ट एजूके इन अफसर के खिलाफ भी मिली है?

**चौधरी राजेन्द्र सिंह:** इसके लिए तो सैपरेट नोटिस चाहिए क्योंकि यह सवाल गुडगांव और महेंद्रगढ के बारे में है।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** स्पीकर साहब, ये जो कम्प्लेंटस आई है ये एसडीएमज और डीसीज के खिलाफ आई हैं तो जब हमारी कम्प्लेंटस उनके ही खिलाफ है और वे उनको ही रेफर कर दी गई हैं तो वे इनका न्याय कैसे कर पायेंगे?

**मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रिटिकायत डीसी के खिलाफ है तो उसकी इंक्वायरी कमि नर करेगा और अगर डीसी के नीचे के लैवल के अफसर के खिलाफ रिटिकायत है तो उसकी इंक्वायरी डीसी करेगा।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, अगर कोई गलत काम डीसी के कहने पर ही पटवारी करता है तो उस मामले में डीसी क्या न्याय दे सकता है।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, डा0 साहब को मैं क्या कहूं। ये तो बहुत पुराने मैम्बर है और उम्र में भी कुछ बडे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब किसी को बहुत बुरी हार हो जाती है तो आदमी ऐसे ही कहा करता है। राव बीरेंद्र सिंह जी 2 लाख 30

हजार वोटों से जीते हैं। अगर इसके बावजूद भी ये कहें कि ये गलत जीते हैं तो मैं यही कहूंगा कि इनको वहम हो गया है। ( गोर) इस हार के बाद इनके वहम को हम कैसे निकालें ( गोर) जो आदमी अढाई लाख वोटों से जीता हो उसमें गडबड क्या हो सकती है।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, सेंट परसेंट पोलिंग हो ही नहीं सकती। ( गोर)

**चौधरी भजन लाल:** स्पीकर साहब, जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने पैटी इन दायर की है। जब पैटी इन दायर की हुई हो तो उस बारे में बहस नहीं करनी चाहिए। जहां तक हम समझते हैं आपको सोच में और हमारी सोच में थोडा बहुत अन्तर हो सकता है। लोगों ने जो रिक्वायत की है उस बारे में इन्कवायरी हो रही है आपकी की बात करते हैं कभी उचाना हल्के का जिकर करते हैं और तययूब हुसैन जी नूह का जिकर करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय चुनावों में जनता ने इसको काफी कंडेम किया है उसका जहर अभी तक उपर से उतरा नहीं है। ( गोर)

**श्रीमति चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, ये 1982 के चुनावों में हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** मैम्बर साहेबान अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारकित प्रश्नों के  
लिखित उत्तर

**Construction of MIG, LIG and One Room set Houses in  
Sonepat**

**\*953. Shri Devi Dass:** Will the minister for Local Government be pleased to state-

(a) the total number of quarters which stand constructed at present in Housing Colony Phase-III, Sector-14, Sonepat togetherwith the cost thereof at the time of inviting applications; and

(b) whether any increase was made in the prices of the dsaid quarters at a later stage, if so, details thereof in respect of MIG, LIG and One Room set and Two Room set etc.?

**स्थानीय भासन मंत्री (श्री प्यारा सिंह):**

(क) तथा (ख) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

**विवरणिका**

(क) हाउसिंग बोर्ड ने हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सोनीपत के सैक्टर 14 फेज 3 में 106 कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 151 निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 46, ए माध्यम आय वर्ग तथा 56 बी मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए। आवेदन आमन्त्रण के समय इनकी अनुमानित लागत निम्न प्रकार से थी-

ई.डब्ल्यू.एस.	रुपये 8000/- प्रति इकाई
एल.आई.जी.	रुपये 18000/-

एम.आई.जी.-ए	रूपये 38506 / -
एम.आई.जी.-बी	रूपये 46200 / -

(ख) अलाटमेंट के समय इन मकानों की कीमते निम्नलिखित विवरण अनुसार बढ़ा दी गई—

ई.डब्ल्यू.एस.	रूपये 15300 / - प्रति इकाई
एल.आई.जी.	रूपये 34600 / -
एम.आई.जी.-ए	रूपये 69700 / -
एम.आई.जी.-बी	रूपये 83100 / -

### **Laboratory Technicians**

**\*887. Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the minister for State for Health be pleased to state-

(a) the number of sanctioned posts of Laboratory Technicians (Malaria) as on 31.1.1984 togetherwith the number of said Technicians actually working in the Primary Health Centres in the State on the same and the norm, if any, prescribed for the creation of the said posts;

(b) whether the number of Technicians, as referred to in part (a) above. conform to the said norm; if any, prescribed; and

(c) the method of recruitment prescribed for the said posts?

**स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री करतार देवी):**

(क) दिनांक 31-12-84 को प्रयोग ाला तकनीि ायन (मलेरिया) के 71 पद स्वीकृत थे, सात प्रयोग ाला तकनीि ायन (मलेरिया) 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य कर रहे थे जबकि अन्य 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक एक प्रयोग ाला सहायक (मलेरिया) कार्य कर रहा था। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रयोग ाला तकनीि ायन (मलेरिया) के पद में भरने का नाम निर्धारित है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रयोग ाला तकनीि ायन (मलेरिया) के पद निम्नलिखित वर्गों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(1) सफाई निरीक्षकों / मलेरियों निरीक्षकों (निर्धारित प्रि ाक्षण तथा योग्यता सहित) वरिष्ठता कम मैरिट के आधार पर तथा जो 3/4 वर्ष का अनुभव रखते हों तथा कर्मचारियों का सेवा रिकार्ड संतोशजनक हो।

(2) प्रयोग ाला सहायक (मलेरिया) के पदों को मूल स्वास्थ्य कर्मियों में से वरिष्ठता कम मैरिट के आधार पर तथा तीन सप्ताह को माईकोस्कोपिक प्रि ाक्षण दे कर पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।



## **Cases of Murder and attempt to Murder**

**\*816. Prof. Sampat Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of cases of murder and attempt to murder, registered under sections 302 and 307 IPC in the Districts of Hisar, Sirsa, Rohtak and Sonapat separately during the period from 1<sup>st</sup> January, 1982 to date;

(b) the names and addresses of the murdered persons as referred to in part (a) above;

(c) the names and addresses of the persons against whom the cases, as referred to in part(a) above, have been registered;

(d) the names and addresses of such persons, out of those referred to in part (b) above as are Harijan's;

(e) the number of such cases, out of those referred to in part (a) above as are pending in the courts, togetherwith the number of cases, out of those referred to in part(c) above in which the accused persons have been convicted and acquitted separately; and

(f) whether any cases, out of those referred to in part(a) above, are still untraced; if so, the details thereof?



क) से (च) तक:- सूचना सदन के पटन पर रखी जाती है।

### सूचना

क								ख			ग					
दर्ज हुए मुकदमों की संख्या								मारे गये व्यक्तियों की संख्या			उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध जिनके विरुद्ध मुकदमें दर्ज किये गये					
क्र० सं०	जिला	82		83		84		82	83	84	82		83		84	
		302	307	302	307	302	307				302	307	302	307	302	307
1	हिसार	52	44	44	39	49	31	58	51	53	133	119	112	140	112	71
2	सिरसा	29	26	27	25	15	16	30	27	16	60	85	81	69	30	46

3	रोहतक	48	12	47	21	49	12	50	49	62	108	28	86	44	144	21
4	सोनीपत	19	11	17	9	28	13	26	19	30	42	50	66	42	72	46
	जोड	148	93	135	94	151	72	164	146	161	343	282	345	295	378	184

नोट:- 471 मारे व्यक्तियों तथा 1827 देशियों के नाम व पते इक्टडे करने में जितना समय व परिश्रम लगेगा उसके मुकाबले में सम्भव लाभ की प्राप्ति बहुत कम होगी।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) में दिए गए मारे गये व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते जो हरिजन हैं—

### जिला हिसार

1. सर्वजीत कौर पुत्री नि गान सिंह रामदासिया निवासी बादलगढ ।
2. गुरनाम पुत्र किरपाल मजहबी निवासी सरदारेवाला ।
3. बीरू बालमिकी निवास बुआन ।
4. लीलू पुत्र रूपा हरिजन निवासी कुमहाड ।
5. राजी पत्नी भाम रेर धानक निवासी सतरोड ।

### वर्ष 1983

1. बीकर पुत्र गुरमेल हरिजन निवासी रतिया ।
2. जयदेव पुत्र बीर सिंह हरिजन निवासी हबोतपुर ।
3. बसन्ती पत्नी राम सरूप हरिजन निवासी नया गांव ।
4. फुला पुत्र मातु धानक निवासी भाहपुर ।
5. जरनैल पुत्र गरजा सिंह चमार निवासी दमकौरा
6. गुरजा सिंह चमार निवासी दमकौरा ।

7. औम हरिजन निवासी ढान्ड ।

### वर्ष 1984

1. सूरज भान हरिजन निवासी थूराना ।
2. करतार पुत्र सुधन हरिजन निवासी बुढाना ।
3. रामफल नैल निवासी भटौर ।
4. कामीर पुत्र बुरजन मजहबी सिक्ख निवासी खुनान ।
5. हनुमन्त राय हरिजन निवासी मोरी ग्रेट हिसा ।
6. गुरजा सिंह चमार निवासी दमकौरा ।
7. औम हरिजन निवासी ढान्ड ।

### जिला सिरसा

1. तारा चन्द पुत्र बनवारी लाल बाल्मिकी निवासी बलीयाना जिला रोहतक ।
2. श्रीमति विमला पत्नी खुर गीद बाल्मिकी निवासी बैनी थाना रानिया सिरसा ।

### वर्ष 1983

1. हरनाम सिंह पुत्र सिंह राम चमार हरिजन निवासी घीला खेडा थाना फतेहाबाद जिला हिसार ।

2. भोगा सिंह पुत्र सुहागा सिंह मजहबी सिक्ख निवासी  
वाहरालवाली थाना सिरसा ।

3. बचित्तर सिंह उर्फ छिन्दा पुत्र करनैल सिंह मजहबी  
सिक्ख निवासी बहादुर खेडा थाना सदर अबोहर जिला भटिण्डा ।

### जिला रोहतक

#### वर्ष 1982

1. धर्मपाल पुत्र जामी राम हरिजन निवासी बिधराना ।

#### वर्ष 1983

1. दिलबाग पुत्र ताले राम हरिजन निवासी रोहतक ।

3. बीरू बाल्मिकी निवास बुआन ।

### जिला सोनीपत

1. हरी राम हरिजन निवासी बराहमनवास ।

2. राम कुमार पुत्र अनिल बाल्मिकी निवासी राबडा ।

3. रनवीर पुत्र मामन बाल्मिकि निवासी बरौदा ।

#### वर्ष 1983

1. भीमा बाल्मिकि निवासी बहालगढ ।

#### वर्ष 1984

1. सरतू पुत्र रामजी लाल हरिजन निवासी खेडा दहिया ।
2. कालू पुत्र माम चन्द हरिजन निवासी देवडू ।
3. रमे । पुत्र रामचन्द हरिजन निवासी भगान थाना  
गन्नौर ।
4. राम चन्दर निवासी गन्नौर ।





(क) वर्ष 1982, 1983 तथा 1984 में हत्या तथा हत्या के प्रयत्न से संबंधित (धारा 302 भदस तथा 307 भदस) मुकदमों की सूचना को न्यायालय में लम्बित हैं जो सजा तथा बरी हो चुके हैं।

		1982						1983						1984							
क्र. सं.	जिला	न्यायालय में लम्बित		सजा हुए		बरी हुए		न्यायालय में लम्बित	302	307	सजा हुए		बरी हुए		न्यायालय में लम्बित		सजा हुए		बरी हुए		
		30	30	30	30	30	30				302	307	302	30	30	30	30	30	30	30	30
		2	7	2	7	2	7						7	2	7	2	7	2	7	2	7
1	हिसार	17	29	11	1	20	6	30	28	9	3	1	4	26	17	1	2	10	3		
2	सिरसा	—	2	16	5	12	14	11	10	4	5	10	7	9	7	3	1	1	1	4	
3	रोहत	2	1	16	2	22	7	12	8	14	6	10	6	34	8	2	1	7	1		

	क																		
4	सोनीप त	1	3	7	3	5	5	—	4	3	—	12	4	18	7	—	—	4	2
	जोड	20	35	50	11	59	32	53	50	30	14	33	21	87	39	6	4	22	10

(ख) वर्ष 1982, 1983 तथा 1984 में हत्या तथा हत्या के प्रयत्न के मुकदमों से संबंधित सूचना जो अदमपता भेजे गए।

		1982		1982		1983	
क	जिला	302	307	302	307	302	307
0							
सं							
0							
1	हिसार	2	3	3	2	—	1
2	सिरसा	1	1	2	1	2	1
3	रोहतक	8	2	4	1	2	—
4	सोनीपत	6	—	2	1	5	—
	जोड	17	6	11	5	9	2

अदमपता भेजे गए मुकदमों का विवरण देने में जितना समय व परिश्रम लगेगा उसके मुकाबले में सम्भव लाभ की प्राप्ति बहुत कम होगी।

#### **Upgradation of Schools in District Faridabad**

**\*931. Chaudhri Khillan Singh:** Will the Minister of State of Education be pleased to state the area-wise details and number of schools if any, upgraded during the year 1984-85 in district Faridabad?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): वर्ष 1984-85 के दौरान जिला फरीदाबाद में 12 स्कूलों (6 प्राइमरी से मिडल और 6 मिडल से हाई) का स्तर बढ़ावा गया है। क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स्कूल की कैटेगरी	क्षेत्रवार विवरण		
	ग्रामीण	भाहरी	जोड़
प्राथमिक से मिडल	6	—	6
मिडल से हाई	4	2	6

**Liquor Shops in Haryana**

**\*937. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to gradually decrease the number of vends for country liquor and Indian made foreign liquor in the State; if so, the details of the steps, if any taken or proposed to be taken for the purpose?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): भाराब के ठेकों की संख्या इसकी कुल आव यकता को ध्यान में रख कर नि चित की जाती है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ठेकों की संख्या में थोड़ी सी कमी हुई है।

### **Release of Water in Sheranwali Distributory**

**\*955. Shri Bhagi Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the extent of water released in Sheranwali distributory during the period from 1<sup>st</sup> December 1984 to 1<sup>st</sup> March 1985; and

(b) if full water has not been released in the said distributory during the said period the reasons therefore?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला):

(क) भोरांवाली वित्रिका में 1-12-1984 से 1-3-1985 तक कुल 6056 क्यूसिक्स दिन पानी छोडा गया।

(ख) इस समय के दौरान यह वित्रिका अनुमोदित रोटे ानल प्रोग्राम के अनुसार चलाई गई थी।

### **Construction of Harijan Chaupals in the State**

**\*948. Master Ram Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the number of Harijan Chaupals constructed in the State during the period from 1-1-1982 to 31<sup>st</sup> December, 1984;

(b) the number of Harijan Chaupals, if any, under construction at present; and

(c) the number of Harijan Chaupals, if any, proposed to be constructed during 1985-86?

**उद्योग मंत्री (श्रीमति भाकुन्तला भगवाडिया):**

(क) 903

(ख) 299

(क) 52

**विभिन्न विशयों का उठाना जाना**

**डा० भीम सिंह दहिया:** स्पीकर साहब, फरीदाबाद में बंधुआ मजदूरों की दुर्दशा को लेकर लोकसभा में कई दिनों से चर्चा हो रही है और भारत सरकार ने यह आवासन दिया है कि इस बारे में कोई मीटिंग बुलाएंगे। यह बड़े अफसोस की बात है कि हरियाणा सरकार के मामले को भारत सरकार को सुलझाना पडा। इस बारे में मैंने आपकी सेवा में एक काल अटेंशन मोड का नोटिस दिया है उसका क्या बना?

**श्री अध्यक्ष:** मैं उसे कंसीडर कर रहा हूँ।

**डा० भीम सिंह दहिया:** स्पीकर साहब, इसी तरह से एक और काल अटैं इन मो इन का नोटिस दिया है। हमारे में एक प्रोफ़ैसर्ज कालोनी है उसके अन्दर एक सज्जन पुरुश ने आरे की मीन लगा ली है। इस बारे में भी बता दें।

**श्री अध्यक्ष:** डा० साहब वह मेरे पास आज सुबह आया है मैं उसे कंसीडर करूंगा।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, मैंने कल सुबह आपकी सेवा में क्वेरीज के बारे में एक काल अटैं इन मो इन का नोटिस दिया है। वह मो इन किस स्टेज पर है उसके बारे में बता दें?

**श्री अध्यक्ष:** वह अभी मुझे मिला नहीं है।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, वह मैंने कल सुबह 9.00 बजे आपकी सेवा में दे दिया था।

**श्री अध्यक्ष:** अभी मुझे सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि वह उनके पास अंडर कंसीड्रे इन है जब मेरे पास पहुंचेगा तो मैं उसे कंसीडर करूंगा।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि क्वेरीज के मामले को लेकर पिछले सैं इन में भी काफी बातें हुई थी। क्वेरीज में जो लोग काम करते हैं वे मोस्टली रिडयुल्ड कास्टस हैं। उनकी एक्सप्लायटे इन अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसम्बर 1983 को अपनी जजमेंट में 20-21



डायरेक्टिवज स्टेट गवर्नमेंट को दिए थे। उनको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और उन्हें प्लाउट किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को क्वेरीज की पालिसी के बारे में बताना चाहिए कि नई पालिसी क्या है?

**श्री अध्यक्ष:** मैं इसे कंसीडर करूंगा और फिर आपको बताऊंगा।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में परसों एक काल अटेंशन मोशन का नोटिस दिया था कि रोहतक भाहर में पीने का पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है इस बारे में सीएम साहब ने अयोरेंस भी दी थी। रोहतक भाहर की नगरपालिका के एरिया में लोगों को पीने का पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है।

**श्री अध्यक्ष:** डा० साहब, मैंने गवर्नमेंट से इसी बारे में चौधरी ओम प्रकाश के नोटिस पर कमेंट्स मांगे हुए हैं। आपका नोटिस भी उसके साथ आ जाएगा।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, मैं कल मुख्यमंत्री जी से परसनली मिला था और मैंने इस बारे में कहा था कि आपको डीसी साहब ने जो बात कही है वह ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, यह बड़ा अरजेंट मैटर है और पब्लिक इम्पोर्टेंस का है।

**श्री अध्यक्ष:** मैंने आपको बता दिया है कि इस बारे में कमेंट्स मांगे हुए हैं।

**चौधरी कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, मैं जीरो आवर में बोल रहा हूँ यह मेरे पास दसवीं क्लास का पेपर है यह थोडा सा छपा हुआ है बाकी सारा कागज खाली है। इसके अलावा इसकी प्रिंटिंग भी ठीक नहीं है यह कागज भी घटिया है।

**श्री अध्यक्ष:** आप इस बारे में लिख कर दें दे। मैं उसे कंसीडर कर लूंगा।

**चौधरी कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैं इन मो इन का नोटिस दिया है कि महेंद्रगढ नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर ने मेन बाजार में दो दुकानों के सामने मलवा फैंकवा दिया है। उस बारे में आपने क्या फैसला लिया है?

**श्री अध्यक्ष:** वह आज सुबह आया है मैं उसे देखूंगा।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** स्पीकर साहब, मैंने पीने के पानी के बारे में एक काल अटैं इन मो इन का नोटिस आपकी सेवा में दिया था और आपने वह नोटिस भी कर लिया था।

**श्री अध्यक्ष:** उस बारे में आज ही कंसन्ड मिनिस्टर अपनी स्टेटमेंट देंगे।

**चौधरी नर सिंह ढांडा:** स्पीकर साहब, मैंने भी आपकी सेवा में एक काल अटैं इन मो इन का नोटिस भाार्टेज आफ

इलैक्ट्रिसिटी और फेल्योर आफ रेन के बारे में 18 तारीख को दिया था उसके बारे में आपने क्या फैसला लिया है?

**श्री अध्यक्ष:** मैंने इस बारे में गवर्नमेंट कमेंटस मांगे हैं।

**श्रीमति चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, मैंने भी आपकी सेवा में तीन काल अटैं इन मो इंज के नोटिस दिए थे। मेरा एक काल अटैं इन मो इन तो तहसील टोहाना में दुलत ढाणी गांव की कारपैन्टरस की बारात को लीलत गांव में पीटा गया था। उन तीनों नोटिसिज के बारे में आपने क्या फैसला किया है?

**श्री अध्यक्ष:** आपके तीनों नोटिस डिसअलाउ हो चुके हैं और आपको इन्फर्मे इन भेज दी गई है।

**श्री भागी राम:** स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में एक काल अटैं इन मो इन का नोटिस दिया था कि सिरसा जिले में खास करके बारानी एरियाज में चने की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। उस बारे में आपने क्या फैसला लिया है?

**श्री अध्यक्ष:** अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है मैं उसे कंसीडर करूंगा।

**श्री ओम प्रकाश:** मैंने भी आपकी सेवा में एक काल अटैं इन मो इन का नोटिस दिया था कि भिवानी, रोहतक और जींद के एरिया में पानी व बिजली न मिलने की वजह से चने की

फसल बिल्कुल बरबाद हो चुकी है। उस बारे में आपने क्या फैसला लिया है?

**श्री अध्यक्ष:** इस बारे में मैंने गवर्नमेंट से कमेंट्स मांगे हैं।

### राज्यपाल का संदेश

**Mr. Speaker:** Hon. Members I have received a message from the Hon'ble Governor which reads as follows:-

“I write to acknowledge with thanks the receipt of your demi-official letter No. HVS-LA/22/85/7767 dated 15<sup>th</sup> March 1985 forwarding a copy of motion of thanks passed by the Haryana Vidhan Sabha at its meeting held on 15<sup>th</sup> March, 1985. I shall be grateful if you kindly convey to the Hon'ble Members of the Haryana Vidhan Sabha my thanks and appreciation for this kind thought in accepting the motion.”

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, मैं आपकी सेवा में एक बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब के एड्रेस पर धन्यवाद का प्रस्ताव पास होने के बाद गवर्नर साहब हमें हमें आपकी थ्रू खाने के लिए याद किया करते हैं क्या उन्होंने हमें खाने पर बुलाया है या आप हमें खाने पर बुलाने के लिए कह रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** डा० साहब, मेरी तरफ से आप सभी माननीय सदस्यों को इस महीने की 29 तारीख को खाना दिया जायेगा।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक अनप्लैजेंट बात कहना चाहता हूँ कि सदन में हर डिपार्टमेंट की तरफ हर साल रिपोर्ट्स आया करती है लेकिन अभी तक हमारे पास किसी भी विभाग की तरफ से रिपोर्ट नहीं आई है। वे कब तक आएंगी ताकि हम उनके बारे में रूल 84 के तहत डिस्कान के लिए लिखकर दे सकें और उन पर डिस्कस कर सकें। हरियाणा सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स बड़ी मेहनत के बाद अपनी अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। यदि वे रिपोर्ट्स सदन में नहीं आएंगी तो उनके बारे में डिस्कान नहीं हो सकेगी। यदि डिस्कान नहीं हो सकेगी तो उन रिपोर्ट्स का क्या फायदा? आप हमारी बात को एप्रिप्रिएट कीजिए और गवर्नमेंट को पुलअप कीजिए। इस बारे में आप गवर्नमेंट का लिहाज बिल्कुल न कीजिए। Your position is dignified and you are all powerful, Sir.

**श्री अध्यक्ष:** डा० साहब इस बारे में मैं आपको दो घंटे के बाद बताऊंगा।

### वक्तव्य

लोक स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भिवानी तथा महेन्द्रगढ़ जिलों में पेयजल की भारी कमी सम्बन्धी

**श्री अध्यक्ष:** आनरेबल मैम्बरज, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने आज श्री हीरा नन्द आर्य की काल अटैंडेंस को नोटिस देकर

नम्बर 13 पर स्टेटमेंट देने के लिए कहा था। वे कृपया अपनी स्टेटमेंट दे दें।

**लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमति प्रसन्नी देवी):** इससे पूर्व कि मैं सदन के समक्ष भिवानी और महेंद्रगढ जिलों में भिन्न भिन्न ग्रामों में पेयजल की स्थिति के विषय में कोई विवरण दूं, मैं इस महान सदन को यह सूचित करना चाहती हूं कि सरकार स्थिति से पूरी अवगत है और नियमित पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक पग उठा रही है सिवाय कुछ विस्तारों के जो नियंत्रण से बाहर हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दिये गये 29 गांवों में से 22 गांव जिनके नाम इस प्रकार हैं: 1. खरखडी 2. गारवा 3. सैनीबास 4. मिथि 5. मोरका 6. कटवार 7. तलबानी 8. सुरपुरा कलां 9. सुरपुरा खुर्द 10. पतवां 11. सुधिवास 12. कलाली 13. विधवां 14. मंढोली खुर्द 15. सिवाच 16. बुधसैली 17. कलोड 18. गुढा 19. गंगोली 20. मोतीपुरा 21. मतानी 22. संडवा को पेयजल सुविधा साहडवा जल घर से प्रदान की जा रही है। यह पेयजल योजना 50 गांवों की है और वर्ष 1967-68 में 5 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन के आधार पर बनाई गई थी। इस समय इस पेयजल योजना के अन्तर्गत गांवों की आबादी 74000 है जबकि यह योजना केवल 52000 की आबादी के लिए बनाई गई थी। लगभग सभी गांवों में भूमिगत जल खारा है और विंशट स्रोत किसी भी गांव में उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह योजना नहर के उपर ही आधारित

की गई थी। जनसंख्या के आधार पर तथा जलधर की सीमित क्षमता के कारण जोकि 5 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। सीमित मात्रा में ही पानी की उपलब्धि कराई जा सकती है। बिना किसी रूकावट के पानी उपलब्ध कराने के लिए जलधर तथा 2 बूस्टिंग स्टेजों के उपर डिजल स्टैंडबाई पम्प लगाये गये हैं।

उपरोक्त गांवों में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं:-

दो नई परियोजनाएं, ईगानवाल 5 गांवों की सामूहिक योजना तथा सांडवा 3 गांवों की जल वितरण योजनाओं को अनुमति प्रदान कर दी गई है। सांडवा ग्राम समूह योजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसके अतिरिक्त एक और नई योजना 2 गांवों बूरा तथा दुबेटा को भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और इस पर कार्य भीघ ही चालू कर दिया जायेगा। जब भी उपरोक्त योजनाएं पूरी हो जायेगी इनमें से ये 10 गांव साहडवा ग्राम समूह से अलग कर दिये जायेंगे और इस प्रकार भोश 40 गांवों में पानी की मात्रा में बढौतरी हो जायेगी।

मुख्य साहडवा ग्राम समूह योजना को बढ़ाने के लिए अनुमान तैयार किए जा रहे हैं और सरकार धन राशि की उपलब्धि को देखते हुए इसकी स्वीकृति पर विचार कर रही है।

2 गांवों जिनके नाम लिलस तथा ढानी सालेवाली को देवसर समूह में तथा 2 गांव मोहला और गुरेरा, किकराल गुप में

भामिल किए गए है। जोकि 10 गैलन प्रति दिन प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा के आधार पर बनाई गई है और सम्पूर्ण कर दी गई है तथा अब इन 4 गांवों में पानी पूरी मात्रा में दिया जा रहा है।

बारडा तथा डालनवास ग्रामों की जल वितरण योजनाएं महेंद्रगढ जिले में आती है तथा यह गहरे कुओं पर आधारित है जिनकी पानी देने की क्षमता इन दोनों गांवों के निवासियों के लिए पर्याप्त है। फिर भी बिजली की वितरण तालिका अनुसार सीमित मात्रा में ही लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पानी दिया जा रहा है।

गांव नावां जो कि महेंद्रगढ जिले में आता है किसी भी जल वितरण योजना में भामिल नहीं किया गया है परन्तु यह समस्याग्रस्त गांव होने के कारण इसका अनुमान स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बनाया जा रहा है।

उपरोक्त द ाई गई स्थिति के अनुसार उपरोक्त गांवों में सीमित मात्रा में पानी दिया जा रहा है तथा आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा रहे हैं ताकि पानी की मात्रा में बढौतरी की जा सके। यहां यह कहना भी उचित होगा कि सरकार डीजल इंजन तथा जनरेटिंग सैट जल वितरण योजनाओं के लिए वििाश्ट ढंग से लगाने के लिए गम्भीरता से विचार कर रही है जिससे कि सुचारू रूप से पानी दिया जा सके।



**श्री हीरा नन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने बताया है कि 10 गांवों में पानी देने के लिए एक नई योजना बनाई गई है। इन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 1967-68 में जहां इन गांवों की आबादी 52 हजार थी वह अब बढ़ कर 74 हजार हो गई है। पहले इन सारे गांवों में 5 गैलन प्रति व्यक्ति पानी देने की योजना बनाई गई थी। अध्यक्ष महोदय ये सारे गांव सुधिवास समेत टेल पर पड़ते हैं। टेल पर पड़ने की वजह से इन गांवों में पानी नहीं पहुंच पाता। यदि पहुंचता भी है तो वह भूल चूक कर ही पहुंच पाता है। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यदि वहां पर पानी सही मात्रा में पहुंचे तो भी अढाई तीन गैलन के हिसाब से पानी नहीं पहुंच पाता क्योंकि कभी पानी की समस्या रहती है तो कभी बिजली की रूकावट आ जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन गांवों में भी 10 गैलन प्रति व्यक्ति पानी देने के लिए कोई नई योजना बनाने का विचार है ताकि वहां के इलाके के लोगों की पीने के पानी की समस्या खत्म हो सके।

**श्रीमति प्रसन्नी देवी:** इन्होंने कुछ गांवों के बारे में पूछा था वह मैंने बता दिया है किसी विशेष गांव के बारे में पूछेंगे तो वह बता दिया जायेगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से पूरी कोशिश होती है कि जितना पानी नहर के जरिए या ट्यूबवैल के जरिए अवेलेबल हो सकें वह दिया जा सके। स्पीकर साहब, पीने के पानी की स्पैशियल प्राथमिकता दिए जाने की कोशिश की जाती है। मैंने माननीय सदस्य को लिखित जवाब में बताया है कि

10 गांवों में अलग से पीने के पानी का प्रबन्ध किया जा रहा है। इन 10 गांवों में से अभी 4 गांवों में ही चालू हो जाएगा तो ये 10 गांव इन 40 गांवों में से निकल जाएंगे। इस प्रकार इन 40 गांवों में से 10 गांवों के निकल जाने के बाद जो पापुले उन वहां की है वह भी कम हो जायेगी। इस प्रकार पापुले उन कम होने की वजह से इन गांवों में भी पानी की और सुविधा हो जायेगी।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** स्पीकर साहब, अभी इन्होंने बताया है कि 10 गांवों के लिए अलग से योजना बनाई गई है और इन में से 4 गांवों में पानी चालू हो चुका है। इन 4 गांवों में प्रति व्यक्ति 10 गैलन के हिसाब से पानी दिया जा रहा है। साथ ही इन्होंने यह भी बताया है कि ये 10 गांव इन 40 गांवों से अलग हो जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दूसरे गांवों में भी पानी की मात्रा को बढ़ाया जायेगा?

**श्रीमति प्रसन्नती देवी:** स्पीकर साहब, जो जवाब मैंने दिया है उसमें बताया है कि 4 गांवों में 10 गैलन प्रति दिन प्रति व्यक्ति पानी दिया जा रहा है और बाकी गांवों में 5 गैलन प्रति व्यक्ति पानी दिया जा रहा है। मैं इन्हें यह भी बताना चाहूंगी कि इन 4 गांवों के अतिरिक्त जो गांव इन्होंने अपनी मो उन में दिए है उनमें 5 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से ही पानी दिये जाने की योजना रहेगी।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** स्पीकर साहब, मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि जब सारे प्रदेश में 10 गैलन पानी देने की योजना है तो भिवानी जिले के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है जबकि वहाँ पर पहले ही पानी की काफी समस्या है इसके अलावा अब गर्मी का मौसम भी आ रहा है जिससे वहाँ पर पानी की और भी भयंकर समस्या हो जाएगी।

**श्री अध्यक्ष:** आप भिवानी जिले में भी 10 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी देने का प्रबंध करिए।

**श्रीमति प्रसन्नती देवी:** स्पीकर साहब, वहाँ पर ट्यूबवैल्ज भी कामयाब नहीं है। उस एरिया में सिर्फ नहर का ही पानी जाता है जिस कारण यह कठिनाई है। यदि वहाँ पर 300-400 फुट पर जाकर कहीं कोई ट्यूबवैल लगता है तो उसका भी पानी खारा निकलता है जिस कारण उस एरिया में पानी की बहुत भारी समस्या है। सिर्फ नहर का पानी होने के कारण ही उस एरिया में 5 गैलन पानी देने की योजना बनाई गई है। स्पीकर साहब, जब पानी उस एरिया में नहर के जरिए पहुंचेगा तभी सबको पानी मिल सकेगा।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, ये पानी की समस्या के बारे में यहाँ पर जिकर कर रही है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रोहतक की समस्या का भी कोई इन्हें ख्याल है क्योंकि वहाँ पर पीने के पानी की समस्या कई दिनों से बनी हुई है?

**श्री अध्यक्ष:** डा० साहब, रोहतक के बारे में भी अलग से एक क्वै चन एक दो दिन में आ रहा है।

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, कल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोहतक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बारे में अपनी जजमेंट दी है। वहां पर काफी दिनों से स्थिति कमकामकी एक लीगल प्वायंट को लेकर चल रही थी। (विधन) लोग वहां पर एग्रीव थे... (गोर एवं विधन)

**श्री अध्यक्ष:** इस बारे में हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है।

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, अभी भी वे वाइस चांसलर बने हुए हैं। उस यूनिवर्सिटी से हरियाणा के लोगों के हित जुड़े हुए हैं। कल हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी है। (विधन)

**Mr. Speaker:** What do you want now?

**श्री राम बिलास भार्मा:** ड

**Mr. Speaker:** Can the judgement be ignored?

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, हाईकोर्ट से स्ट्रिकचर पास होने के बाद भी वे वाइस चांसलर बने हुए हैं। अब कोई कोर्ट ने उनको अपील की भी इजाजत नहीं दी है। इस यूनिवर्सिटी के साथ कई लोगों की जिन्दगी जुड़ी हुई है। मैं तो

यही जानना चाहता हूँ कि वे आज के दिन वाईस चांसलर हैं या नहीं। इस बारे में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष:** क्या आपने इस बारे में कोई काल अटेंशन मोशन वगैरह दी है?

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, कुछ बातों पर आप बगैर काल अटेंशन मोशन का नोटिस दिये बोलने की इजाजत दे देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बारे में भी सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करें क्योंकि यह एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है।

**Mr. Speaker:** I cannot ask the Minister to make a statement off hand. If you give a notice it will be considered.

### गैर सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा सम्बन्धी प्रक्रिया के नियमों में संशोधन का प्रश्न उठाना

**श्री हीरा नन्द आर्य:** स्पीकर साहब, मैंने पिछली दफा 14.3.85 को नौन आफिशियल रैज्योलूशन के बारे में प्वायंट उठाया था और आपसे यह रिक्वेस्ट की थी कि रूलज में अमेंडमेंट कर दी जाये ताकि जो रैज्योलूशन एक सेशन में मूव हो जाये और उस पर डिस्कशन हो जाये तो वह दूसरे सेशन तक न चल सके। जनाब ने एक रूलज कमेटी बनाई थी और उसकी एक सब कमेटी बनाई थी यदि आप मुनासिब समझें तो यह मामला रूलज

कमेटी की सौंप दिया जाये। आपने उस वक्त यह फरमाया था कि इस मामले को देखेंगे।

स्पीकर साहब, क्या आपने इस मामले पर विचार किया है? यदि किसी है तो आपने क्या फैसला लिया है?

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ।

श्री हीरा नन्द आर्य: आप कब तक इस मामले पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: 3-4 दिन में।

### अध्यक्ष द्वारा रूलिंग

#### एक प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा दिये गये भाशणों सम्बन्धी

**Mr. Speaker:** Before the House resumes discussion on the non official resolution regarding S.Y.L. Canal, I want to give a rulling.

आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे यह क्वै चन पुट किया गया था कि जो मैम्बर्ज नान आफिं आयल रैजोल्यू इन पर एक बार बोल चुके हैं उनमें से क्या कोई मैम्बर दोबारा बोल सकता है या नहीं? As per rule, a member cannot speak twice on the same motion.

अब आप जिन सदस्यों के नाम देंगे, उन में उन मैम्बर्ज का नाम न दें जो पहले बोल चुके हैं।

गैर सरकारी प्रस्ताव—

एस0वाई0एल0 नहर के निर्माण सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

**Mr. Speaker:** Now the House will resume discussion on the non-official resolution regarding S.Y.L. Canal which was moved by Shri Devi Dass, MLA on behalf of Shri Fateh Chand Vij, MLA on the 15<sup>th</sup> September 1983 and further discussed on the 15<sup>th</sup> and 29<sup>th</sup> March 1984 and 14<sup>th</sup> March, 1985.

The Irrigation and Power Minister was still on his legs when the House adjourned on the 14<sup>th</sup> March, 1985. He may please resume his speech.

**Irrigation and Power Ministe (Chaudhri Shamsheer Singh Surjewala):** I may be permitted to intervene at any later stage so that I may deal with the other points that may be raised.

**Mr. Speaker:** All right.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, सुरजेवाला जी ने क्या कहा है यह मैंने सुना नहीं है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इन्होंने कहा है कि वे रैजोल्यूशन पर स्टेज पर कंटीन्यू नहीं करेंगे, दूसरे मैनबर को बोलने दें।

### क्लोजर

**Shri Mangal Sein:** This resolution has been discussed for a long time, Sir, and I move-

“That the question be now put.”

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the question be now put.

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल (मुढाल खुर्द): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कांस्टीच्यूशन अमेंडमेंट नं० 53 बिल कल यूनानिमसली पास हुआ है उसी तरह से इस रैजोल्यूशन को भी यूनानिमसली पास करवा लिया जाए।

चौधरी ओम प्रकाश (बेरी): अध्यक्ष महोदय, एसवाईएल कैनल का मसला एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है और पिछले डेढ़ साल से इस प्रस्ताव पर खर्चा चल रही है। (व्यवधान) अब इस सदन में इस चर्चा को बन्द किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस बारे में सरकार के इरादे कुछ और हैं और वह इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही है।



**श्री अध्यक्ष:** इसमें डिस्कान की बात नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं कि यह बड़ा इम्पोर्टेंट इजु है। यह बात दुरुस्त है कि दो साल में डिस्कान हो रही है लेकिन इसके उपर बहस सिर्फ 4 दिन ही हुई है। इसके अलावा मैंने चार्ट देखा है इसके मुताबिक 50 मैम्बरज ऐसे हैं जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है लेकिन फिर भी अगर मैम्बर सोहबान कहते हैं कि क्वैचन पुट किया जाए तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आनरेबल मैम्बरज, के सेंटिमेंटस को समझते हुए मैं इस मोडान को पुट करता हूँ।

**श्री मंगल सैन:** जनाब मेरी एक सबमिशन है। अगला प्रस्ताव उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि यह है। अगला प्रस्ताव बिजली बोर्ड के बारे में है। हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में इतनी ज्यादा किमिनल नैगलीजेंस है जिसका कोई हिसाब नहीं लेकिन ये इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते चाहे हरियाणा की फैक्टरीयां बन्द रहे, चाहे मजदूर बेकार हो जाएं, चाहे होस्पिटल के आप्रेशन थियेटर में हमें ही अन्धेरा रहे, कुछ भी हो जाए हरियाणा सरकार बोर्ड का कुछ नहीं बिगाड सकती। स्पीकर साहब, यह प्रस्ताव भी बड़ा जरूरी है इसी लिए मैंने एसवाईएल के प्रस्ताव पर डिस्कान वाईडअप करने के लिए कहा है।

**श्री अध्यक्ष:** डा० साहब, आप जानते हैं कि I can guided by the rules.

**Shri Mangal Sein:** Therefore, Sir, your hands are tight and you are helpless. लेकिन हम आपसे फरियाद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते ।

**श्री अध्यक्ष:** जैसा हाउस चाहेगा वैसा कर लेंगे ।

**मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा कि यह बड़ा इम्पोर्टेंट रैजोल्यूशन है अभी तक इस पर कम से कम 50 सदस्यों ने बोलना है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस रैजोल्यूशन को जारी रखा जाना चाहिए ताकि सारे मैम्बर्स अपने अपने सुझाव हाउस के सामने रख सकें (व्यवधान) ।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, इस गवर्नमेंट ने यह प्रोमिस किया था कि एसवाईएल को दिसम्बर 1983 तक पूरा कर देंगे । स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी के हाथ से इन्होंने फावडा भी मरवा दिया था लेकिन हुआ कुछ नहीं । ये हरियाणा के इन्ट्रैस्ट के साथ हमें ठग मजाक करते हैं । बडी हैरानी की बात है अब भी इनको इस पर डिस्कशन करने का भाव है । It is just to kill the time, Sir. They are not serious about S.Y.L.

**श्रीमति चन्द्रावती:** जनाब स्पीकर साहब, इस पर बहुत बहस हो चुकी है । मैं कहना चाहती हूँ कि ..... विघ्न

**श्री अध्यक्ष:** जो आप कहना चाहती हैं वह मैं समझ चुका हूँ । आप बैठ जाइए । मैं मोशन मूव कर रहा हूँ ।

**श्री राम बिलास भार्मा:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर ।

**Mr. Speaker:** No point of order please. No more discussion please. I will put the motion to the vote of the House.

Question is-

That the question be now put.

The motion was lost.

### गैर सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

**श्री अध्यक्ष:** अब रैज्योलू इन पर बहस रिज्यूम होगी।  
चौधरी हुकम सिंह।

**चौधरी हुकम सिंह:** स्पीकर साहब, एसवाईएल नहर के प्रस्ताव पर आपके माध्यम से सदन में काफी विचार विमर्श हुआ है। मैं भी इसी प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए एसवाईएल नहर का प्रस्ताव बड़ा महत्व रखता है और उस नहर के साथ किसानों के हित सीधे जुड़े हुए हैं। जिला भिवानी, रोहतक, महेन्द्रगढ़ और गुडगांव के किसानों का हित सीधा इसी नहर के साथ जुड़ा है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, पंजाब से पानी का हिस्सा जो मिला है उसको हरियाणा में लाने के लिए एसवाईएस की स्कीम तैयार की गई थी और बहुत सा पैसा हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार को काम पूरा करने के

लिए दिया है। इस पर काम तो भुरू है लेकिन जिस तेजी से काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। यह बात ठीक है कि जल्दी काम नहीं हो रहा, लेकिन इसके भी कुछ कारण हैं। कारण यह है कि पंजाब में कुछ झगड़े भुरू हो गये जिसकी वजह से देरी हो गई। देरी होने की वजह से हरियाणा के किसान को सफर करना पडा। इससे विशेष नुकसान रोहतक और महेन्द्रगढ के किसानों को हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा कि आपको मालूम होगा जेएलएन 1977 में तैयार हो गई थी और यह नहर एसवाईएल का पानी लाने के लिए ही बनाई गई थी। इस नहर में साढे चार हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होनी थी। इस नहर की कैपेसिटी जहां तक मुझे पता है तकरीबन 3200 क्यूसिक पानी की थी। (व्यवधान) इस नहर पर हरियाणा सरकार का सैंकडों करोड रूपया खर्च हो चुका है। इस नहर के दूसरी तरफ महेन्द्रगढ कैनाल बनाई गई है .....

**श्री राम बिलास भार्मा:** डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी हुकम सिंह जी गलत फिगर कोट कर रहे हैं और हमारा पानी का हिस्सा कम कर रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम है और हमारा पानी का हिस्सा कम कर रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम है 35 लाख मिलियन करोड जमीन के लिए पानी मांग रखा है और यह 3300 की बात कर रहे हैं। कृपा करके ये आंकडों पर न जाये। इनके आंकडे पढ कर हमारा हिस्सा न कट जाए। इस बात का ध्यान रखे।

**चौधरी हुकम सिंह:** आपने मेरी बात सुनी नहीं। यह जेएलएन की बात थी एसवाईएल की बात नहीं है। ये आंकड़े मैं सदन को जेएलएन के बता रहा हूँ। एसवाईएल के प्रस्ताव के साथ जेएलएन का सीधा सम्बन्ध जुड़ता है इसलिए मैंने यह कहा था।

### **11.00 बजे**

डिप्टी स्पीकर साहब, जिस वक्त जेएलएन और महेंद्रगढ़ कैनल को तैयार किया गया था तो उस पर हमारी हरियाणा सरकार का सैंकड़ों करोड़ रूपया लगा था लेकिन उन नहरों में पूरे साल में कभी 15 दिन कभी 20 दिन या कभी दो महीने पानी चलता है। यह पानी भी उस समय चलता है जब रबी या खरीफ की फसलों की बिजाई होती है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस जेएलएन और महेंद्रगढ़ कैनल से महेंद्रगढ़ जिले को पीने के लिए पानी भी दिया जाना था लेकिन इन नहरों में पानी न जाने की वजह से उन लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत रहती है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से रोहतक जिले में खासकर साल्हावास के इलाके में चिडिया खाचरौली और पातवास माइनर्ज से सिंचाई होनी थी। साल्हावास में तो एक पम्प हाउस बनाया गया था जो एिया में सबसे बड़ा पम्प हाउस है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह स्कीम इसलिए बनाई गई थी कि एसवाईएल का पानी जब मिलेगा तो जेएलएन कैनल में पानी डाल करके गुडगांव, महेंद्रगढ़ और भिवानी के रेतीले इलाकों को दिया जायेगा। साल्हावास में पम्प हाउस बना करके लिफ्ट स्कीम द्वारा लगभग

580 फुट उंचा पानी पहुंचाया गया है जोकि एक रिकार्ड है। इन सब कामों पर हरियाणा सरकार का बहुत ज्यादा पैसा लगा था। अगर आज एसवाईएल का पानी हमें नहीं मिलता है तो इन इलाकों के किसानों को लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसी न किसी तरह से चाहे हरियाणा सरकार इस काम को स्वयं करे, पंजाब सरकार से करवायें या भारत सरकार से करवाए यह नहर जितनी जल्दी से जल्दी तैयार की जाए उतना ही अच्छा है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि पानी आदमी की जिन्दगी में अहम चीज है। जितना अनाज आदमी के जीवन के लिए जरूरी है उतना ही पानी भी जरूरी है। किसानों के लिए तो पानी और भी जरूरी है क्योंकि हम लोग अनाज पानी से ही पैदा करते हैं जहां पानी मिलेगा वहां किसान अनाज पैदा कर सकेंगे। लेकिन जहां पानी नहीं मिलेगा वहां अनाज पैदा नहीं हो सकेगा। बिजली की पोजी उन अब तो काफी ठीक है लेकिन अनाज पैदा हो नहीं सकेगा। बिजली की सिंचाई के लिए ट्यूबवैलज लगा रखे हैं लेकिन उनसे सिंचाई करने में किसान का खर्च ज्यादा होता है। इसके अलावा वे ट्यूबवैलज से उतनी पैदावार नहीं कर सकते जितनी नहर के पानी से कर सकते हैं। अगर किसान को नहर का पानी मिल जाए तो वे ज्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं। आज भी हरियाणा का किसान बहुत ज्यादा अनाज पैदा कर रहा है। इस साल चावल का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। 75 लाख टन के करीब उत्पादन बताया जाता है। अगर हरियाणा के किसान को एसवाईएल का पानी जल्दी मिल

जाए तो ये हरियाणा के नाम को ओर उंचा कर सकते हैं। हमारे इलाके में ऐसी जमीन है जिससे बिना सिंचाई के फसल ले नहीं सकते। कुरुक्षेत्र करनाल और अम्बाला की ग्रीन बेल्ट में दूसरी फसलों के अलावा पैडी भी बहुत होती है क्योंकि उन्हें ट्यूबवैलज से भी काफी पानी मिल जाता है और नहरों से भी काफी पानी मिल जाता है। हरियाणा का जो बाकी आधे से ज्यादा हिस्सा रह जाता है उस रेतीले इलाके में केवल एसवाईएल के पानी से ही अनाज पैदा हो सकेगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, राम बिलास भार्मा जी और डा० मंगल सैन आदि सब तो यूँ कह रहे हैं कि एसवाईएल नहर जल्दी तैयार की जाए लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। 1971 में जेएलएन कैनल खुद कर बिल्कुल तैयार हो गई थी। महेंद्रगढ़ और गुडगांव जिले में सारे के सारे माईनर्ज भी तैयार कर दिए गए थे। ये सब इसलिए तैयार कर दिये गये थे कि एसवाईएल का पानी लाएंगे और हरियाणा की खु क बेल्ट को पानी देंगे। 1977 में जब ये भाई सरकार में बैठे और पंजाब के बादल साहब के साथ इनका दोस्ताना था तो क्या कभी इन्होंने यह जरूरत समझी कि चूंकि हरियाणा का आधे से ज्यादा हिस्सा खु क है इसलिए हमें जेएलएन कैनल के लिए एसवाईएल का पानी लेना चाहिए। कभी एक दिन भी इन्होंने इस बात की जरूरत नहीं समझी। क्यों नहीं समझी क्योंकि इनका प्रका । सिंह बादल के साथ भाईचारा था। अगर ये हरियाणा के हितों के लिए लड़ते, कोई बात उनसे

कहते तो दोस्ती टूट जाती। आज भी ये कहते हैं कि अकालियों की सरकार बना दी जाए जबकि वे हरियाणा का पानी रोकते हैं। (विधन) हमारी सरकार ने तो वहां अपना स्टाफ भेज रखा है मीनरी भेज रखी है। जब एसवाईएल नहर बन कर तैयार होगी तो हमारी मीनें खाली हो जाएगी और स्टाफ खाली हो जाएगा। उनसे हम और जगह काम ले सकेंगे। क्योंकि हमारे पास ज्यादा पटवारी होंगे, जूनियर इंजीनियर्स होंगे और एसडीओज होंगे।

**श्री लछमन सिंह कम्बोज:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। इन्होंने अभी कहा कि हरियाणा सरकार ने अपना स्टाफ वहां भेजा हुआ है। क्या ये बताएंगे कि वह कौन सा स्टाफ है?

**श्री उपाध्यक्ष:** यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

**चौधरी हुकम सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जेएलएन कैनल और महेंद्रगढ़ कैनल तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स को लगभग चार लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगी। आप जानते हैं कि हरियाणा का किसान एक हैक्टेयर में कितनी पैदावार करता है। आप यह भी अन्दाजा लगाएं कि वह चार लाख हैक्टेयर में कितनी पैदावार कर सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि एसवाईएल नहर की खुदाई की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। हमारी सरकार इस तरफ काफी ध्यान दे रही है। आईपीएम साहब ने यहां बताया था कि लगभग



11 किलोमीटर नहर तैयार हो गई है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एसवाईएल के बारे में कह रहा था। (विघ्न)

**चौधरी सुरेन्द्र सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, अपोजी इन के भाई आज तो इतना भाोर कर रहे हैं लेकिन जब इनकी सरकार थी और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इरीगे इन एण्ड पावर मिनिस्टर थे उस समय कैरियर चैनल के लिए चार पांच किलोमीटर जमीन एक्वायर करने की नोटिफिके इन की थी जब कि यह चैनल 112 किलोमीटर बननी थी। यहां अब ये कहते हैं कि चौधरी साहब इस कैरियर चैनल को बनाने में इन्ट्रैस्टिड नहीं है। (हंसी)

**चौधरी हुकम सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा कि आईपीएम साहब ने पिछले दिनों बताया था कि वह 11 किलोमीटर खुद कर तैयार हो चुकी है। और आगे भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बन कर तैयार हो जायेगी क्योंकि उसके लिए पहले भी पैसा दिय गया और अब दे रहे हैं। हमारी सरकार ने उस नहर को पूरा करने के लिए पूरा जोर दिया हुआ है जितनी जल्दी इसे तैयार किया जाये उतना ही अच्छा है क्योंकि हरियाणा के किसानों का इसके साथ सीधा हित जुडा हुआ है। ( गोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पहले बोलता नहीं, लेकिन जब ये बोलने की कोर्िा करते हैं तो मुझे बोलना पडता है ( गोर) मेरे से ये खफा है इसलिए मैं भी इनके साथ जुड जाता हूं।

आप जानते हैं कि हरियाणा के आधे हिस्से में जमीन के नीचे का पानी खारा है। खारा पानी होने के कारण ट्यूबवैल्ज नहीं लग सकते जिस कारण से वहां किसान अनाज पैदा करने में असमर्थ है और न ही अपने लिए कुछ धंधा कर सकते हैं।

**श्री भागी राम: \*\*\*\*\***

**श्री उपाध्यक्ष:** जो कुछ इन्होंने कहा है यह रिकार्ड में नहीं आयेगा।

**चौधरी हुकम सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि नीचे का पानी खारा होने के कारण सिंचाई नहीं हो सकती। हमारे सिंचाई के दो ही साधन हैं।

**प्रो० सम्पत सिंह: \*\*\*\*\***

**श्री उपाध्यक्ष:** यह रिकार्ड में नहीं आयेगा।

**श्री भागी राम: \*\*\*\*\***

**श्री उपाध्यक्ष:** यह भी रिकार्ड में नहीं आयेगा।

**चौधरी हुकम सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि हमारे सिंचाई के दो ही साधन हैं एक नहर और दूसरा ट्यूबवैल्ज। आधे इलाके में नीचे का पानी खारा होने के कारण ट्यूबवैल्ज से सिंचाई नहीं हो सकती। ( गोर एवं विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** मैं सारे मैम्बर साहेबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि जो मैम्बर बोल रहा है उसे बोलने दें और हाउस का डेकोरम बनाये रखे।

**शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):** डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत विरोधी पक्ष के भाईयों से प्रार्थना करूंगा कि जो भाई बोल रहा है उसे आराम से बोलने दें। जब अपोजी उन के भाई बोलते हैं तो हम कुछ नहीं बोलते। हमारे नये सदस्य बोल रहे हैं इसलिए इन्हें बोलने देना चाहिए। जब ये बोलेंगे और हम बीच में बोलेगें तो फिर ये नाराज होंगे। ( गोर)

**श्री उपाध्यक्ष:** आप बैठिए। आप भ्रान्ति से मैम्बर को सुनें ( गोर)

**चौधरी हुकम सिंह:** डिप्टी स्पीकर मैं कह रहा था कि हरियाणा प्रदे में सिंचाई के दो ही साधन हैं।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** \*\*\*\*\*

**श्री उपाध्यक्ष:** यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। कुछ भी रिकार्ड में नहीं आयेगा।

**चौधरी हुकम सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि हरियाणा में ट्यूबवैल्ज बिजली और इंजन से चलते हैं लेकिन बिजली और तेल के इंजन का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि किसान उसे बरदास्त नहीं कर सकता। दूसरे सिंचाई भी उतनी

नहीं होती जिससे नहर के पानी से हो सकती है। नहर से पैदावार भी ज्यादा होती है और सिंचाई भी ज्यादा होती है। पैदावार ज्यादा होगी तो प्रान्त खुाहाल होगा। इसलिये किसान को नहर का जितना ज्यादा पानी मिले। उतना ही अच्छा है।

जैसे किसानों को दूसरी नहरों का पानी मिलता है इसी तरीके से एसवाईएल को जो हमारा हिस्सा है वह भी मिलना चाहिए। हम अपने हिस्से के लिए पंजाब से कोई भीख नहीं मांगते न ही हम किसी दूसरे प्रदेश से अपने हिस्से के लिए भीख मांगते हैं। यह तो हमारा हक है जो हमारा हिस्सा है वह हमें मिलना चाहिए। पहले पंजाब और हरियाणा प्रान्त एक ही प्रान्त था। 1966 से पहले पंजाब और हरियाणा इक्टठे थे। 1966 के बाद पंजाब हमारा बडा भाई है और हरियाणा पंजाब का एक छोटा भाई है। यह कुदरती बात है कि जब दो भाई इक्टठे हो तो रहना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सांझा होता है। लेकिन जब अलग अलग हो जाते है तो सब कुछ सांझा बंट जाता है। पंजाब वाले एसवाईएल का पानी हमें न दे कर पाकिस्तान को बेकार में जाने दे रहे हैं। हमारा बडा भाई हमें पानी नहीं दे रहा है इसलिए हरियाणा के किसानों को बडा दुख है और तकलीफ है। वह पानी बेकार में पाकिस्तान को तो जाता रहता है लेकिन हरियाणा को नहीं मिल रहा है। इस बारे में हरियाणा सरकार बडी मजबूती के साथ लड रही है और पहले भी इसके लिये हर तरीके से कोशिश करती रही है जब कभी कोई मीटिंग हुई है या पानी

लेने की बात हुई है या इस बारे में कोई काम करने की बात आयी है तो हरियाणा सरकार ने एक परसेंट भी कोताही नहीं की है। इस बारे में हमने कोई ढील नहीं की है और हर तरीके से तन मन धन से इस काम को किया है। आगे भी उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कोर्ि । । करके यह उस पानी को हरियाणा में लायेगी। धन्यवाद। (व्यवधान एवं भाोर)

**चौधरी नर सिंह ढांडा:** डिप्टी स्पीकर साहब, एसवाईएल के बारे में कुछ बातें मैं भी सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा क्योंकि इसके साथ सारे हरियाणा के किसानों और मजदूरों का हित जुडा हुआ है। इसके बगैर किसान और मजदूर आज बेचारे भूखे की हालत में बैठे है। डिप्टी स्पीकर सर, क्या ही अच्छा होता अगर आज से डेढ साल पहले जब यह प्रस्ताव इस हाउस मे आया था इसको पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देते? यहां पर तो इस पर टाईम वेस्ट ही हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1961 में 110 करोड रूपया इस पानी के लिए पाकिस्तान को दिया था। हरियाणा को जो हिस्सा मिलना चाहिए था उसे पंजाब सरकार से दिलवाने में सेंट्रल गवर्नमेंट नाकामयाब रही है। इस बात की ओर वह ध्यान नहीं दे पायी। इस वजह से वह पानी समुद्र में बेकार जा रहा है उसके बाद 1966 में जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग हो गये तो उसके बाद खासतौर पर हरियाणा और राजस्थान इस बात की तरफ देखता रहा है कि यह पानी कब आयेगा। मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल ने भी कई बार वायदा किया कि हरियाणा के

किसानों को बहुत जल्दी ही पानी मिलेगा। 1976 में इस झगड़े का अवार्ड आया लेकिन उस अवार्ड को लागू नहीं किया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार थी तो हरियाणा और पंजाब पानी का मसला हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गये थे।

**चौधरी सुरेन्द्र सिंह:** उन्होंने तो यह ठीक नहीं किया।

**चौधरी नर सिंह ढांडा:** अब सुप्रीम कोर्ट वाली बात भी सुन लो। सुप्रीम कोर्ट से अगर इस केस का फैसला हो जाता है वह आर्डर एग्जीक्यूट हो जाता लेकिन चौधरी भजन लाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद यह कहा कि चौधरी देवीलाल ने तो प्रकाश सिंह बादल से मिलकर केस को सुप्रीम कोर्ट में टांग दिया है चौधरी भजन लाल ने उस केस को वापिस लेकर कपूरी गांव में जहां करोड़ों रूपया बरबाद हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से नहर खोदने का उदघाटन करवाया और वहां यह कहा कि यह नहर दो साल में बन कर तैयार हो जायेगी। हरियाणा के किसानों को पानी मिल जायेगा लेकिन इन सब बातों के होने के बावजूद वह मामला अभी तक अटका हुआ है अब फिर से उस केस को सुप्रीम कोर्ट में देने की बात चल रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, जब इस बात का जिक्र आता है कि इस केस को फिर सुप्रीम कोर्ट में दिया जाये तो बड़ा ही दुख होता है क्योंकि अब तक तो इसका फैसला पहले ही हो जाना था आज पंजाब में भी कांग्रेस सरकार (यानि गवर्नर राज) हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार और सेंट्र में भी कांग्रेस की

सरकार है लेकिन फिर भी वह पानी हरियाणा के लोगों को नहीं मिल रहा है।

**श्री सुरेन्द्र सिंह:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया था उस वक्त यहां पर भी जनता पार्टी की सरकार थी दिल्ली में भी जनता पार्टी की सरकार थी और पंजाब में भी अकाली दल की सरकार थी उस समय क्यों यह लोग पानी नहीं ला सके?

**चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल:** डिप्टी स्पीकर साहब, अभी चौधरी सुरेन्द्र जी यह कह रहे थे कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार पंजाब में भी थी दिल्ली में भी थी और हरियाणा में भी थी। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार 36 साल तक लगातार दोनों स्टेटस में और सैंटर में रही है लेकिन अब तक यह पानी क्यों नहीं ला सके है क्या इसका जवाब देंगे।

**चौधरी नर सिंह ढांडा:** डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा का 47-48 करोड़ रूपया पंजाब के कर्मचारी खा गये और उस पैसे का ब्याज हमें देना पड रहा है दिल्ली की सरकार बैठी हुई देख रही है। पंजाब में पिछले दिनों अब मिलिट्री भेजी गयी थी तो सैंटर को वहां पर यह नहर बनाने की कोशिश करनी चाहिये थी। इसके बगैर हरियाणा का किसान सुखी नहीं है वह दुखी बैठा है। सारे हरियाणा के किसान जब कभी इस हाउस में बजट आता है तो उस की तरफ देखते रहते हैं। बजट में यह वायदा किया

जाता है कि दो साल में यह नहर बना दी जायेगी और किसानों को पानी मिलने लगेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड रहा है कि हरियाणा के लोगों को यह सरकार बहका रही है। हरियाणा के लोगों के खून पसीने की कमाई वेस्ट की जा रही है। हम लोग देखते रहते हैं कि कब पानी यहां पर आयेगा? क्या नहर खोद दी गयी? जब हरियाणा के अन्दर नहर खोदी गयी तो काफी पैसा खर्च किया गया था वह नहर भी अब प्रतिदिन टूटती जा रही है क्योंकि इसमें पानी नहीं आ रहा है। अगर उसमें पानी नहीं आयेगा तो वह नहर टूटती ही जायेगी। अभी तो हरियाणा के पानी के हिस्से के बारे में आपतियां उठायी जा रही है। दिल्ली पंजाब और हरियाणा की सरकार इस बात की ओर ध्यान नहीं दे रही है। जहां तक इस प्रस्ताव को पास करके दिल्ली की सरकार को भेजने का सम्बन्ध है इस हाउस में जब यह प्रस्ताव आया था इन्हें चाहिये तो यह था कि उसी वक्त पास करके भेज दिया जाता। लेकिन जब वोट लेने का मौका आता है याह पैसा मांगने का मौका होता है तो यह लोग सब इसकी बात करते है जब यहां पर इस बात के लिये वोटिंग करवाई जाती है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाये तो यह कहते हैं कि नही। जब भी एसवाईएल का मामला आता है कि इससे हरियाणा को पानी मिलना चाहिये तो यह कहते है कि हां जरूर मिलना चाहिये लेकिन जब वोटिंग करवाई जाती है तो नौ कहते हैं। यह इस हाउस में कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं।



**श्री उपाध्यक्ष:** वह तो यह कहते हैं कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। इस पर जितनी ज्यादा डिस्कशन हो जाये उतनी ही अच्छी है।

**चौधरी नर सिंह ढांडा:** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सब यह चाहते हैं कि हरियाणा के लोगों को पानी जलदी से जलदी मिले तो इस प्रस्ताव को पास क्यों नहीं कर देते। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रस्ताव को फौरी पास किया जाये। यह जो लोग इसकी वोटिंग पर नो कहते हैं यह इस सरकार की बदनीयती का सबूत है। यह सरकार चाहती है कि यह पांच साल तक सरकता रहे और काम के नाम पर कुछ न किया जाये। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अन्त में इतना ही कहता हूँ कि इस प्रस्ताव को आज ही पास कर दिया जाये। जय हिन्द। (व्यवधान व भाोर).....

**चौधरी अजमत खां:** डिप्टी स्पीकर साहब, एसवाईएल का जो प्रस्ताव आया है मैं उस को बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह सच है कि एसवाईएल के साथ हरियाणा के मजदूर किसान और दूसरे लोगों की जिन्दगी का बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं कि हवा के बाद इन्सानी जिन्दगी का पानी सब से पहला हिस्सा है। इन्सान को हवा के बाद अगर पानी न मिले तो इंसान जिन्दा नहीं रह सकता। पुराने जमाने में लोग काफिले की भाव्ल में पानी की तलाश में जगह बदलते रहते थे हमारी सरकार ने इस तरफ काफी काम किया है और यही वजह है

कि 1966 में जब हरियाणा बना तो हरियाणा सरकार ने इस तरफ खासतौर पर ध्यान दिया। 1966 से पहले जब पंजाब और हरियाणा एक थे उस वक्त भी हरियाणा के अन्दर पानी की समस्या थी। जब चौधरी बंसीलाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने उस वक्त उन्होंने पानी के लिए जददोजहाद भुरू की। बीच में कुछ टाईम के लिए हमारे अपोजी इन के भाईयों की सरकार आई ये हमारे भाई बरसरे इक्तदार हुए लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं किया। आजकल के जमारने में हर आदमी अपने हक को तो बेहतर समझता है लेकिन दूसरे के हक के लिए आनाकानी करता है। जब दो भाईयों में आपस में क्ले ा बढ जाता है और आपस में भेदभाव बढ जाता है तो प्यार से समस्या हल की जा सकती है और दूसरे एक भाई को समझाकर समस्या का हल किया जा सकता है। जब यहां पर जनता पार्टी का राज था उस वक्त प्यार से यह समस्या हल हो सकती थी लेकिन हल नहीं की गई। उस वक्त हरियाणा में चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे और पंजाब में मि० बादल चीफ मिनिस्टर थे। इस पानी का फ़ैसला बडी आसानी से हो सकता था लेकिन उस वक्त इनहोंने कोई तवज्जह नहीं दी। इसके बाद उस मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। बहरहाल इस मसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट से वापिस ले लिया गया और इसकी वजह यह थी कि वहां इसके हल होने में देर लगती। इसलिए कोर्ि ा ा यह थी कि यह मसला जल्दी हल हो जाए लेकिन जिस मकसद से इस मसले को कोर्ट से लाया गया वह मकसद पूरा नहीं हो रहा है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि महेंद्रगढ, भिवानी, गुडगांव

और फरीदाबाद के वे हिस्से जहां से लोग पानी की वजह से तरस रहे हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, पहले गर्मी के मौसम में पीने के पानी के लिए लोग कच्ची कूड़ खोद लिया करते थे उंटों पर पानी लाया करते थे और दो चार मील से अपने सरों पर पानी ले आया करते थे लेकिन अब जमाना बदल रहा है और हर आदमी चाहता है कि उसके घर में नलका लगा हुआ हो। अब कच्चे कुएं खोदना और उनसे पानी लेना बहुत मुश्किल काम हो गया है। इसका कारण यह है कि अन्डर ग्राउण्ड वाटर का लैवल इतना नीचा चला गया है कि पानी बहुत गहराई तक चला गया है मेवात के इलाके में तो पानी बहुत नीचा चला गया है। एसवाईएल का पानी जब गुडगांव नहर को मिलेगा तभी लोगों को भ्रान्ति मिलेगी। आज वहां के लोग सिर्फ खेती के पानी के लिए ही नहीं तरस रहे बल्कि पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। एसवाईएल का पानी गुडगांव नहर को मिलेगा तो मेवात का सारा इलाका उस पानी से सैराब होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर यह पानी अगले पांच सात साल तक गुडगांव कैनल को नहीं मिला, गुडगांव के एरिया में अगर यह नहर नहीं निकली तो वहां के लोग भाहर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। उस इलाके में जो अन्डर ग्राउण्ड वाटर है उसका लैवल हर साल दस पन्द्रह फुट नीचे चला जा रहा है क्योंकि ट्यूबवैल्ज बढ़ते जा रहे हैं। किसान को खेती के पानी की जरूरत है नहर के पानी की जरूरत है इसलिए मेरी सरकार से गुजारि है कि एसवाईएल पर जोर दिया जाए। मैं यह नहीं कहता कि इस वक्त इसके लिए को... नहीं

की जा रही है लेकिन कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, जिससे कि हम और अच्छे ढंग से इस मामले को ज्यादा प्रैस कर सकें। इसके लिए सैन्टर्ल गवर्नमेंट पर जोर डालें या प्यार से अपने उन भाईयों को समझाएं। जो इस काम में अडचन डाल रहे हैं। और इतना ही नहीं वे हमारे भाई और भी आगे बढ़ कर इस मसले की आड में और दूसरे मसले खड़े कर रहे हैं। हम उन से प्यार के ताल्लुकात कायम करें और सैन्टर्ल गवर्नमेंट से गुजारि । करें कि वह इस नहर को जल्दी से जल्दी तैयार कराये। हमारे कुछ भाई कहते हैं कि हमने 47 करोड रूपया क्यों दे दिया जबकि वहा कुछ काम नहीं हुआ है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम यह रूपया नहीं देते तो उस सरकार को और बहाना मिल जाता हमें ज्यादा नुकसान होता। एतराज तो करना बहुत आसान होता है लेकिन किसी मसले को हल करना मुश्किल होता है। डिप्टी स्पीकर साहब, नुकताचीनी करने से यह मसला हल नहीं होगा। हम सब को मिलकर कोई ऐसा रास्ता ढूँढना चाहिए, कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए ताकि पानी का मसला हल हो सकें और इन्सानी जिन्दगी आराम से कट सके। मैं अपने उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं जो यह कहते हैं कि सरकार इस मसले को बडी आसानी से हल करने में नाकामयाब रही है लेकिन जब से पावर में थे और इस मसले को बडी आसानी से हल कर सकते थे। उस वक्त उन्होंने यह मसला हल क्यों नहीं किया। यह तो वही बात हुई जैसे कि किसी तस्वीर नवी । ने एक तस्वीर बनाई और उसको एक जगह रख दिया और उसके साथ एक पेंसिल रख दी और

लिख दिया कि जहां से कोई खराबी है वहां पर पेंसिल का नि गान लगा दिया जाए। कुछ दिन के बाद जब उस तस्वीर नवी ने उस तस्वीर को देखा तो सब जगह पेंसिल से नि गान लगे हुए थे। उसके बाद उस आदमी ने फिर उस तस्वीर को रखा और कहा कि जहां इस तस्वीर में कमी है उसको दूर कर दिया जाए लेकिन कुछ दिन के बाद जब देखा गया तो वहां पर कोई सुधार किसी ने नहीं किया। यही बात हमारे अपोजी गान के भाईयों पर लागू होती है। ये कोई सुजै गान तो देते नहीं है कि यह मसला किस तरह से हल किया जा सकता है। ये केवल नुक्ताचीनी करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, जब ये पावर में थे उस वक्त पंजाब में ये हालात नहीं थे और ये लोग आसानी से मसला हल कर सकते थे। ये हालात तो बाद में हुए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस मसले को हल करने के लिए जो रास्ता अपनाया है वह सही है लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से भी सरकार इसको हल कर सकती है वह इसको जल्दी हल करे। इसको आसानी मसला समझ कर हल किया जाए। इसमें इंसान की भलाई छिपी हुई है। अगर महेंद्रगढ़, भिवानी, गुडगांव और फरीदाबाद को पानी नहीं मिला तो वहां और मसाइल पैदा होंगे। बे तक हमारा पैदावार का टारगेट बढ़ रहा है लेकिन इसका कारण यह है कि हम नए साधन जुटाकर पैदावार बढ़ा रहे हैं। नये खेतों से दुबारा फसल ली जा रही है लेकिन जो पुराने खेत हैं जिनसे हम पैदावार लेते थे उनका पैदावार घट रही है। इसका कारण यह है कि हम किसान को वक्त पर न तो बिजली दे पा रहे

है और न पानी दे पा रहे है। हमारे पास बिजली की कमी है और पानी की भी कमी है। इस वजह से किसान को मेहनत, बीज और खाद बेकार जा रहे है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह सारे हिन्दुस्तान का मसला है। यह इन्सानी मसला है और इसके साथ लाखों आदमियों बच्चों और औरतों की जिन्दगी वाबस्ता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सरकार से अपील करता हूं कि इस मसले पर और ज्यादा जोर दिया जाए और पैसे की वजह से इस काम में कोई अडचन नहीं आनी चाहिए। अगर वे पैसा मांगते है तो वह दे दिया जाए वरना उनको बहाना मिल जाएगा कि पैसे न देने के कारण काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी मेरी सुजै उन यह है कि अगर सैन्टर्ल गवर्नमेंट इस बात को मान जाये कि हमारे औफिसर्ज वहां पर डिप्यूट कर दिए जाए तो यह अच्छा होगा। अफसर हमारे यहां काम कर रहे हैं वे काम में डिले कर सकते है। इसलिए मेरा कहना हे कि हरियाणा के अफसर और अगर सैन्टर्ल गवर्नमेंट अपने अफसर भी भामिल करना चाहे तो वे भी भामिल किए जा सकते है और उनके थू काम करवाया जाए। अगर वहां पर लेबर की कमी हो तो वह भी यहां से ले जाई जा सकती है। इन लफजों के साथ मैं आपका भुक्रिया अदा करता हूं।

**चौधरी प्रभू राम:** आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका भुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सब से पहले मैं अपनी सरकार से यह दरखास्त करूंगा कि मेरे हल्का सढौरा में पीने के पानी की बडी भारी किल्लत है।

इसलिये यहां पर हर तरीके से पानी की किल्लत को दूर किया जाए। ट्यूबवैल्ज भी लगाए जाएं। पहले भी सरकार की तरफ से इस तरह की मदद की गयी है। वाटर सप्लाई की तरफ खास तवज्जो सरकार को देना चाहिए ताकि लोगों को किसी किस्म की दिक्कत न हो और उनको पीने का पानी मुहैया होता रहे। एक बार भोली वाला गांव में अग लग गई लेकिन वहां पर आग बुझाने के लिए पानी नहीं था। तालाब सूखे पड़े थे। इसलिये इस समस्या को दूर किया जाए और ट्यूबवैल्ज के लिए स्पै 11 बिजली का प्रावधान करके पानी की सप्लाई को बहाल किया जाए। गर्मियों में वहां पर पानी न होने की वजह से मवेशी जो हैं वे हरिद्वार चले जाते हैं। और बरसात आने तक वे वहां पर ही रहते हैं इससे लोगों के मन में काफी रोश और दिक्कत होती है। इसलिये सरकार को मेरे इस ब्यान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। वहां के लोग पीने के पानी न मिलने के कारण बड़े ही परेशान हैं। वहां के जो तालाब सूखे पड़ें उनको भरवाया जाए।

दूसरी बात मैं अपने हल्के की सडकों के बारे में कहूंगा कि जो सडकें वहां पर नहीं बनी हैं उनको जल्दी ही बनाकर अप्रोच रोडज से मिलाया जाए। एक सडक नारायणगढ गदौली रोड है वहां से वेलवाला का केवल एक किलोमीटर का टुकडा है दूसरी गोपाल मोचन धनौरा रोड से एहड वाला गांव में हरिजन, चौपाल तक की सडक भी बनने वाली है। इन अधूरी सडकों के काम को सरकार भीघ्र ही पूरा करे ताकि किसानों को

ओर दूसरे लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इसलिए इन गांवों को लिंक रोड से मिलाया जाए।

इससे अगला प्वायंट में अपनी सरकार के सामने यह रखना चाहता हूं कि मेरे हल्के में बहुत से गरीब लोग बसते हैं। जैसे हरिजन किसान और दूसरे गरीब लोग जिनके रोजी कमाने के अपने कोई साधन नहीं है। वे गरीब फूंस का मकान बनाकर अपना निर्वाह करते हैं। सरकार की तरफ से जो 2000 रूपये की मकान बनाने के लिए सहायता दी जा रही है वह बहुत थोड़ी है। अगर सरकार इसको दो हजार से बढ़ा कर 5000 तक कर दे तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ न कुछ राहत तो गरीब आदमी को मिल ही जायेगी?

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे अगली बात में पुलों के बारे में कहना चाहूंगा कि पावनी सरावां रोड पर चंटग नदी का पुल, सढौरा से जाते हुए गाड के इलाके मिरजा पुर रोड पर सढौरा नदी का पुल है। इनके उपर पुल बनाने का काम बीच में ही पडा है हालांकि इन दोनों पुलो को बनाने के लिये चीफ मिनिस्टर साहब वायदा भी करके आये थे। इसलिये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों पुलों का निर्माण जल्दी से जल्दी कर दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के सढौरा के साथ वाले इलाके कि नपुरा, हल्का छछरौली में हाईडल प्रोजेक्ट की



कालोनी बनी हुई है। वहां पर वाटर सप्लाई का प्रोग्राम काफी अच्छा है ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं। लेकिन इस इलाके में नलके, ट्यूबवैल्ज और तालाब पूरी तरह से सूख गये हैं मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इलाके में भी इसी तरह से हाइडल प्रोजेक्ट कालोनी जैसी सुविधाएं दी जायें ताकि लोगों को पानी की दिक्कत न रहे। दूसरी बात मैं अपनी सरकार के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि मेरे हल्के में नहर जमनगर्बी बनार से पानी आबपा की के लिये सप्लाई होता है। और उस पानी की सरकार ने पक्की नाकेबन्दी कर रखी है जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना हैस कि मेरे हल्के को खुला पानी दिया जाए क्योंकि हमने इस नहर में आने वाली जमीन का कोई हरजाना नहीं लिया कोई कीमत नहीं ली। इसलिये हमें इस नहर का पूरा फायदा होना चाहिये बहुत से गांव ऐसे है जिनको पानी न होने की वजह से काफी किल्लत है। इस नहर के कारण सरकार को काफी लाभ भी होता है और लोगों से आबयाना भी काफी मिलता है तो इसलिये सरकार को यह कोर्ि । । करनी चाहिये कि लोगों को भी इस नहर का पानी पूरी मात्रा में मिलता रहे।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक दो बातें कहकर मैं अपना स्था लूंगा। यहां पर ये भाई बैठे इलैक्शन के बारे में बातें करते हैं। इलैक्शन का हार इन्होंने देख ही लिया कि जनता के कितने भारी बहुमत से हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जीता कर

भेजा है। मैं इनको इलैक्ट्रान की बात भी बताता हूँ। मेरा हल्का सढौरा है मैं कांग्रेस की टिकट से जीत कर आया हूँ। जिस वक्त कांउटिंग हो रही थी तो चौधरी देवीलाल जी का नाम लेकर एक घनसिंह नायब तहसीलदार वहां से आया और रिटर्निंग अफसर श्री पुरी को अपने साथ कुछ कहकर बाहर ले गया। चौधरी सूरजभान जोकि एमपी थे वे भी उस वक्त उनके साथ थे। उस वक्त कांउटिंग के हिसाब से मैं 7 वोटों से जीत रहा था केवल रिजल्ट ही बताना था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ इन्होंने मिल मिलाकर चौधरी भागमल को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया हम हैरान रह गये कि हम तो पहले 7 वोटों से जीत रहे हैं ये क्या हो गया। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि आप रि-कांउटिंग के लिये दरखास्त दे दो। हमने दरखास्त दे दी तो उस वक्त सूरजभान एमपी कहने लगा कि कोई रि-कांउटिंग नहीं होगी। उसके बाद जो आबजर्वर उस तीन इलाकों के लगे हुए थे वे आ गये, हम उन से बोले कि हम पहले 7 वोटों से जीत रहे थे और अब हम 5 वोटों से हरवा दिये गये हैं। रि-कांउटिंग होनी चाहिये। आबजर्वर साहब ने कहा कि रि-कांउटिंग करो। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि रिटर्निंग अफसर मैं हूँ यह सारी जिम्मेवारी मेरी है उन्होंने कहा कि प्रभूराम जी रिकाउटिंग के लिए कह रहे थे और हम कोई दो बूथ ले लेते हैं उनकी कांउटिंग कर देते है। हमने दो बूथों के नाम बताएं उनकी काउंटिंग हुई और हमारे दो वोट निकले उसके बाद हमने दो बूथ और दिये। वहां से भी हमारी दो वोटें निकली और एक कम्युनिस्ट पार्टी की। तो उस पपर आबजर्वर ने कहा कि

फौरन इनका नाम रिकमेंड करो और फिर भी पता नहीं क्या किया गया हमारी वोटों को केन्सल करके, उनकी तरफ का फैसला दे दिया और चौधरी भागमल को इलैक्टड घोशित कर दिया गया। इसके बाद फौरन मैं दिल्ली इलैक्ट्रान आफिस में भाग, हाई कोर्ट में अपील की और अब आप लोगों के सामने यह सारी बातें हैं कि हाईकोर्ट ने भी मेरे हक में फैसला दिया है। मेरी इस सरकार से रिक्वेस्ट है कि सूरजभान को तो अम्बाला की जनता ने सजा दे ही दी है और अब सरकार नायब तहसीलदार और रिटर्निंग अफसर श्री पुरी के खिलाफ एक न ले और उचित कार्यवाही करे और पूछे कि क्यों इन लोगों ने काफी हेराफेरी दिखायी है और चौधरी भागमल जी से ढाई साल का भता वगैरह भी वापिस ले क्योंकि उस सरकारी पैसे पर उनका कोई हक नहीं था। यह कार्यवाही भीष्म से भीष्म की जानी चाहिये बस मैं इतना ही कहता हुआ अपनी बात को खत्म करता हुआ अपना स्था लेता हूँ। जयहिन्द

**शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):** उपाध्यक्ष महोदय आज जो नान आफिशियल रेजोल्यूशन जोकि एसवाईएल से सम्बन्धित है यहां पर जेरे गौर है इस पर बोलते हुए हमारे विरोधी दल के भाइयों ने कहा कि जो एसवाईएल नहर है यह जल्दी से जल्दी खुदे और पंजाब सरकार ने इसे खोदने में जो देरी की है और अब जो कास्ट आफ प्रोडक्शन बढी है वह सारा खर्चा पंजाब सरकार से लिया जाए। इसी विचारधारा को लेकर सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार यहां पर व्यक्त किये

हैं। यह एसवाईएल हरियाणा की लाईफ लाईन हो गयी है और यह हरियाणा के किसानों के लिये जिन्दगी और मौत का सवाल हो गयी है क्योंकि आज जो हरियाणा में कुल पानी आ रहा है वह 10 हजार क्यूबिक आ रहा है और वैस्टर्न यमुना कैनल का और इसके अलावा जो ट्यूबवैल्ज है उनको मिलाकर जितना पानी आज हरियाणा की धरती को मिलना चाहिये वह एसवाईएल से नहीं मिल रहा है। इसलिये यह फैसला हुआ कि सारा जो टोटल पानी है उसमें 4.22 पंजाब को, 3.50 एमएएफ हरियाणा को, 8.60 एमएएफ राजस्थान को, 0.20 दिल्ली को और 0.65 जम्मू और कश्मीर राज्य को मिलेगा। तो इस तरह से रावी ब्यास का पानी 17.17 एमएएफ वर्क आउट किया गया। इसमें जो पानी हरियाणा को आना था उसके लिए हरियाणा ने काफी साल पहले आगे पानी लगाने के लिए अपने एरिया में नहरें बना ली हैं लेकिन जो पंजाब का 112 किलोमीटर का पोरा है उसमें यह नहर नहीं बन सकी है। एसवाईएल में टोटल 10150 क्यूबिक पानी आना है जिसमें से 1400 क्यूबिक तो पंजाब में आन्नद पुर हाईडल प्रोजेक्ट के लिए होगा। 1350 क्यूबिक रोपड थर्मल प्लांट के लिए होगा और 900 क्यूबिक पंजाब के एरिया की जमीन की सिंचाई के लिए होगा। इस तरह से एसवाईएल में जो पानी आना है उसमें से 3650 क्यूबिक पानी तो पंजाब के लिए ही है और बाकी 6500 क्यूबिक पानी हरियाणा की जमीन के लिए आना है। इनका जो कास्ट है उसका अन्दाजा अक्टूबर 1981 में 2180 मिलियन लगाया गया था जो अब बढ़ कर जून 1984 में 2560 मिलियन हो गया है जो यह

फर्क है वह पंजाब गवर्नमेंट को देना चाहिए क्योंकि एसवाईएल की खुदाई का काम पंजाब गवर्नमेंट करवा रही है। इसलिये रैजोल्यूशन के मुताबिक इसे हरियाणा या सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों वहन करे। इस नहर के काम पर जो टोटल स्टाफ लगा हुआ है वह पंजाब का ही लगा हुआ है। स्टाफ के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां 5 तो चीफ इंजीनियर्स हैं, 19 एसइज हैं 81 एक्सीयंज 293 एसडीओज और 786 जेईज लगाये हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आगे जो लेबर है वह हजारों में है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय इस तरह से जो एसवाईएल का ओवर हैड एक्सपेंडीचर चल रहा है वह सारा पंजाब गवर्नमेंट के हिसाब से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां कि हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल है और जिससे हरियाणा की कम से कम 100 करोड़ रूपए की फसल ज्यादा हो सकती है उसके न बनने से यह हमारा नुकसान हो रहा है। यदि यह नहर बन जाए तो हर साल हमारा सौ करोड़ रूपए का फायदा हो सकता है। इससे हमारी इकानोमी और किसान की हालत बहुत सुधर सकती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे राजनैतिक कारण हैं। यदि हम इसकी बैंक ग्रांउड में जाएं तो पता चलेगा। जब यह फैसला किया गया कि इतना इतना पानी दिया जाएगा तो उसके बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। इसी बात को लेकर उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने पंजाब सरकार के पास एक करोड़ रूपया जमा करवाया। उन्होंने बताया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने उनसे वायदा किया है कि मीटिंग

करके इसकी खुदाई का काम भुरू करेंगे। लेकिन वह काम किस वजह से नहीं हुआ वह तो हमारे विरोधी भाई अच्छी तरह से जानते हैं और बता सकते हैं। उनका आपस में भाई चारा था इसलिये उन्होंने हरियाणा या हरियाणा के किसानों की तकलीफ के बारे में नहीं सोचा। जब 1980 में कांग्रेस की सरकार आई तो श्रीमति गांधी ने अक्टूबर 1981 में कपूरी गांव में इस नहर की खुदाई का उदघाटन किया और वहां पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री तथा दूसरे मंत्री हाजिर थे। उस समय यह फैसला हुआ कि यहां से खुदाई भुरू की जाए और उंचाई की तरफ यानि पंजाब की तरफ यह काम आगे बढ़ता रहे। उसी समय अकालियों ने मूवमेंट छेडी कि यह खुदाई नहीं होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने 1981 में गिरफ्तारियां दी और इसकी खिलाफत की। इसको लेकर आगे उनका धर्म युद्ध चला और वह सारा सिलसिला अब तक कायम है। इसके पीछे कौन है जो एसवाईएल को खुदने नहीं देना चाहते। अकाली पार्टी चाहती है कि पंजाब में एसवाईएल न खुदे जबकि राबी ब्यास का पानी पाकिस्तान को जा रहा है। उनकी मदद ये हमारे विरोधी भाई कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने खुद कहा कि पंजाब में अकालियों की सरकार होनी चाहिए। यह बात उन्होंने यहां हाउस में कही थी। उपाध्यक्ष महोदय, अगर पंजाब में अकालियों की सरकार होगी तो एसवाईएल के खुदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि अकाली तो आज भी धर्म युद्ध का नाम लेकर हमारे किसानों के खिलाफ इस ढंग से चल रहे हैं जबकि आज उनकी सरकार नहीं है।

**चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल:** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ये कहते हैं कि अकालियों की सरकार होगी तो नहर नहीं खुदेगी। मैं जानना चाहता हू कि 1980 से इनकी सरकार चल रही है इस दौरान क्यों नहीं खुदी। तीन चार साल पंजाब में मुख्यमंत्री सरदार दरबारा सिंह रहे। ( गोर)

**श्री उपाध्यक्ष:** आप कृपा बैठिये।

**प्रो० सम्पत सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है मंत्री जी की खुद की कलैक्टिव रिसपौसिबिलिटी है ये खुद सरकार में है। इनकी तीन साल से अपनी सरकार चल रही है और उससे पहले भी चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री थे। इस नहर की खुदाई का उदघाटन खुद प्रधान मंत्री करती है और वहां पर इनके मुख्यमंत्री जी भी जाते हैं और कहते हैं कि दो साल में यह नहर खुद कर तैयार हो जाएगी। अब कहते हैं कि 1987 में जाकर तैयार होगी। केंद्र की सरकार भी इनकी है और उसके नीचे भी इनकी सरकारें हैं। आज तो कोई अकाली सरकार नहीं है। वैसे तो गलत बातें कहने का क्या फायदा है। दो साल में नहरों में कोई आ गई है। ये लोग गांवों में तो जा नहीं सकते और यहां पर उल्टे सीधे भाषण दे रहे हैं। आप इस रैजोल्यूशन को पास क्यों नहीं करते? ( गोर)

**श्री जगदीश नेहरा:** उपाध्यक्ष महोदय, एसवाईएल आज का मसला नहीं है बल्कि 1977 में जब हमारे विरोधी भाई सत्ता में

थे उस समय भी यह मसला था। खुद चौधरी देवी लाल ने एक करोड़ रूपया पंजाब सरकार के पास जमा करवाया। उस समय सरदार प्रकाश सिंह बादल और चौधरी देवीलाल दोनों पंजाब और हरियाणा के अलग अलग मुख्यमंत्री थे। ( गोर)

12.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, इनको अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा। जिस समय इनको बोलने का मौका मिलेगा, उस समय ये कुछ भी बात कह सकते हैं। इनको इस तरह से बीच में नहीं बोलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, 1977 से लेकर 1979 तक दो साल छह दिन चौधरी देवी लाल जी की सरकार रही। उन्होंने एसवाईएल कैनाल को मुकम्मल करवाने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की।

**चौधरी नर सिंह ढांडा:** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। इन्होंने यह कहा है कि दो साल 6 दिन चौधरी देवीलाल जी का राज रहा है। मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि चौधरी देवीलाल ने इस नहर का मुकम्मल करवाने के लिए पैसा भी जमा करवा दिया था। \*\*\*\* ( गोर एवं विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** इन्होंने जो 1961 वाली बात की है वह रिकार्ड न की जाए।

**चौधरी कुलबीर सिंह मलिक:** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है।



**श्री उपाध्यक्ष:** आप इस तरह से उनको क्यों इन्टरप्ट कर रहे हैं। अब कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं होगा। आप कृपया बैठ जाएं। ( गोर एवं विघ्न)

**श्री जगदी 1 नेहरा:** डिप्टी स्पीकर साहब, जो वास्तविकता है यदि वह हम कह दें तो मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों को सुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जो भी बात कहूंगा वह सही कहूंगा कोई गलत बात नहीं कहूंगा। मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों को इस तरह से बीच में इन्टरप्ट नहीं करना चाहिए। आपको भी बोलने के समय मिलेगा आपकी जो मर्जी आए वह बात करें। उपाध्यक्ष महोदय, 1977 से लेकर 1979 तक 2 साल 6 दिन तक इनका राज रहा और चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री रहे उस समय उन्होंने एसवाईएल कैनाल को मुकम्मल करवाने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की। उन्होंने इस चैनल को खुदवाने के लिए केवल एक करोड रूपया पंजाब सरकार के पास जमा करवाया था इसके अलावा न उन्होंने इसके लिए कोई लैंड एक्वायर करने की कार्यवाही के लिए पंजाब सरकार को कहा और न ही उन्होंने कोई दूसरी कार्यवाही की। जितनी भी इस चैनल को मुकम्मल करवाने के लिए कार्यवाही हुई है वह उनके राज के बाद हुई है। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए इस नहर को मुकम्मल करवाने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की। ( गोर एवं विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** आप इस तरह से इनको बीच में इन्टरप्ट क्यों कर रहे हैं आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। ( गोर)

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। नेहरा साहब कुछ भी कहें लेकिन वे इस बात को डिसटॉर्ट न करे कि चौधरी देवीलाल जी के जमाने में एसवाईएल नहर के लिए पंजाब के एरिया में लैंड एक्वायर नहीं हुई थी। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि उनके जमाने में एसवाईएल नहर की खुदाई के लिए बाकायदा पैसा दिया गया था और 7 किलोमीटर की लैंग्थ में जमीन भी एक्वायर हुई थी। इसको आप डिसटॉर्ट न करें।

**श्री जगदी । नेहरा:** उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने एसवाईएल नहर खुदवाने के लिए पंजाब सरकार को एक करोड़ रूपया दे दिया था। पैसा जमा करवाने के अलावा उनका यह फर्ज बनता था कि उस समय वे किसानों की भलाई के लिए एसवाईएल चैनल को मुकम्मल करवाने के लिए कोई न कोई कार्यवाही करते। समय वे हरियाणा के किसानों की भलाई के लिए बड़े उत्सुक होते थे। और हरियाणा के किसानों को सुविधाएं देने के लिए काफी लालायित होते थे इसलिए उनको यह चैनल मुकम्मल करवाने के लिए कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिए थी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उस समय पंजाब में अकाली पार्टी की सरकार थी और वे चौधरी देवीलाल जी के साथ मिल कर सुप्रीम कोर्ट में गए ताकि यह मामला 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लटका रहे और एसवाईएल कैनल न बने। यह इनकी अकाली पार्टी के साथ

गांठसांठ थी। चौधरी देवीलाल जी और अकाली पार्टी मिल कर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ( गोर एवं विघ्न)

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है इन्होंने अब एक और नई बात कह दी। इनको इतनी बेसलैस बात नहीं कहनी चाहिए। \*\*\*\*\* ( गोर एवं विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** कैबिनेट में लेने वाली बात रिकार्ड न की जाए। ( गोर एवं विघ्न)

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, \*\*\*\*\* ( गोर एवं विघ्न)

**श्री जगदी ा नेहरा:** उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही है। मैं उसकी तो ताइद कर रहा हूं कि उन्होंने उस समय एक करोड रूपया दिया था। चौधरी देवीलाल जी अकालियों के साथ मिल करके सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उस समय अकाली यह चाहते थे कि यह मसला 10 साल में सुप्रीम कोर्ट में लटका रहे। \*\*\*\*\* ( गोर एवं विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** नेहरा साहब इस बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि कैबिनेट वाली बात रिकार्ड न की जाए। ( गोर एवं विघ्न)

**लोक निर्माण मंत्री (चौधरी अमर सिंह):** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। डिप्टी स्पीकर साहब,

एसवाईएल नहर हरियाणा की लाईफ लाईन का सवाल है और आप देख रहे हैं कि अपोजी इन के माननीय सदस्य बीच में किस तरह से टोकाटाकी कर रहे हैं इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। मेरे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूँ कि 1961 मैं तो हरियाणा बना ही नहीं था। हरियाणा 1966 में बना है। इतना जरूर मसला डिस्कस हो रहा है इनको इस तरह से बीच में टोकाटाकी नहीं करनी चाहिए। ( गोर)

**चौधरी नर सिंह ढांडा:** डिप्टी स्पीकर साहब, इनकी यह बात ठीक है कि हरियाणा 1966 में बना था। .....  
..... ( गोर एवं विघ्न)

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है मैं चौधरी अमर सिंह जी की सेवा में एक भोर अर्ज करना चाहता हूँ..... ( गोर)

**श्री उपाध्यक्ष:** मेरी इजाजत के बगैर जो कुछ बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए। ( गोर एवं विघ्न)

**चौधरी अमर सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, .....  
( गोर एवं विघ्न)

**प्रो० सम्पत सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, .....  
( गोर एवं विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।  
( तोर)

**श्री अध्यक्ष:** आप पर्सनल बातों को छोड़िए। नेहरा साहब, आप अपनी बात कहिये।

**श्री जगदी ा नेहरा:** स्पीकर साहब, 1977-79 के दौरान विरोधी पक्ष के भाइयों ने अकाली भाईयों के साथ मिलकर इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया। इनके दिलों में मैलापन था जिसकी वजह से यह केस कोर्ट में गया। ये अकाली भाईयों को ना खु ा करना नहीं चाहते थे और न ही उनका विरोध कर सकते थे इसलिए उस दौरान कोई कार्यवाही नहीं की। सन 1980 में जब दुबारा कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो इस पर काम फिर भुरु हुआ। जब काम भुरु हुआ तो अकाली पार्टी ने विरोध करना भुरु कर दिया कि पंजाब में एसवाईएल को नहीं खुदने देंगे। उन्होंने इस बात पर मोर्चा लगाकर गिरफ्तारी दी और जो आन्दोलन एक एसवाईएल नहर न खोदने के बारे में चला था वह बाद में धर्मयुद्ध में बदल गया। उसके बाद जो हालात हुए और यह आन्दोलन जिस चरम सीमा पर पहुंचा वह सब को पता है। इस आन्दोलन ने श्रीमति इंदिरा गांधी को भी मौत के मुंह में ले लिया। जब पिछली विधान सभा में चौधरी देवी लाल जी आए थे तो उन्होंने खुद यहां पर कहा था कि पंजाब के अन्दर अकाली पार्टी की सरकार होनी चाहिये। ये अकाली पार्टी को प्लीड करते हैं कि उनकी सरकार हो। इसका मतलब यह है कि हमारे विरोधी

पक्ष के भाई अकालियों से सांठ गांठ कर रहे हैं कि एसवाईएल न खुदे। इस नहर के न खुदने से किसानों को नुकसान हो रहा है उनकी जीवन तबाह हो रहा है। इस साल तो बारिश भी नहीं हुई जिस कारण किसानों को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। यदि एसवाईएल नहर खुद कर तैयार हो जाती है तो इससे पंजाब को भी फायदा होगा। पंजाब का जो आन्नदपुर हाईडल प्रोजेक्ट या रोपड का थर्मल प्लांट है उसका संबंध भी इस नहर से है। यदि यह नहर चालू हो जाती है तो इन प्रोजेक्ट्स से पंजाब वाले अपने लोगों के लिये बिजली पैदा कर सकेंगे। दूसरे वे इस पानी को अपनी सिंचाई के लिए भी उपयोग में ला सकेंगे। अकाली भाई कांग्रेस पार्टी वालों की कोई बात नहीं मानते। यदि यह नहर बन जाती है तो पंजाब को भी फायदा होगा लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जो विरोधी पक्ष के भाई हैं उन्होंने कभी भी एक लफज अकाली भाइयों को नहीं कहा कि इस नहर को खुद लेने दो। आज पानी हरियाणा में आने की बजाये पाकिस्तान को जा रहा है। दूसरे पंजाब के अन्दर इस पानी की वजह से सेम हो रही है। विरोधी पक्ष के भाइयों ने या जो इनके लीडर हैं इनहोंने कभी भी प्रेस में स्टेटमेंट नहीं दी कि अकाली वार्ता की टेबल पर आएँ और इस समस्या को सुलझाएँ। इन्होंने कभी उनको नहीं कहा कि इस पानी से हरियाणा के लोगों के हित जुड़े हुए हैं। (विघ्न)

**श्री भागी राम:** सरकार किसकी है?

**श्री मनफूल सिंह:** मंत्री जी काफी देर से यही बोल रहे हैं कि अकालियों की सरकार ने यह किया, अकालियों की सरकार ने वह किया। अब पीछे तो अकालियों की सरकार नहीं थी अभी भी वहां पर राष्ट्रपति भासन लागू है। ..... आपको इस बात के बारे में पता ही है। अकालियों का नाम बदनाम किया जा रहा है। यह गलत बात है। यह इनको नहीं कहना चाहिए। ( गोर) यह बडा सीरियस मामला है। ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** आप बैठ जाइये।

**श्री जगदी ा नेहरा:** स्पीकर साहब, यदि हमारे विरोधी पक्ष के भाई चाहते हैं कि यह नहर बने और यहां के किसानों को पानी मिले ताकि उनकी जिन्दगी बेहतर हो तो उन्होंने सीरियस होकर अकालियों से कहना चाहिए कि एसवाईएल नहर की खुदाई का माहौल तैयार होने दें। ये उनको कहें कि नहर की तो खुदाई होने दो बाकी मसले बाद में हल होते रहेंगे। इन्होंने उनको कहना चाहिए कि आंदोलन को छोडकर कम्परोमाईज करें। इनके जितने भी लीडर हैं वे कहते कुछ हैं और करते कुछ है। अब मैं चौधरी देवीलाल जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। (विघ्न)

**श्री भागी राम:** इनको तो सोते समय भी चौधरी देवी लाल जी ही नहर आते हैं। (विघ्न)

**श्री जगदी ा नेहरा:** चौधरी देवीलाल जीको भी तो मैं ही नजर आता हूं।

**श्री भागी राम:** उनका नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है? आप तो शिक्षा मंत्री हैं। (विघ्न)

**श्री जगदीश नेहरा:** मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी का नाम नहीं ले रहा। उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वे मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

**श्री मनफूल सिंह:** स्पीकर साहब, मैं इन्हें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इमारत बनाने वाले इमानत बना बहरे तला तल पर, किनारों पर मत बना, अकसर डूब जाते हैं।

**श्री जगदीश नेहरा:** किनारे की बात तो विपक्ष वाले भाई ही करते हैं कांग्रेस पार्टी तो नींव की गहराई में जाकर मकान बनाती है। स्पीकर साहब, मैं चौधरी देवी लाल जी के बारे में यह कह रहा था। (गोर एवं विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** आप चौधरी देवी लाल जी का नाम भी सुनना नहीं चाहते।

**श्री भागी राम:** इनको तो चौधरी देवी लाल का भूत नजर आता है। (हंसी) मैं आपको बता देता हूँ कि अब की बार चौधरी देवी लाल जी ने रोड़ी हल्के से चुनाव लड़ना है अब की बार चौधरी देवी लाल आपकी जमानत जब्त करवायेंगे। (विघ्न) लगता है कि आपको अमृतसर हस्पताल में दाखिल कराना पड़ेगा। (हंसी)



**श्री जगदी १ नेहरा:** स्पीकर साहब, जब 1982 में असैम्बली बैठी थी तो मैंने उस समय इनके नेता को कहा था कि आप मेहम से इस्तीफा दे दें और मैं रोडी से इस्तीफा दे देता हूँ। दोनों के इस्तीफा देने के बाद फिर हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद पता लग जायेगा कि कौन कितने पानी में है। ( गोर एवं विघ्न)

**श्री भागी राम:** मैं आज भी छाती पर हाथ रखकर कहता हूँ कि आप अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड कर दिखा दें। अब की बार जो चुनाव होंगे। उन में आप लोगों को पूरी तरह से फिट कर देंगे।

**श्री जगदी १ नेहरा:** मैं यही तो चाहता हूँ कि वहीं आये उनको पूरी तरह से फिट कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह का नाम लूंगा। (व्यवधान) भायद चौधरी वीरेन्द्र सिंह का नाम भी ये सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) स्पीकर साहब, अगर चौधरी वीरेन्द्र सिंह का नाम भी ये सुनना नहीं चाहते तो मैं चौधरी चरण सिंह का नाम ले लेता हूँ। एसवाईएल से संबंधित जितने भी आदमी है मैं उनका नाम लेना जरूरी समझता हूँ। चौधरी चरण सिंह ने अकालियों के बारे में जो स्टैंड लिया था उसकी सारे मुलक में प्र ांसा की थी। सब ने कहा था कि अच्छा स्टैंड लिया था लेकिन जब हरियाणा और पंजाब की बात आई थी उस वक्त चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने जो स्टैंड लिया था वह बहुत गलत लिया था। आप भी अकालियों के साथ इनका गठबन्धन है इनका भाईचारा है इनका मेल मिलाप है और प्यार है। जब इतना

प्यार है तो जाएं और अकालियों से कहें कि वे एसवाईएल की खुदाई कम्पलीट होने दे और हरियाणा के पानी के रास्ते में कोई अडचन न अडाये। स्पीकर साहब, ये किसान के बड़े हमदर्द बनते हैं। जब भाखडा मेन लाईन टूटी थी तो सिवाये श्रीमति चन्द्रावती के तमाम विरोधी सदस्यों में से कोई भी वहां नहीं गया और न ही कुछ कहा। इसलिए विरोधी पक्ष के सदस्य एसवाईएल के लिए रेजोल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि यह मामला पक्ष और विपक्ष का नहीं है। सारे हरियाणा मामला है और सारे भाई यही चाहते हैं कि हमारा हिस्सा 6500 क्यूसिक है और 3650 क्यूसिक पंजाब का हिस्सा है। हमारा सारा पानी हरियाणा में आये और हरियाणा की धरती, जिसमें विशेषकर महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, फरीदाबाद और गुडगांव जिलों का एरिया आता है की सिंचाई हो ताकि किसान की हालत सुधरे। मैं यही दुर्खास्त करूंगा कि एसवाईएल पर जो वहां खर्चा हो रहा है उसको हरियाणा सरकार अपने जिम्मे ले ले। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द

अध्यक्ष द्वारा घोषणा—

पंजाब यूनिवर्सिटी सैनिट के लिए इलैक्टन सम्बन्धी

**Mr. Speaker:** Hon. Members, Shri Kanwal Singh, MLA has withdrawn his name for election to the Senate of the

Punjab University. Therefore the time of withdrawal may be treated to have been extended till day.

After this withdrawal only two members are left, namely Shri Inderjit Singh and Shri Ram Bilas Sharma, for two vacancies. They may therefore be deemed to have been declared elected to serve on the Senate of the said University.

**Shri Verender Singh:** You have granted the time for extension, Sir. Thank you for it.

### गैर सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

**डा० भीम सिंह दहिया:** स्पीकर साहब, सदन के सामने सर्वश्री फतेहचन्द और देवीदास की तरफ से जो प्रस्ताव आया है कि एसवाईएल की कंस्ट्रकान का काम पंजाब सरकार के हाथों से ले लिया जाए और या हरियाणा सरकार को दे दिया जाए या किसी सैन्ट्रल एजेंसी को दे दिया जाए यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। यह प्रस्ताव सदन के सामने कई बार आ चुका है पता नहीं सरकार को क्या आपत्ति है क्यों नहीं इसको पास किया जाता। बार बार ट्रेजरी बेंचिज की तरफ से यही सुनने को मिलता है कि अकालियों ने आन्दोलन कर दिया, उग्रवादियों या अकालियों ने एसवाईएल को नहीं बनने दिया। ये हमारे उपर भी इल्जाम लगाते हैं कि विरोधी पक्ष जो हरियाणा का है उसके अकालियों से अच्छे सम्बन्ध है और विरोधी पक्ष इस सम्बन्ध को हरियाणा के हित में इस्तेमाल नहीं करता। ये हम से चाहते हैं कि उनको विरोधी पक्ष समझाये कि वे इस नहर को बनने दें। स्पीकर

साहब, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि भारत सरकार इस मामले में बेबस क्यों हो गई? क्यों नहीं ये खुदवाई का काम कम्प्लीट करवा सके? इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारे रहम पर है कि हम अकालियों को कहें कि नहर खुदने दो, तब भायद खुद जाए। मुझे इसमें तथ्य नजर नहीं आता। इसका असल कारण और है जो ट्रेजरी बैंचिज के भाई कहना नहीं चाहते। स्पीकर साहब, मुझे जो पता चली है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमने सुना है कि 20 लाख रूपया एक कंट्रैक्टर का बैलेंस में पडा हुआ है। इस रकम को अदा नहीं किया जा रहा। ऐसे ही और भी केसिज है जिनकी पैमेंट नहीं हुई है। बहरहाल जब तक काम करने वाले आदमी को पैमेंट नहीं होगी। कंट्रैक्टर की रकम अदा नहीं की जाएगी तो वह काम कैसे करेगा? लोग काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं मीनरी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। स्पीकर साहब, यह भी सुनने में आया है कि इस सिलसिले में पीछे भारत सरकार ने जो मीटिंग बुलाई थी उस मीटिंग में भारत सरकार ने कहा था कि हरियाणा हर महीने 5 करोड रूपया देगा और पंजाब 1 करोड रूपया देगा मैंने सुना है कि 47 करोड रूपया बैलेंस है जो हरियाणा सरकार ने देना है। हरियाणा सरकार को रकम की पेमेंट कर देनी चाहिए थी। लेकिन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई इसके कारणों पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रकाश नहीं डाला गया। हरियाणा सरकार बार बार एक ही रट लगाए रखती है कि अकाली लोग नहर नहीं बनने देते। स्पीकर साहब, मैंने यह भी सुना है कि जो गांव इस एरिया से उठाए गए हैं उनको सरकार ने

मुआवजा देना है। हरियाणा के हिस्से में मुआवजे का 50 करोड रूपया आता है। यह रकम अभी बकाया है हरियाणा सरकार अभी तक दे नहीं पाई है। कसूर सरकार का अपना है और बलेम किसी और को दिया जा रहा है कि हम अपोजी इन वाले नहीं बनने देते। यह सब बहानेबाजी है। मेरी समझ में नहीं आता सरकार ऐसा क्यों नहीं बनने देते। यह सब बहानेबाजी है। मेरी समझ में नहीं आता सरकार ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन सच तो यह है कि ये असल बात का सामना नहीं करना चाहते। एक तरफ कांग्रेस के भाई यह कहते हैं कि वहां अपोजी इन के भाई गये ही नहीं और दूसरी तरफ वहां पर फौज लगा दी है और फिर कहते हैं कि पुलिस बडी कामयाब है सारी स्टेट में पूरा कंट्रोल है बडा पीस है और सब कुछ है। अगर ऐसा है तो फिर दिक्कत क्या है। क्यों नहीं खुदवाई यह नहर? स्पीकर साहब, भारत सरकार की तरफ से एक और तो यह बयानबाजी की जाती है कि बडा पीस है स्टेट पर पूरा कंट्रोल है और दूसरी तरफ क्या कारण है कि पीस होते हुए भी एसवाईएल न बने? इन दोनों बातों मे बडा अन्तर है और दोनों बातें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती है। लेकिन इन दोनों बातों के पीछे यह भेद छुपा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाए क्योंकि हो सकता है पंजाब सरकार जो कांग्रेस सरकार है बहानेबाजी करती हो और अकालियों का नाम ले लेकर उनको बदनाम करती हो। पंजाब सरकार का तो अपना वैस्टिड इन्ट्रेस्ट है। वह नहीं चाहती की हरियाणा को पानी मिले। अकालियों की बात नहीं है यह पंजाब

सरकार की बात है जो कांग्रेसियों की सरकार है यहीं लोग नहर बनने नहीं देते। अकालियों को वैसे ही बदनाम किया जा रहा है स्पीकर साहब, एक बात और कही जाती है कि हम वहां पर बनती हुई एसवाईएल नहर को खोदने नहीं गये, हमने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया कोई ब्यानबाजी नहीं की। भायद इनको ध्यान नहीं भूल गये, हमने यहां तक बयान दिया था कि अगर हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड किया गया। हरियाणा के साथ इनजस्टिस हुआ और हमारा इन्ट्रैस्ट प्रोक्टैक्ट नहीं हुआ तो हमने पहले ही इस्तीफा दे रखा है और जिस दिन ऐसा हो गया, हम इस सदन में नहीं बैठेंगे जिस दिन हरियाणा के साथ अन्याय होगा।

स्पीकर साहब, मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप एक हाउस की कमेटी बना दें जिससे हम भी हों ताकि 5—7 आदमी जाकर देख लें कि क्या काम हुआ है क्योंकि सरकार की तरफ से हाउस में कबै चन के जवाब में तो अलग जवाब आ रहा है और बजट में अलग बात कही जा रही है। कभी कहते हैं कि 50 किलोमीटर फेजिज में काम हो गया है कभी कहते हैं कि बहुत काम हो गया और कभी कहते हैं और कभी कहते हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। फिर कभी कहते हैं कि काम दो साल में हो जाएगा कभी 1983 की बात कहीं गई फिर 1985 की बात कही गई और अब 1987 का टारगैट रख दिया गया है। अगर इसी तरह से ये हर बार दो दो साल आगे चलते जाएंगे तो काम कभी पूरा नहीं

होगा। (विघ्न) हमें पता है कि अभी वहां कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हाउस की एक कमेटी बना दी जाए ताकि ऐक्चुअल काम का पता लग जाए और हमें गुमराह न किया जाए। स्पीकर साहब, यहां यह भी कहा गया कि पंजाब सरकार काम में दिलचस्पी नहीं ले रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर वहां की सरकार इतनी नकारा है और अकालियों की इतनी हिम्मत है कि वे काम को नहीं होने देते तो उस काम को किसी सैन्ट्रल एजैन्सी को सौंप दिया जाए या हरियाणा सरकार को सौंप दिया जाए। इन भावों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को पास किया जाए।

**श्रीमति भारदा रानी:** माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो प्रस्ताव बहस के लिए मौजूद है वह एसवाईएल नहर के निर्माण के बारे में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एसवाईएल नहर का निर्माण जल्दी हो जाए। इस बात को हरियाणा का एक एक आदमी एक एक किसान, खेत में काम करने वाला एक एक व्यक्ति, चाहे कोई गांव में रहने वाला है या भाहर में रहने वाला है उत्सुकता की नजर से देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारा इलाका ही नहीं बल्कि हरियाणा का लगभग दो तिहाई से अधिक हिस्सा सूखा एरिया है और यदि कहीं मौसम जैसा इस साल रहा है वैसा ही हर साल हो जाए तो सब लोगों के लिए पानी की बात हो जाती है। हमारी जमीन के नीचे बहुत अच्छा पानी नहीं है और उपर नहरों का पानी भी बहुत कम है।

एसवाईएल नहर से साढ़े तीन मिलियन एकड फीट पानी हरियाणा में आएगा। इसके लिए बहुत समय पहले से हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार पडा है। खाल खुदे पडे हैं नहरे खुदी पडी है लेकिन अब वे सब नेस्तानाबूदउ होती जा रही है। इस नहर का बहुत जल्दी तैयार होना हमारे लिये बहुत जरूरी है। यह खु गी की बात है कि इस नहर का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने और इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर ने इस बारे में स्थिति यहां बताई थी कि काफी काम वहां हो चुका है और जल्दी ही इस नहर का काम पूरा हो जाएगा। इस समय यह पानी पहले अपने दे ा से बाहर जा रहा है पंजाब से बाहर जा रहा है। इस नहर के बनने से इस पानी का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप जरा इस प्रस्ताव की भाशा पढिए। इसमें लिखा है कि—‘यह सदन राज्य सरकार से सिफारि ा करता है कि वह केंद्रीय सरकार से बात करें कि पंजाब क्षेत्र में एसवाईएल नहर के निर्माण कार्य को पंजाब सरकार से वापिस लिया जाए तथा उसके निर्माण कार्य में विलम्ब को टालने के लिए हरियाणा सरकार को सौंपा जाए। आगे यह सिफारि ा करता है कि उस समय के अनुमानो के अनुसार निर्माण की लागत, यदि कोई, कार्य करवाने में विलम्ब के कारण अब बढ गई हो तो वह अब पंजाब सरकार द्वारा वहन की जाए।’

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अन्तर्राष्टीय सरकार के आपसी व्यवहार के कुछ नार्मज होते हैं कुछ तरीके होते हैं



कुछ म्यूचुअल अन्डरस्टैंडिंग होती है जो परम्परा से चली आ रही है। यह ठीक है कि वह बात तय की हुई नहीं है लिखित बात नहीं है लेकिन वह एक अन्डरस्टूड ऐग्रीमेंट होता है। अगर एक राज्य के अन्दर काम होना है तो दूसरा राज्य जिसके लिए वह काम होना है वह उसी राज्य की सरकार के द्वारा काम करवाएगा। इन लिमिटस को आपसी रिले ान्ज को इतनी आसानी से तोडना संभव नहीं है। इस नहर के निर्माण में अब भी जो देरी हुई है उसके बारे में इनको अच्छी तरह से मालूम है कि वह किस हालत में हुई है। हमारे विरोधी भाई अकालियों के साथ खातेपीते रहे हैं। मिल कर इलैक् ान लडते रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की सरकारों के विरोध में योजनाएं बनाते रहे हैं। ये प्यार से बैठकर उन्हें समझा सकते थे कि आप भी इसी दे ा के हैं और हम भी इसी दे ा के हैं। साढे तीन मिलियन एकड फीट पानी जो इस समय पाकिस्तान में जा रहा है उसे अपने ही दे ा में प्रयोग करने के लिए इस नहर को बन जाने दो। इस पर क्यों हल्ला गुल्ला मचाते हो। स्पीकर साहब, यह हल्ला गुल्ला कब मचा? इसी जड कहा है। यह देखने वाली बात है। जब चंडीगढ के बारे में फैसला हुआ जब राबी ब्यास का पानी जो पाकिस्तान को जा रहा है हरियाणा को देने का निर्णय हुआ, तभी ये सारे ऐजिटे ान्ज भुरू हुए है तभी से सारी बातें पैदा हुई है। इसका मतलब यह है कि वे लोग नहीं चाहते कि पानी हरियाणा को मिले लेकिन ये लोग बडे आराम से उनके साथ मिलकर बैठते हैं खाते हैं और पीते हैं। (विघ्न) इन्हें चाहिए था कि ये उनके विरुद्ध वक्तव्य देते। उनका

खुलमखुलला विरोध करते। ये उनसे कहते कि आप दे 1 के पानी को पाकिस्तान में जाना तो पसन्द कर रहे हैं लेकिन अपनी पड़ोसी स्टेट को अपने से ही अलग होकर जो हिस्सा एक स्टेट बना है यानि हरियाणा को जहां बिल्कुल सूखा पडा है पानी देना नहीं चाहते। जो कि एक गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, उनकी सारी धार्मिक मांगे, सारे ऐजीटे एन्ज उग्रवादी विचारधारा और खालिस्तान की मांग इसी बात के उपर है कि हरियाणा को पानी न दिया जाए। हमारे विरोधी भाईयो को चाहिए कि इन सारी चीजों को सामने रखकर ये उनके विरुद्ध वक्तव्य दे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि पंजाब में भी सब लोग इस तरह के कामों में भागिल नहीं हैं उसमें भी तरह तरह के गुप्स हैं तरह तरह की विचारधारा है लेकिन जो लोग इस विचारधारा के हैं कि पाकिस्तान को तो पानी चला जाए लेकिन हरियाणा को पानी न मिले उनको राष्ट्रद्रोही की कहा जाएगा। राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। स्पीकर साहब, हरियाणा को यदि पानी मिल जाए तो उसका लाभ पंजाब को भी है क्योंकि एक गांव में यदि हरियाली होती है तो पड़ोसी गांव पर भी उसका असर पडता है एक राज्य अगर हरा भरा होता है तो दूसरे राज्य पर भी उसका असर पडता है अगर हरियाणा के अन्दर पानी आएगा तो उसके खेत हरे भरे होंगे तो उसका लाभ पंजाब को भी होगा, पंजाब में जो अकाली रहते हैं उनको भी होगा। अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो हमारी पूज्य स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी जी इस नहर का िालान्यास करके आई थी और

तबसे इसके निर्माण का काम चल रहा है। यह बात अलग है कि उसके निर्माण में कुछ देर हो रही है। इस देर के भी कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो टैक्निकल कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वहां काम करने वाले कुछ लोगों की मनोवृत्ति भी इसकी देरी का एक कारण हो। वे भी भायद न चाहते हो कि उस राज्य से पानी किसी दूसरे राज्य में जाए। इसलिए इस सरकार को दोशी ठहरा देना या यह नतीजा निकाल लेना कि पंजाब सरकार इस काम को नहीं करना चाहती है ठीक बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन भाईयो से यह पूछना चाहती हूं कि यदि वे लोग पंजाब सरकार को उस नहर को नहीं बनाने देते तो वे हरियाणा सरकार को कैसे बनाने देंगे? स्पीकर साहब, इन्होंने यह जो प्रस्ताव दिया है यह माना कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे का नाम इसके अन्दर है लेकिन इसकी भाब्दावली के मैं तो बिल्कुल विरुद्ध हूं। यह बात इस तरीके से हो सकती है कि ये इस प्रस्ताव को वापिस ले लें और ट्रैजरी बेंचिज की तरफ से एक प्रस्ताव आए जिसमें काम को जल्दी से जल्दी ऐक्सपेडाइट करवाने की सिफारि । पंजाब सरकार से की जाएं। अगर हमें लगे कि काम में कुछ ढील है पंजाब सरकार को इसे ऐक्सपेडाइट करवाने में कोई मजबूरी सामने आ रही है तो हम भारत सरकार से निवेदन करें कि वह उनको कहे कि काम को जल्दी से जल्दी करें ताकि जो साढे तीन मिलियन एकड फीट पानी हरियाणा को मिलना है वह हमें मिले क्योंकि हरियाणा के लोग बडी उत्सुकता से पानी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह जो

प्रस्ताव आया है यह गलत भावदावली के अन्दर आया है इसलिए यह प्रस्ताव इनको वापस ले लेना चाहिये।

**चौधरी फूल चन्द:** अध्यक्ष महोदय पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बोलने के लिए समय दिया। आज सदन के सामने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। प्रस्ताव इस प्रकार है—

‘यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि वह केंद्रीय सरकार से बात करें कि पंजाब क्षेत्र में एसवाईएल नहर के निर्माण कार्य को पंजाब सरकार से वापिस लिया जाए तथा उसके निर्माण कार्य में विलम्ब को टालने के लिए हरियाणा सरकार को सौंपा जाए। आगे यह सिफारिश करता है कि उस समय के अनुमानों के अनुसार निर्माण की लागत, यदि कोई, कार्य करवाने में विलम्ब के कारण अब बढ़ गई हो तो वह अब पंजाब सरकार द्वारा वहन की जाए।’

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से चिन्तित हैं कि एसवाईएल नहर जिसके बनने में बड़ी देरी हो रही है वह हरियाणा के जन जीवन का प्रतीक है और सबकी हार्दिक इच्छा है कि इस नहर की जल्द से जल्द खुदाई होनी चाहिए। उस नहर में पानी आने से हरियाणा के लोगों के जीवन में एक खुशी की लहर आयेगी और यह पानी उस क्षेत्र में जायेगा जो बिना सिंचाई के पड़े हैं। स्पीकर साहब आप जानते हैं मेरा

और आपका क्षेत्र तो पास ही पास लगते हैं। उन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं है। अम्बाला, भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुडगांवा के क्षेत्रों में पानी की कोई सुविधा नहीं है। कई जगह तो ऐसी है जहां पर पीने और सिंचाई के लिए पानी नहीं है। (विघ्न) मास्टर रिाव प्रसाद के अम्बाला भाहर के इलाके को भी शामिल कर लेंगे क्योंकि वहां पीने के पानी की दिक्कत है। स्पीकर साहब, पंजाब के भाई खुशु तो जरूर है। कि पंजाब अलग हो गया लेकिन जब पंजाब और हरियाणा एक था तो पंजाब वाले भाई हरियाणा के नाम को इस्तेमाल करते थे। हरियाणा उनकी मांग पर बना था। जब हम लोग पंजाब से अलग हुए तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था क्योंकि जो पैसा हमारे क्षेत्र का था वह पंजाब में ही लगता था और हरियाणा यों ही वीरान पडा रहता था। हरियाणा बनने के बाद ही हमारे एरिया के लोगों की उन्नति हुई। आज हरियाणा उन्नति के लिहाज से देश में प्रथम नम्बर पर है। स्पीकर साहब, जब भी कभी चर्चा चलती है तो पंजाब के भाई बड़े मान और खुले भावों में कहते हैं। कि हमें करनाल तक का एरिया मिलना चाहिए। अम्बाला की तो एक पोजीशन है कि जैसे यह उनके बीच में ही है लेकिन जब पानी देने बात आती है तो देने के लिए तैयार नहीं। बड़े दुख के साथ कहना पडता है कि पंजाब वालों को पाकिस्तान को पानी देना मंजूर है या कहीं और देना हो तो मंजूर है लेकिन हरियाणा राजस्थान और दिल्ली को देना मंजूर नहीं फिर ये बात कहते हैं कि देश एक है। मेरे भाई नेहरा साहब कह रहे थे कि जब विपक्ष के साथियों को मौका आया था तो उस

वक्त उन्होंने उसे नहर को बनाने के बारे में कोई कदम उठाया। स्पीकर साहब जब 1977 में जनता पार्टी बनी और हरियाणा में यह भानुमती का कुम्बा जुडा तो इन्होंने अकालियों के साथ समझौता कर लिया। चुनाव मिटिंगों में जगह जगह जाकर कहते थे कि अकाली पार्टी के साथ हमारा समझौता है हम एक हैं लेकिन अकाली पार्टी का इलैक् इन मैनीफैस्टों यह था कि हरियाणा को पानी नहीं देना है। जब मैनीफोस्टो अकाली पार्टी का यह था कि पानी नहीं देना तो फिर ये लोग इनका साथ कैसे दे रहे थे। ये भाई जब उनके इलैक् इन मैनीफैस्टों से सहमत थे तो उनसे पानी की बात कैसे कर सकते हैं? ये किसान के हितैशी नहीं हैं। ये भाई किसान के नाम का प्रयोग करते हैं। और जगह जगह प्रचार करते हैं कि हमने किसानों के लिए यह किया वह किया। आप इस बात से अन्दाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के किसानों के कितने हितैशी हैं मैंने गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए कहा था कि ये कितने हितैशी बने लेकिन इनके खाने के दांत और है और दिखाने के और है। मैंने चौधरी चरण सिंह के समय का किस्सा सुनाया था कि उनके समय में गन्ने का क्या भाव रहा है? स्पीकर साहब, आपका और हमारा क्षेत्र गन्ना पैदा करने वाला है। अगर किसान को गन्ने का उचित मूल्य न मिले तो उसकी इकोनोमी खराब हो जाती हैं उन दिनों गन्ने का क्या हाल था गन्ने का रेट पन्द्रह रूपये क्विंटल से गिर कर चार रूपये आ गया था। उस टाइम पर गोला और पाती छह रूपये क्विंटल बिकती थी और गन्ना चार रूपये बिकता था। यही हाल आलू का था। हमारे क्षेत्र

में आलू उगाया जाता है। आलू का इतना बुरा हाल हुआ कि किसी ने पूछा तक नहीं। हमारे मंत्री जी कह रहे हैं गन्ना चार रूपये, पाती छह चरण सिंह की जय। आप इसी प्रकार नरमा के भाव के बारे में देखें। उसके भाव भी बहुत गिरे थे। स्पीकर साहब, एक बात मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि एक जाति पर ऐसप र्नि आ जाता है लेकिन मेरा कहने का मुद्दा यह है किसान के हित में इन्होंने कोई कदम नहीं उठाये बल्कि किसान की दयनीय हालत बना दी। कई सालों तक वह उठ नहीं पाया। आप जानते हैं कि यह नहर क्यों नहीं खुद रही है? इस अर्से में इन लोगों ने इतनी अफरा-तफरी मचा दी कि ब्यान नहीं की जा सकती चाहे वह राजनैतिक जीवन में थी या सामाजिक जीवन में थी। इन लोगों ने इतनी छूट दे दी कि किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। आज ये बिना आधार की बात करते हैं लेकिन मैं इनहें बताना चाहता हूं कि श्रीमति इंदिरा गांधी आतंकवाद का िकार हो गई और हमारे बीच में नहीं रही लेकिन यह 3.50 एमएएफ पानी देकर हरियाणा पर इन्दिरा जी ने अहसान किया है। इस पानी के आने से लोगों की जिन्दगी में एक नई लहर दौड़ जायेगी। इसलिए हमारे पंजाब के साथ यह नहीं चाहते कि इसका पानी हरियाणा में आये। वे लोग कभी कोर्ट में चले जायेंगे। कभी आतंकवाद का कोई न कोई किस्सा बना कर उसे रोक देंगे। उनका तो मैनीफैस्टो है कि हरियाणा को पानी नहीं देना है। मैं आपके जरिए सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार कितना जोर लगा रही है पानी लाने के लिए लेकिन वे अपनी तरफ से प्लान

बना रहे हैं कि किसी न किसी बहाने से विलम्ब की जाये और इसका पानी हरियाणा में न जाये। किसी किसान को रिट करवा देंगे कि उसके पीछे कौन है किस के कारण विलम्ब हुई है इस बात को गहराई से मेरे सज्जन साथियों को सोचना पड़ेगा। यह तभी सोच सकते हैं जब हम सही मायनों में हरियाणा के हितैशी हो।

स्पीकर साहब, आज अगर यह नहर नहीं आती है तो हमारे क्षेत्र अम्बाला और कुरुक्षेत्र में पानी मिलने की मांग कैसे पूर्ण होगी? हमारे अम्बाला जिले में कुछ क्षेत्रों में ट्यूबवैल्ज लगते नहीं और लगे हैं तो उनका पानी नीचे चला गया है। इसी तरह से कुरुक्षेत्र में भी है। अम्बाला जिले में तो नहर के पानी की बहुत ही कमी है जैसे कभी तो सारे हरियाणा में ही है लेकिन हमारे जिले में खासतौर से है। हरियाणा में दस हजार क्यूसिक पानी भाखडा से आता है। इस पानी से क्या गुजारा होता है? अध्यक्ष महोदय, जिस खेती को पानी नहीं मिलता। यह वायबल नहीं है आज अगर किसान कर्जा ले ले तो वह दे नहीं सकता। कारखानेदार तो आज के दिन कर्जे की अदायगी कर देता होगा लेकिन जिस किसान के पास नहर का पानी, ट्यूबवैल्ज के साधन नहीं है अगर वह चार पांच हजार कर्जा ले ले तो कर्जा चुकाते चुकाते उसकी कमर टूट जाती है। जब किसान की पैदावार उपयुक्त नहीं है तो उसकी द ॥ ठीक नहीं है। किसान की द ॥ ठीक नहीं है तो उस किसान के साथ लगे हुए मजदूर या कामगर की द ॥ कभी ठीक



नहीं हो सकती। अगर यह नहर हरियाणा में आती है तो हमारे किसानों की हालत सुधर सकती है। पंजाब के लोगों को पानी की आवश्यकता नहीं है। पंजाब में पानी सरप्लस है।

हमारे बड़े भाई पंजाब वालों को पानी दिल्ली को देना मंजूर नहीं, राजस्थान को देना मंजूर नहीं, हरियाणा को देना मंजूर नहीं, लेकिन पाकिस्तान को देना मंजूर है। इसका क्या कारण है इसके पीछे क्या बात नजर आती है। यह किस बात को दर्शाता है। जैसे आपको मालूम है अगर पानी आ जाता है तो हमारे क्षेत्र के लिए अभी जो दादुपुर कैनल जैसे प्रोजेक्ट जो मंजूर हुए पड़े हैं वह बन सकेंगे। अगर हमारे पास कुछ फालतू पानी आता है तो हमारे एग्जिस्टिंग पानी में से इस नहर को पानी मिलेगा। यह नहर बनेगी और हमारे क्षेत्र के लोगों का जीवन खुलाहाल होगा और उसमें जीवन की नई लहर आएगी। इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी जहां पर पानी नहीं है। जैसे महेंद्रगढ़ वगैरा है वहां पर भी पानी जायेगा। वहां का जन-जीवन बढेगा। लेकिन अचम्भा है हमारे साथियों ने कभी ऐसा नहीं सोचा। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि नहर पहले से चल रही है उस नहर को दो बार कटवा दिया और आतंकवाद इतना है कि जिसकी कोई हद नहीं। जैसे मैंने जिक्र किया कि इंदिरा जी तो आतंकवाद का शिकार हो गयी। वह इस देश पर बलिदान हो गई। हम लोगों को अपने नहर को देखने के लिए जिससे हमें पानी मिलता है भेष बदल कर जाना पडा। चौधरी भजन लाल जी गए। हमारे

भामा और सिंह सुरजेवाला, इरीगेटन एण्ड पावर मिनिस्टर को भी छिप कर जाना पडा। (मास्टर टिपु प्रसाद की ओर से विघ्न) मास्टर जी, आप कहते हैं कि गए नहीं लेकिन मुझे मालूम है डा० मंगल सैन सुरजेवाला जी साथ गये थे अपनी नहर का पानी लाने के लिए जिसको काट दिया गया है उसको ठीक करवाने के लिए हमें चोरी छिपे जाना पडता है। इस प्रकार के हालात हमारे प्रदेश और हमारे पड़ोसी प्रान्त में हो तो हमारे साथियों को यह चाहिए कि इन हालात को सुधारने के लिए वह आगे बढे। उनको भगवान सदबुद्धि दे और जो आज देश में हालात है वह ठीक हों। हमारा देश एक है चाहे हम कहीं और किसी भी सूबे में रहते हैं या किसी भी प्रान्त में रहते हैं। हम अपने देश की एकरूपता बरकरार रखने के लिए देश की बहबूदी हो आगे बढाने के लिए और किसी भी भले काम के लिए एक रहें। यह बात ठीक है। कि इस देश में भिन्न भिन्न राज्य हैं वह किसी कारण से है। हमारा देश एक है। देश के हर प्रान्त की उन्नति के लिए और हर प्रान्त के कार्य के लिए अध्यक्ष महोदय हम सब का यह फर्ज बनता है। कि जो नामर्ज निश्चित है उनके मुताबिक हम एक दूसरे की सहायता करें। एक दूसरे के साथ मिल कर चले नहीं तो अध्यक्ष महोदय क्या होगा। आपको याद होगा एक बार हमारी बसें हिमाचल प्रदेश में टैक्स के कारण रोक ली गई थी। जब उन्होंने हमारी बसें रोक ली तो वे यह बात भूल गये कि हिमाचल की बसें भी हरियाणा होकर दिल्ली जाती है। जब उन्होंने हमारी बसें रोक ली तो हमने भी हिमाचल की कुछ बसें रोक ली। नतीजा क्या हुआ।

दो दो मील तक ट्रकों की, बसों की और कारों की लाईनें लग गयी। हम ऐसे हालात नहीं चाहते आपको पता ही है कि यहां पर दो अढाई साल तक जनता पार्टी की सरकार रही, सैंटर में भी रही और पंजाब हरियाणा में भी रही। लेकिन उस दौरान भी इस मामले में कुछ न कुछ हो सका। अब हमारे भाई यह कहते हैं कि पंजाब में भी केंद्र का नुमायंदा है। कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है तो अब कर लो। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि कोई काम हम लाठी या गोली से नहीं करना या करवाना चाहते। हम यह चाहते हैं कि यह काम सदभावना से हो जाए तो क्या ही अच्छा रहे। एक मुददा हमारे विपक्ष के भाई जो अहम है वह भूल गये वह है आतंकवाद का। इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि हम उनके चुनाव मैनिफैस्टो के खिलाफ है। ऐसी कोई बात रिकार्ड पर नहीं है। पिछले दिनों ही मेरे ख्याल में पिछले सप्ताह ही हमारे सिचाई मंत्री जी जब बोल रहे थे तो इन्होंने यह फरमाया कि साढे ग्यारह किलोमीटर नहर बन गई है। यह थोडी सी खुशी की बात है। हमारी सरकार की ओर से 45 करोड रूपया जमा हो चुका है। इस काम की प्रगति में तेजी से चलना रहना चाहिये। हमारे साथियों को यह चाहिए कि वे उग्रवाद को पनाह न दें। अध्यक्ष महोदय, मुझे आता है कि हमारे विपक्ष के भाई पंजाब के भाइयों को सलाह देंगे कि वे आतंकवाद को पनाह न दें। भुरू में भायद उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उन्होंने आतंकवाद को पनाह क्यों दी। यही नहीं उन्होंने जो देना विदे में मालाहूर हरमिंदर साहब है। उसमें भी उग्रवादियों

को पनाह दी उन्हें छिपने के ठिकाने दे दिये। आज वे इस बात के लिये पछताते हैं कि हमने क्यों ऐसा किया? आज जेलों के अन्दर कई लोग तो ऐसे हैं जो बाहर भाकल भी नहीं दिखा सकते? कई लोग तो यह कहते हैं कि हम लोग तो अन्दर ही ठीक है। इसका क्या कारण था? इसका कारण उग्रवाद था। हमारे साथियों को यह चाहिये कि खुले भावों में उसकी निन्दा करें। जो अवार्ड दिया गया था उसके बारे में उनको अभी तक वह बात याद करनी चाहिये कि अवार्ड मिलने के बाद सारे पंजाब में दीवाली मनाई गई थी इन्होंने लडियां सजाई थी। वे उस बात को कैसे भूल गये? कैसे यह जहर उनके सामने आ गया? उस जहर का कितने लोगों को ितकार होना पडा? यह एक चिन्ता का विषय है। इन्सानियत के लिये यह एक बहुत ही निंदनीय बात है। दोनों तरफ से इन्सानियत का खून हुआ है। यह इन्सानियत के नाम पर एक धब्बा है। हम सारे ही इसकी निन्दा करें और दे ा में राष्ट्रीय एकता को बढाने के लिये और अपने दे ा और प्रदे ा की उन्नति के लिए काम करें। सारे प्रान्तों की उन्नति के लिये और हमारे प्रान्तों की बेहतरी के लिये विशेषतौर पर यह जरूरी है कि इसके लिये सदभावना का माहौल तैयार किया जाये। यह मामूली सा नहर का मसला है। आपको याद होगा कि जब 1982 में कपूरी गांव में इस नहर का कार्य आरम्भ करने इंदिरा जी आयी तो वहां से थोड़ी दूर पर ही यह नारे सुनाई देते थे कि हम नहर नहीं खूदने देंगे। हम यह करेगें हम वह करैंगे। यह सारी बातें हरियाणा के जन जीवन की उन्नति के लिए रुकावट है। हमारी अगर यह नहर बन जाती

है तो हमारा प्रदे 1 प्रगति की ओर बढ़ता है। बिजली का संकट काफी हद तक हल होता है। हमारे विपक्ष के साथी इसकी बहुत चर्चा करते हैं इसका भी हल होता है। ट्यूबवैल्ज को फिर बिजली भी मिलेगी। क्योंकि नहर का जब पानी आएगा तो ट्यूबवैल्ज को बिजली की भी आव यकता पड़ेगी। इसके अलावा बिजली की जरनें 1न के और साधन भी बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से यह निवेदन करूंगा कि हमारे बगल की स्टेट पंजाब के अपने भाइयों को दे 1 के हित के लिए हरियाणा के हित में राजस्थान के हित में दिल्ली के हित में यानी जहां जहां पर भी यह पानी जाना है आज समय की मांग यह है कि पृथकतावादी ताकतों को एक तरफ करके सदभावना से सोचें। मन में यह सोच धारण करें कि हम सब भाई भाई हैं चाहे वह हरियाणा में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं। या जम्मू क मीर में रहते हैं उन सब की भलाई ही इंसानियत का तकाजा है। (व्यवधान व भाोर) विज साहब का प्रस्ताव ठीक हइै वे साधन सम्पन्न है लेकिन उनकी और से जो थोड़ी सी बातें आई है कि इस नहर के बनाने में विलम्ब हो रहा है उसके कारण मैंने आपको बता दिए है। मैंने इस साथियों को विलम्ब का कारण बता दिया है। इस विलम्ब के कारण को दूर करें। जैसे मैंने बताया है उनसे वे समझौता तोडकर उनको मजबूर करें कि वे आपकी बात को माने। आप उनसे यह कहो कि भाई जब आप हमें चुनाव में साथ लेकर चलना चाहते हो तो हमारी तरक्की की लहर को मत रोको, हम आपको साथ लेकर इस तरह से नहीं चल सकेंगे। भगवान उनकी

सदबुद्धि दें। उनके मन में सदभावना दे और हमारी यह नहर बने। ऐसा होने के बाद हमारे जो किसान भाई हैं खासतौर पर हमारे क्षेत्र के और महेन्द्रगढ़ क्षेत्र के और पूर्वी हरियाणा के उस भाग के भाई जहां सूखा पडा है। उनमें भी पानी आने से हमारे देहात के लोग सुख की सांस लेंगे।

### 13.00 बजे

आज गुप्ता जी एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और कह रहे थे कि जो रहन-सहन का स्तर है वह ठीक है और उसकी क्वालिटी और बढ़ेगी। यह नहर बनने से वह स्तर अवश्य बढ़ेगा। स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो कदम उठाए हैं जिससे कि यह नहर जल्दी से जल्दी बने उस कदम को और तेज करें। इस दिनांक में प्रयास तो बहुत हुए हैं जैसे कि पैसा लगा दिया और पंजाब का स्टाफ लगा दिया इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमें तो काम चाहिए जिससे कि हरियाणा की बेहतरी हो। स्पीकर साहब, सदन में बताया गया है कि यह नहर 1987 तक पूरी हो जाएगी मुझे पूरी आशा है कि यह नहर उसी साल में पूरी हो जाएगी और उसके बाद हरियाणा की खुलाहाली बढ़ेगी। धन्यवाद।

ष्णीय अध्यक्ष महोदय, सदन में एसवाईएल के निर्माण पर जो चर्चा चल रही है। निस्संदेह यह बहुत गंभीर विशय है और

इस पर सोच विचार करके इसके निर्माण में सभी को मिलजुल कर सहयोग देना बहुत जरूरी है।

**श्री मंगल सैन:** बहन जी आप किस के बारे में बोल रही है।

**बहिन भान्ति देवी:** मैं सतलुज यमुना योजक नहर के बारे में जो प्रस्ताव है उस पर बोल रही हूं और कुछ पूछना हो तो और पूछ लो। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि कम से कम मैंने किसी को कभी भी विधान सभा में बोलते हुए, बीच में नहीं टोका है। मुझे भी बोलते समय टोकना नहीं चाहिये। स्पीकर साहब पुराने विधायक के नाते डा० साहब को बोलने का अभ्यास है। यहां विधान सभा में बैठे सदस्यों को भी तथा बाहर से आने वाले दार्जिलों को भी उनके बोलने का ढंग अच्छा लगता है परन्तु बहुत बार इनकी बात तीर सी लगती है जो दूसरे को घाव के सामान कष्ट दायक होती है। अध्यक्ष महोदय, बिहारी सत सई नाम की एक पुस्तक है। उसमें सात सौ दोहे हैं उस पुस्तक की आलोचना प्रति आलोचना में एक दोहा जो डा० साहब के बोलने पर फिट बैठता है इस प्रकार है—

सत सैया के दोहे ज्यों नावक के तीर

देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर।

बराए मेहरबानी मेरे बोलने के टाईम आप टोका न किया करें और अगर अब इतना कहने पर भी करेंगे तो आपकी मर्जी है भाई साहब।

अध्यक्ष महोदय, मैं एसवाईएल के निर्माण के विषय में कुछ भाव रख रही थी क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय है और इसका निर्माण बहुत जरूरी है क्योंकि हरियाणा की समृद्धि और हरियाणा की सम्पन्नता इससे जुड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि प्रभू के मंगलमय विधान के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं और इसी परिस्थिति परिवर्तन के परिणामस्वरूप यह परिस्थिति भी बन गई है कि इस नहर का निर्माण भुरू हुआ। आप सब को मालूम है कि 1947 से पहले सतलुज, रावी, ब्यास, चनाव और जेहलम ये पांच नदियां जिस क्षेत्र में बहती थी वह पंजाब कहलाता था। परिस्थितियां बदली। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति का समय आया और दुर्भाग्यवश दे आ का बंटवारा हुआ और उसके बाद फिर परिस्थितियां बदली और 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ। स्पीकर साहब, हम देखते हैं कि नदियां तो अपने विधान के मुताबिक पहाड़ों से निकलकर का मीर, पाकिस्तान और पंजाब को पानी देती हुई अरब सागर में पहुंच रही हैं हरियाणा में आई और अपने उसी क्रम के अनुसार सारे इलाके को बिना किसी भेदभाव के भीतल और मीठा जल अपने रास्ते में आने वाले सब प्रदेशों को देती रही लेकिन हम पंजाब व हरियाणावासी छोटी छोटी बातों पर आपसी मतभेदों के कारण इस नहर की खुदाई में



रूकावट पा रहे हैं। जहां तक आज एसवाईएल के जल का सवाल है हरियाणा के कुछ हिस्से जैसे महेंद्रगढ़, हिसार, रिवाड़ी और गुडगांव इनमें पानी की जरूरत है। उन सूखे इलाकों को हरा भरा करने के लिए इस योजक नहर के पानी की बहुत आवश्यकता है और इसके साथ ही साथ मनुष्य के लिए और पशुओं के पीने के लिए मीठे पानी की जरूरत है। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि कोई इस का विरोध करें। यह राजनैतिक रूकावट है कि हमारे पंजाब के भाई लोग जो पोलिटी पयंज है या जो भी है। नदी का फालतू पानी पाकिस्तान में जाना पसन्द कर रहे हैं परन्तु हरियाणा को नहीं देना चाहते तभी सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के निर्माण को रोक रहे हैं। ऐसे मामले में बहुत सोच समझकर समस्या का हल निकालना चाहिए। इस मामले पर आज सारा हरियाणा की नहीं बल्कि सारा देश चिन्तित है कि यह नहर जल्दी से जल्दी बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय यह 118 किलोमीटर लम्बी नहर है और इस पर बहुत अधिक धन व्यय हो चुका है। हरियाणा में इसका निर्माण को चुका है रूकावट तो पंजाब में राजनैतिक मतभेदों के कारण आई हुई है। जब जनता राज में परिस्थितियां ठीक थीं और अनुकूल अवसर था। वह जनता सरकार ने खो दिया और अब जब काम शुरू हुआ तो परिस्थितियां कुछ खराब हो गईं। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मेरा यह निवेदन है कि सभी को मिलजुल कर केंद्र से सहयोग से समस्या को हल करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तभी हमारे प्रदेश की उन्नति हो सकेगी।

**चौधरी सूबे सिंह पुनिया:** सभापति महोदय, एसवाईएल नहर के बारे में जो रेजोल्यूशन आज सदन में चर्चा का विषय बना हुआ है मैं उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस परियोजना का उद्घाटन हमारी पूजनीय स्व० प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी जी के कर कमलों से हुआ था और उनका दिया हुआ 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उसमें सबसे पहली जो बात कही गयी है वह है सिंचाई के साधनों की क्षमता को बढ़ावा देना। स्पीकर साहब, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता आज कृषि और उससे संबंधित उद्योग धंधों पर अपना गुजारा करती है अपना जीवन निर्वाह करती है। यह जो परियोजना है यह राष्ट्रीय महत्व रखती है पिछले सप्ताह भी चर्चा हुई है और हमारे बिजली एवं सिंचाई मंत्री महोदय चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला जी ने बताया था कि इस परियोजना पर कार्य आरम्भ हो चुका है और इसके निर्माण के लिए पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसलिये इस परियोजना के लिये हरियाणा सरकार ने पैसा भी दिया था। साथ में यहां पर यह भी बताया गया था कि इस नहर का 11 किलोमीटर लम्बा हिस्सा बन चुका है। इसके लिये हरियाणा सरकार पहले ही केंद्रीय सरकार को इसकी डिले के बारे में सूचित कर चुकी है। और इस कारण से जो खर्चा हरियाणा सरकार पर पडा है उसके लिये बार बार भारत सरकार से प्रार्थना कर चुकी है कि भारत सरकार हरियाणा सरकार की इस मामले में पूरी तरह से मदद करें क्योंकि यह परियोजना केंद्र सरकार के

आ र्णवाद से ही आरम्भ की गई है। मैं सदन को ध्यान आपके माध्यम से इस और आकर्षित करना चाहूंगा कि जब यहां पर विरोधी पक्ष की सरकार रही तो उन्होंने एक करोड रूपया इसके लिये दिया था ताकि इस कार्य के लिये जमीन एकवायर की जा सके लेकिन 1977 में जब इनकी जनता सरकार बनी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने दो बातों का नारा यहां पर दिया था कि भ्रष्टाचार बन्द और पानी का प्रबन्ध और यह नारा पूरी तरह से फेल हुआ। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है उस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उस समय के मुख्यमंत्री महोदय ने अपने ..... से भी नाता तोड लिया। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** किसी का नाम यहां पर नहीं आयेगा।

**चौधरी सूबे सिंह पूनियां:** पानी का प्रबंध करने का सवाल जहां तक है उस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बाल्टी पानी की तो किसी को प्यास बुझाने के लिए दे नहीं पाये और किसानों को खेती की सिंचाई के लिए क्या पानी देंगे ( गोर) स्पीकर साहब, मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि यह तो एसवाईएल की परियोजना है यह एक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। हरियाणा के बच्चे बच्चे के मन में इस बात की उत्सुकता है कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए और सरकार इस बारे में पूरी तरह से प्रयास भी कर रही है सर्तक भी है लेकिन दूसरी तरफ का वातावरण आजकल इतना दूषित हो चुका है

जिसके कारण इस काम में देरी हो रही है। विरोधी दल के भाईयों को मैं इतना ही कहूंगा कि—

मंजिल पे जिन्होंने पहुंचना हो वे ठिकवा नहीं करते।

ठिकवा जो करते हैं वे पहुंचा नहीं करते।

और एक बात अन्त में कह कर अपने अपोजी इन भाईयों से प्रार्थना करूंगा कि जो भाब्दावली उन्होंने अपने रेजोल्यू इन में दी है उसको बदले क्योंकि हरियाणा सरकार पहले ही अपने इन प्रयासों से सर्तक है। स्पीकर साहब, इस के साथ अब मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं। जयहिन्द।

**श्री महेंद्र प्रताप सिंह:** हाउस में जो एसवाईएल के बारे में चर्चा हो रही है उसके बारे में हमारे साथियों ने इसमें यह कहा है कि इस नहर के बनने में पंजाब सरकार के कारण जो रूकावट आई है उसके लिये यह हाउस एक रेजोल्यू इन पास करे और भारत सरकार को यह अप्रोच करें कि पंजाब सरकार से जो कि इस नहर को खोदने में असमर्थ रही है उसको हरियाणा सरकार अपने चार्ज में लेकर उसकी खुदवाई का काम खुद करवायें। इसलिए मैं एक बात यहां सदन में कहना चाहती हूं कि विरोधी पक्ष के भाइयों ने बार बार यहां पर सरकार को आलोचना भी की है। तरह तरह के इलजाम भी लगाये हैं लेकिन वे स्वयं भी इस बात को समझते हैं कि सरकार ठीक तरीके से काम कर रही है। जहां तक कि आलोचना का ताल्लुक है अगर कोई मुद्दा ऐसा है

तो हमें कोई ऐतराज नहीं है वे आलोचना करें, उनका फर्ज भी है लेकिन आलोचना सिर्फ आलोचना के लिए ही कर रहे हैं यह कोई भाभा की बात नहीं है। वैसे विरोधी दल के भाईयों को पूरा विवास भी है कि हरियाणा सरकार विकास नीतियों और उन कामों को पूरा करने में पूरी क्षमता रखती है और हरियाणा का पूर्ण भला होगा। यह जो एसवाईएल का काम सरकार करवा रही है इसके लिये तो विरोधी दल के भाईयों को सरकार का धन्यवाद करना चाहिये। ( गोर एवं विघ्न)

**Mr. Speaker:** He has well said.

**चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल:** स्पीकर साहब, अभी मेरे एक साथी ने बोलते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की क्षमता पर हमें पूरा विवास है। चूंकि हमारी तरफ से 24-25 आदमी उधर जा चुके हैं और ये भी इन में से एक है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि हमें इनकी सरकार की क्षमता पर कोई भाक नहीं है।

**एक आवाज:** स्पीकर साहब, ऐन्टी डिफैक्टान बिल आने की वजह से इनका खाना पीना बन्द हो गया है। ( गोर)

**श्री महेंद्र प्रताप सिंह:** स्पीकर साहब, अभी ये कह रहे थे कि हमारा खाना पीना बन्द हो गया। खाना पीना तो ऐन्टी डिफैक्टान बिल आने से इनका बन्द हो गया। ( गोर)

**लोक निर्माण मंत्री (श्री अमर सिंह):** स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं हीरा नन्द जी आर्य और प्रो० सम्पत सिंह तथा श्री वीरेन्द्र सिंह को कहना चाहूंगा कि—

आता है याद मुझ को गुजरा हुआ जमाना,  
वह न गाए हकूमत वह मेरा दनदनाना,  
छोटी सी एक झंडी को कार पर सजा कर,  
दूर पर किस भान से होता था रवाना। (हंसी)

**श्री जगदीश नेहरा:** मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। स्पीकर साहब, एसवाईएल के बारे में जो विरोधी भाईयों ने बात कही है उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब 1977 में इनकी सरकार थी तो एसवाईएल प्रोजेक्ट के बारे में एक सवाल श्री सुरजेवाला जी ने पूछा था उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूँ—

‘Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the time by which the Sutlej Yamuna Link Canal Project is likely to be completed together with the total quantity of water which will be received through it. Whether there is any proposal under consideration of the Government to revise and reduce the share of Haryana water as was determined previously by the Central Government; and

(b) whether it is a fact that about 1000 cusecs of water can be received through the existing canal system from

the Sutlej Yamuna Link Project; if so, the reasons for non-utilization of this water going as waste?

**Irrigation and Power Minister (Shri Virender Singh):**

(a) Sutlej Yamuna Link in Haryana territory is likely to be completed by the end of 1978-79. Likely date of completion of work on Sutlej Yamuna Link in Punjab cannot be indicated at this stage. Haryana's full share of 3.5 m.a.f. will be transported through the Sutlej Yamuna Link on its completion. There is no proposal under consideration of the Government to revise and reduce the share of Haryana water as determined previously by the Central Government.

(b) There is some spare capacity in the existing canal system available at times when requirement is not taken. It is, however, either not available or negligible in sowing and maturing periods i.e. in the month of May, June, October and November. The available spare capacity in other months is being partially utilized to carry part of Haryana's share in the surplus Ravi Beas waters.

लेकिन अब ये कह रहे थे कि हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। इसके साथ साथ जब इसी बारे में सप्लीमेंटरी हुआ तो उसके जवाब में इरीगे एंड पावर मिनिस्टर श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने यह कहा कि फार दि टाईम बीइंग इस बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार के दरम्यान बात हुई है। मार्च या अप्रैल के महीने में जब भी मुख्यमंत्री को फुरस्त होगी इस नहर

का उदघाटन कर दिया जायेगा। तो इनकी पहली स्टेटमेंट और अब की बात बिल्कुल कन्ट्राडिक्टरी है। ( गोर)

**श्री मंगल सैन:** एजूके इन स्टेट मिनिस्टर प्वायंट आफ आर्डर पर खडे होकर आप को कुछ पढकर सुना रहे थे। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 1979 में भजन लाल जी ही चीफ मिनिस्टर थे। ( गोर)

**श्री हीरा नन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। नेहरा जी ने जो पढ कर सुनाया उसके विशय में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे टाईम में यह काम इसलिये नहीं हो पाया था कि भजन लाल जी सारी फौज को लेकर इनकी तरफ ले गए थे। (हंसी)

**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले पर कुछ आगे कहने से पहले यह कहना चाहूंगा कि मेरे साथियों ने कुछ बातें मेरे उपर कही थी कि आप भी हमारे साथ है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि साथ तो अब भी हम सारे हैं लेकिन मैं यह बात जरूर कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस बारे में कई बार कह चुके है। यह मामला बहुत पुराना पड गया है। मेरा तो इस सदन में बैठने का पहला मौका है और मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कई बार कह दिया है ..... जहां तक दल बदलने की बात है उसके बारे में तो इससे आगे जवाब देने की कोई गुजांइ नही है। मैं अपने साथियों को याद



दिलाना चाहता हूँ कि जिस वक्त 1977 में जनता पार्टी पावर में आई तो उस समय जनता पार्टी का रूल तकरीबन सारे दे 1 में था, जहां तक की सैंटर में भी जनता पार्टी का ही भासन था। उसके बाद दो साल के बाद इतना जबरदस्त दल बदल हुआ जो चौधरी साहब की रहनुमाई में हुआ। मैं समझता हूँ कि इतना बडा दल बदल भायद ही हिन्दुस्तान की हिस्टरी में कभी हुआ हो इसके बावजूद भी ये ऐसी बात करें तो वह मेरी समझ से बाहर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप लोगों ने मुझे चुनाव में मदद दी थी लेकिन जहां से मैं चुनाव लडा था वहां कि जनता ने एक महीने तक मेरे पर दवाब डाला। इसलिये मैंने समझा कि जो जन हित में है वह ठीक है। ( गोर)

**वन तथा जेल मंत्री (श्री गोवर्धन दास चौहान):** स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आनरेबल मैम्बरज एक नये मैम्बर है और वे अच्छी बातें कह रहे हैं। उधर के भाइयों को इनकी इस तरह से टोका टाकी नहीं करनी चाहिए यह अच्छी रिवायत नही है। ( गोर)

**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह:** स्पीकर साहब, मैं चाहता हूँ कि इस चीज का फैसला हमे 11 के लिए हो जाए ताकि ये इस बात को बार बार न दोहराएं। इस सरकार से पहले जनता पार्टी की सरकार थी उसने दल बदल का कानून नहीं बनाया लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा करना ठीक समझा और उन्होंने ऐसा कानून पास करवाया ताकि यह बात बिल्कुल खत्म हो जाए। एक बात मैं

और कहना चाहता हूँ कि मैं आज ही अपना इस्तीफा लिख कर दे देता हूँ और उधर से जो भाई मेरे बारे में कह रहे हैं वे भी अस्तीफा दे दें। उसके बाद इलैक्ट्रॉन हो जाए। अगर मैं हाउस में न आ सका तो मैं वायदा करता हूँ कि मैं दोबारा सियास्त में नहीं आऊंगा।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, जब ये जीत ही नहीं सकते तो यह वायदा क्या हुआ। ये नौजवान आदमी हैं मेरे मित्र हैं ..... ये गलती न कर जाएं भजन लाल जी इनको टिकट नहीं लेने देंगे। ये भी जानते हैं कि कौन आदमी कैसा है। इनके और बहुत मित्र हैं। फिर आप नहीं आ सकेंगे। हम तो आपके भुभ चिंतक हैं। आप इस हाउस में रहो और आराम से रहो ..... ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** बिकाऊ और छाज वाली बात रिकार्ड न की जाए।

**चौधरी कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ..... (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। यह रिकार्ड पर नहीं आएगा।

**\*13.30 बजे**

अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए एडर्जन  
किया जाता है (तत्प चात सदन भुक्वार दिनांक 22-3-1985 को  
प्रातः 9.30 बजे तक के लिए \* स्थगित हुआ)